चिंतन

राजनीति में एक-दूसरे का सम्मान जरूरी

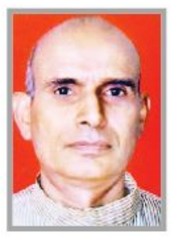

कूटनीति
अखिलेश आर्येन्दु

राजनीतिक दलों के बीच मतभेद स्वाभाविक हैं, आरोप-प्रत्यारोप भी लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा टूटने लगे तो राजनीति का स्तर गिरता है और संवाद कमजोर पड़ने लगता है। हाल ही में कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के क्रम में एक बार फिर संयम खो बैठे और सारी मर्यादा भूल गए। उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को "गद्दार" तक कह दिया। राहुल जिस तरह से तू-तड़ाक की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वह किसी भी प्रकार से नेता विपक्ष की गरिमा के खिलाफ है। यह लोकतंत्र में संबोधन का सभ्य तरीका नहीं हो सकता। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब राहुल ने असभ्य भाषा का प्रयोग किया हो। वे पहले भी ऐसा कर चुके हैं। उन्हें कई बार तो पीएम पर टिप्पणी के लिए कोर्ट तक में माफी मांगनी पड़ी थी। इसके बावजूद उनकी बयानबाजी में संयम का अभाव लगातार दिखाई देता है। संभव है कि उन्हें लगता हो कि तीखे हमले और आक्रामक भाषा से सरकार विरोधी वर्ग उनके करीब आएगा, लेकिन 10-12 साल के राजनीतिक अनुभव बताते हैं कि जनता केवल आक्रोश नहीं, बल्कि गंभीरता और विश्वसनीयता भी देखती है। लोग अब केवल नारेबाजी से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वह नेतृत्व की परिपक्वता और व्यवहार को भी महत्व देते हैं। राहुल गांधी ने आर्थिक संकट, बेरोजगारी और व्यापारिक चुनौतियों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और विपक्ष को सरकार की नीतियों पर सवाल पूछने चाहिए। जब आलोचना के बीच व्यक्तिगत उपहास और अपमानजनक शब्द शामिल हो जाते हैं, तब मूल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। यही कारण है कि उनके बयान के बाद चर्चा आर्थिक चुनौतियों पर नहीं, बल्कि उनकी भाषा पर केंद्रित हो गई। दूसरी ओर, भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी कम तीखी नहीं रहीं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल गांधी को "भारतीय राजनीति का राहु" कहा, जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने उन्हें "रिजेक्टेड माल" तक कह दिया। यह स्थिति बताती है कि भारतीय राजनीति में संवाद की जगह कटाक्ष और तंज ने ले ली है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि क्या यही राजनीतिक संस्कृति आने वाली पीढ़ियों को दी जानी चाहिए। ऐसे समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार का बयान एक सकारात्मक संदेश देता है। शरद पवार ने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने की भूमिका की सराहना की। यह परिपक्व राजनीति का उदाहरण है। पवार ने दशकों से विभिन्न विचारधाराओं के नेताओं पंडित जवाहर लाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ काम किया है। उनके बीच तीखे वैचारिक मतभेद होते थे, फिर भी व्यक्तिगत सम्मान बना रहता था। संसद में बहसें होती थीं, लेकिन भाषा की मर्यादा नहीं टूटती थी। आज सोशल मीडिया और तात्कालिक राजनीति के दौर में बयानबाजी अधिक उत्तेजक हो गई है। नेताओं को यह समझना होगा कि उनके शब्द केवल राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज के व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। राजनीति में एक-दूसरे का आदर खुद का सम्मान बढ़ाने वाली बात होती है। लोग भी नेताओं से अच्छे व्यवहार की आस रखते हैं। उम्मीद है कि राहुल गांधी भी अपना लहजा बेहतर करेंगे और राजनीति में एक-दूसरे का सम्मान करने की परंपरा को बनाए रखेंगे।

विदेश यात्रा : एक तीर से कई लक्ष्य साधे

ऊर्जा संकट, व्यापारिक चेन में अस्थिरता और वैश्विक ध्रुवीकरण का नया दौर शुरू हो गया है। विपक्ष मोदी की विदेश यात्रा पर जो सवाल उठा रहा था, उन सवालों का जवाब उनकी सफल यात्रा ने दे दिया है। जाहिर तौर पर उनकी यात्रा के बरक्स में देखें तो इस यात्रा से खाड़ी और यूरोपीय देशों से भारत के रिश्ते ही मजबूत नहीं हुए, बल्कि कई ऐसे समझौते भी हुए हैं जो आने वाले वक्त में देश की प्रगति और विकास के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। यात्रा की सफलता का मानक यह है कि वैश्विक ऊर्जा संकट से पार पाने में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, वह यूएई से ऊर्जा सुरक्षा को लेकर हुआ समझौता, जिसमें पेट्रोलियम और एलपीजी गैस भंडारण, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा निवेश शामिल है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पांच देशों की विदेश यात्रा पर जाने को लेकर विपक्ष कई दिनों से हंगामा कर रहा था। वह सवाल उठा रहा था कि ऐसे वक्त में जब देश में तेल, गैस, रसायनिक खाद की किल्लत और महंगाई से आम आदमी परेशान हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को पांच देशों के दौरे पर जाना जनहित को नजरअंदाज करने जैसा है, और इसे औचित्यपूर्ण नहीं माना जा सकता है? विपक्ष यह भूल गया कि जिस मकसद को लेकर प्रधानमंत्री ने खाड़ी और यूरोपीय देशों की यात्रा की, वह देश और समाजहित में थी। उसके सकारात्मक परिणाम यात्रा के बाद साफ-साफ दिखाई देने लगे हैं। जाहिर तौर पर, पांच देशों की यह यात्रा आर्थिक, सामरिक, कूटनीतिक और विश्व कूटनीति-राजनीति के लिए ही खास मायने नहीं रखती, बल्कि दुनिया की उभरती महाशक्ति के रूप में जो प्रतिष्ठा मिली है, वह इस यात्रा की अपार सफलता को दर्शाती है। उनकी यह यात्रा ऐसे दौर में हुई है, जब दुनिया में ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के असर साफ-साफ दिखाई दे रहा है। भारत में तेल, गैस, रसायनिक खाद और रोजमर्रा की वस्तुओं की महंगाई बढ़ रही है।

ऊर्जा संकट, व्यापारिक चेन में अस्थिरता और वैश्विक ध्रुवीकरण का नया दौर शुरू हो गया है। विपक्ष मोदी की विदेश यात्रा पर जो सवाल उठा रहा था, उन सवालों का जवाब उनकी सफल यात्रा ने दे दिया है। जाहिर तौर पर उनकी यात्रा के बरक्स में देखें तो इस यात्रा से खाड़ी और यूरोपीय देशों से भारत के रिश्ते ही मजबूत नहीं हुए, बल्कि कई ऐसे समझौते भी हुए हैं जो आने वाले वक्त में देश की प्रगति और विकास के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। यात्रा की सफलता का मानक यह है कि वैश्विक ऊर्जा संकट से पार पाने में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, वह यूएई से ऊर्जा सुरक्षा को लेकर हुआ समझौता, जिसमें पेट्रोलियम और एलपीजी गैस भंडारण, समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा निवेश शामिल है। इससे भारत भविष्य में ऊर्जा संकट से निपटने में सक्षम हो सकेगा। गौरतलब है पेट्रोलियम और गैस की बढ़ती कीमतों से महंगाई पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि तेल, गैस और रसायनिक खादों की किल्लत पर काबू पाया जाए। यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान वहां बसे भारतवंशियों ने ही मोदी का भारतीय परंपराओं से स्वागत नहीं किया बल्कि पांचों देशों में वहां की सरकारों ने पलक-पांवड़े बिछाकर स्वागत किया। यह समझा जा सकता है कि मोदी की यात्रा ने यूएई को भारत से और अधिक समीपता और विश्वासनीयता बढ़ाने का कार्य किया। यूरोपीय देशों में मोदी का भव्य स्वागत ही नहीं हुआ बल्कि स्वीडन ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी उनको सम्मानित किया। जाहिर तौर पर स्वीडन सहित यूरोपीय देशों ने यात्रा के दौरान ऐसे अनेक समझौते किए, जो भारत के लिए सामरिक, आर्थिक और तकनीक को आदान-प्रदान करने में मददगार साबित होंगे। नार्वे, स्वीडन और नीदरलैंड की यात्रा इसलिए भी जरूरी मानी जा रही है कि इससे यूरोपीय देशों के साथ हरित ऊर्जा, जल प्रबंधन, एआई, समुद्री सहयोग और रक्षा तकनीक में सहयोग के नए द्वार खुलें हैं। इनमें उन देशों की कंपनियों द्वारा भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश बहुत बड़े पैमाने पर होने के समझौते किए गए। इससे यूरोपीय देशों के साथ तकनीक साझेदारी विकसित

होगी, जिससे इन क्षेत्रों में अधिक पूंजी निवेश होने से विकास की नई संभावनाएं विकसित होंगी। नार्वे में मोदी ने ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत-नार्डिक शिखर सम्मेलन और इंडिया-नार्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट' में भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने नार्वे, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और स्वीडन के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। इस बैठक में व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, नवाचार को बढ़ावा, स्वच्छ और हरित प्रोद्यौगिकी के अलावा यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर गहन चर्चा हुई। नार्वे समिट में प्रधानमंत्री ने कहा,- भारत-ईएफटीए समझौते से 100 बिलियन डालर के निवेश और 10 लाख रोजगार सृजित करने पर सहमति हुई। फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें डिजिटलीकरण (आई 5जी/6 जी) क्वांटम तकनीक और स्थिरता के क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर जोर दिया गया। इससे इन दोनों देशों में रिश्तों में ही गर्माहट नहीं आई बल्कि तकनीक के क्षेत्र में स्थिरता के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। भारत और चीन के रिश्ते जगजाहिर हैं। कई वस्तुओं का आयात मजबूरी में भारत को चीन से करना पड़ता है, खासकर सेमीकंडक्टर -क्षेत्र में। यूरोपीय देशों से जो समझौते हुए हैं, उनमें सेमीकंडक्टर का समझौता भी एक है जो भारत के लिए चीन पर इसकी निर्भरता को कम करने में मददगार साबित होगा। इस नजरिए से यूरोपीय देशों के साथ एआई, सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक विकास की नए मॉडल की तकनीक पर निवेश का समझौता बेहद अहम है। मोदी का यह दौरा बहु गठबंधन (मल्टी अलाइमेंट) नीति का हिस्सा है। इस गठबंधन में यूरोप देशों के साथ तकनीक सहयोग, चीन के साथ प्रभाव का संतुलन, अमेरिका के साथ साझेदारी, रूस से दोस्ती के गहन रिश्ते, अरब देशों के साथ सामरिक निकटता की नीति बनाए रखना है। यानी दुनिया के उन सभी देशों के साथ मैत्री रखना, जो भारत के साथ मित्रवत बर्ताव रखना अपनी नीति का हिस्सा समझते हैं। यानी किसी गुट का हिस्सा न होकर दुनिया के हर गुट के साथ दोस्ती बनाए रखने की नीति पर चलना।

प्रधानमंत्री की इस यात्रा ने भारत की आर्थिक समृद्धि, रोजगार सृजित करने के मद्देनजर तकनीक के आयात और रणनीतिक साख को बढ़ाने का काम किया। यूएई द्वारा भारत में 5 अरब डालर निवेश की घोषणा, उनकी यात्रा की सफलता की नई इबारत लिखने में सफल हुई है। इसमें बुनियादी ढांचा, सामान्य प्रबंधन या परिवहन व्यवस्था, बैंकिंग, बंदरगाह, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश शामिल है। इससे भारत में हर क्षेत्र में नवनिर्माण की विशाल प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। इटली की यात्रा उनके खास मकसद के तहत सम्पन्न हुई। भारत-इटली के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और व्यापार को बढ़ावा देना था।

उन्होंने वहां अपने समकक्ष जार्जिया मेलोनी के साथ विस्तार से उन सभी मृद्दों पर चर्चा की जो इटली और भारत के लिए लाभकारी हो सकते हैं। इसी तरह घरेलू राजनीति में धुंरधर खिलाड़ी माने जाने वाले मोदी इस यात्रा से जनता को यह यकीन दिलाने में सफल हुए हैं कि उनकी यात्रा तेल, गैस, खाद, तकनीक आयात, मूलभूत निर्माण को आगे बढ़ाने के साथ भारत की छवि दुनिया में खासकर खाड़ी देशों में भारत की सक्रियता रणनीतिक दबाव बनाने में सफल रही है। जाहिर तौर पर आज भारत एक जिम्मेदार और सशक्त देश के रूप में स्थापित हो चुका है। इसका श्रेय मोदी और उनकी सरकार के जनहितकारी और विश्वहितकारी कार्यों और नीतियों को दिया जाना चाहिए। यह मोदी सरकार की परिपक्व विदेश नीति को भी दर्शाता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

आतंकवाद विरोधी दिवस
योगेश कुमार गोयल

घाटी में खिल रही उम्मीदें हार रहा आतंक का अंधकार

भारत सदियों से शांति, सहअस्तित्व और आध्यात्मिक चेतना की भूमि रहा है। यहां विविधताओं में एकता केवल संविधान की अवधारणा नहीं, बल्कि जीवन पद्धति रही है। इसी भारत को लंबे समय से आतंकवाद जैसी भयावह चुनौती का सामना भी करना पड़ रहा है। आतंकवाद ने केवल देश की सीमाओं को नहीं ललकारा, बल्कि समाज की आत्मा, राष्ट्रीय एकता और मानवीय मूल्यों पर भी प्रहार किया है। यह ऐसा अभिशाप है, जिसने हजारों निर्दोष नागरिकों, सुरक्षाकर्मियों और युवाओं की जिंदगी छीन ली। भारत ने इस चुनौती का मुकाबला केवल सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक धैर्य, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय संकल्प के साथ किया है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष 21 मई को 'राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस' मनाकर देश आतंकवाद के विरुद्ध अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता है।

यह दिवस हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद केवल गोलियों और विस्फोटों का नाम नहीं बल्कि वह मानसिकता है, जो समाज में भय, विभाजन और अस्थिरता पैदा करती है। यह दिवस उन हजारों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी अवसर है, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। यह दिन नागरिकों, विशेषकर युवाओं को संदेश देता है कि हिंसा और कट्टरता का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है जबकि शिक्षा, संवाद, लोकतंत्र और विकास ही स्थायी शांति के मार्ग हैं। यदि भारत में आतंकवाद की सबसे बड़ी त्रासदी का कोई प्रतीक क्षेत्र रहा है तो वह जम्मू-कश्मीर है। कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सूफी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए विख्यात कश्मीर घाटी तीन दशकों से आतंक और अस्थिरता की विभीषिका झेलती रही है। 1990 के दशक में शुरू हुआ आतंकवाद केवल स्थानीय असंतोष का परिणाम नहीं था, बल्कि यह सीमा पार से प्रायोजित सुनियोजित षड्यंत्र था, जिसका उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करना था। दक्षिण एशिया आतंकवाद पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000 से 2024 के बीच जम्मू-कश्मीर में 22 हजार से अधिक आतंकी घटनाएं दर्ज की गई। इन घटनाओं में लगभग पांच हजार नागरिकों की मौत हुई जबकि तीन हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। इसी अवधि में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने 24 हजार से अधिक आतंकियों को मार गिराया। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच देशभर में 7217 आतंकी घटनाएं हुई थी, जबकि 2014 से 2024 के बीच यह संख्या घटकर लगभग 2242 रह गई। आतंकी घटनाओं में जनहानि में लगभग 70 प्रतिशत कमी दर्ज की गई है। नागरिकों की मौतों में 81 प्रतिशत और सुरक्षाबलों की शहादतों में लगभग 50 प्रतिशत की कमी आई है।

ये आंकड़े केवल सांख्यिकीय उपलब्धियां नहीं, बल्कि भारत की बहुआयामी आतंकवाद विरोधी नीति की सफलता का प्रमाण हैं। यह भी सच है कि खतरा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वर्ष 2025 में पहलगाम के बैसरन क्षेत्र में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला इस बात का संकेत था कि आतंकवाद की जड़ें अब भी पूरी तरह उखड़ी नहीं हैं। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। यह हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे घातक नागरिक हमलों में माना गया। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद आज भी भारत की शांति और स्थिरता को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल-बद्र जैसे संगठनों को अब भी वहां से आर्थिक, सामरिक और वैचारिक समर्थन प्राप्त होने के आरोप लगते रहे हैं। भारत की आतंकवाद विरोधी नीति (आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता) अब पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और कठोर दिखाई देती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सेना या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहां यह विश्वास मजबूत होता दिखाई देता है कि आने वाले वर्षों में कश्मीर घाटी फिर से अमन, मोहब्बत और इंसानियत की पहचान बनेगी। वह दिन दूर नहीं, जब घाटी केवल चिनार की छांव, डल झील की शांति, बर्फ से ढके पहाड़ों और सूफी संगीत की मिठास के लिए जानी जाएगी। यह तभी संभव होगा, जब आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता, सतर्कता और विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे। भारत का यह संघर्ष केवल सुरक्षा की लड़ाई नहीं बल्कि सभ्यता, मानवता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संघर्ष है और इस संघर्ष में भारत का संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई देता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

भगवान के चरणों में अर्पित करना ही ज्ञान है

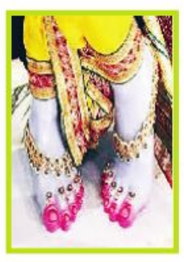

संकलित
दर्शन

सर्व सामर्थ्य होते हुए भी अहंशून्य होकर स्वयं को भगवान के चरणों अर्पित कर देना ही ज्ञान, भक्ति और कर्म की परिपूर्णता है। भगवान के परम भक्त बालिपुत्र अंगद ने रावण की सभा में अपना एक पैर रोपकर अपने मुष्टिप्रहार से रावण के दसों मुकुटों को सिर से गिरा दिया था, वहीं चार मुकुटों को बीच में उछालकर भगवान के पास भेज दिया था। लंका से लौटकर आए अंगद से जब भगवान श्रीराम ने पूछा कि तुमने ये मुकुट कहां और कैसे प्राप्त किए, तब अंगद ने धर्म और ईश्वर से विमुख व्यक्ति की तात्विक व्याख्या की है। अंगद विनम्र भाव से कहते हैं, प्रभु! ये चार मुकुट नहीं, राजनीति के चार पद हैं, जिन पर चलकर व्यक्ति व्यवहार करते हुए भी परमार्थ को प्राप्त कर लेता है। रावण आपसे और धर्म से विमुख हो चुका है, इसलिए राजनीति के चारों चरणों (साम, दाम, दंड और भेद) का दुरुपयोग कर रहा था, इस कारण मुकुट के रूप में ये चारों उसको छोड़कर आपकी शरण में आ गए हैं। रावण ने शेष छह मुकुट जो सिर पर धारण कर रखे हैं, वे साधक के जीवन में रहने वाली षड्संपत्ति (शम, दम, उपरति, तितीक्षा, श्रद्धा और समाधान) हैं। चूंकि रावण उनका भी दुरुपयोग कर रहा था, इसलिए ये षड्संपत्ति न रहकर विकार बनकर रावण के सिर पर शासन कर रहे हैं, जो उसके विनाश के कारण बनेंगे। मेरे प्रभु! गुण तो केवल वे ही हैं, जिन्हें आपने स्वीकारा है। शेष सब अवगुण ही हैं। गुणों का योग जब तक भगवान से नहीं होगा, तब तक व्यक्ति उसका उपयोग और कहां करेगा?

श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भ्रम से बचने की सलाह दी

संकलित
प्रेरणा

महाभारत युद्ध की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव पक्ष की सेनाएं आमने-सामने खड़ी थीं। संख्या और शक्ति के हिसाब से कौरवों की सेना ज्यादा अच्छी दिख रही थी। जब अर्जुन ने कौरव पक्ष में अपने परिवार, कुटुंब के लोगों को देखा तो वे भ्रमित हो गए। अर्जुन ने अपने सारथी यानी श्रीकृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहा। श्रीकृष्ण रथ लोग युद्ध मैदान के बीच में ले गए। वहां पहुंचकर अर्जुन ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे यौद्धाओं को देखा। इन सभी को देखकर अर्जुन ने युद्ध करने का विचार ही छोड़ दिया और अपने धनुष-बाण नीचे रख दिए। अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा कि मेरे कुटुंब के सभी लोग मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता।श्रीकृष्ण समझ गए कि अर्जुन भ्रम में फंस गए हैं। उस समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवान ने समझाया कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो सभी बातें चल सकती हैं, लेकिन भ्रम नहीं चल सकता है। तुम्हें अपने सारे भ्रम छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने काम अधूरे मन और भ्रम के साथ करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है। सफलता चाहते हैं तो सभी भ्रम दूर करते हुए, अपने काम पूरे मन से और एकाग्रता के साथ करना चाहिए।

अंतर्मन

आज की पाती

बहुत जरूरी है वन संपदा को आग से बचाना

हर वर्ष गर्मियों में देश के कुछ वन संपदा के धनी राज्यों में वनों में भयंकर आग लगने की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने को मिलती हैं। आग किसी भी कारण से वनों में लगती है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग गर्मियों के दिनों में बेकार की घास-फूस को जलाने के लिए वनों या खेतों में आग लगा देते हैं, जिससे घास-फूस के साथ ही सैकड़ों वृक्ष भी आग की बलि चढ़ जाते हैं जो कि प्रकृति से खिलवाड़ है और हरी-भरी वादियों के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। लोगों को चाहिए कि अगर वो खेतों से फालतू की घास-फूस को जलाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि यह आग खेतों के साथ लगते वनों में न फैले। इससे एक तो वन संपदा नष्ट होती है, दूसरे कई जंगली जीव-जंतु-पक्षी जल कर नष्ट हो जाते हैं। - संकेत अग्रवाल, सरायपाली

ट्रेंड

प्रेरणादायक पहल

विद्यार्थियों द्वारा योगासन से दिन की शुरुआत करना एक अत्यंत प्रेरणादायक पहल है। यदि बचपन से ही स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है।
-अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला विकास मंत्री

राहुल गांधी की हताशा

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग राहुल गांधी की अत्यधिक हताशा का स्पष्ट संकेत है। घृणा फैलाना कांग्रेस की सच्ची राजनीति रही है। वे नेता और पार्टियां जो स्वयं आपातकाल के दाग और भ्रष्टाचार के इतिहास से घिरी हुई हैं, आज देशभक्ति का उपदेश दे रही हैं।
- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

उर्वरकों की कमी

आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की संभावित कमी है। भारत अपने अधिकांश उर्वरकों का आयात करता है, जो वर्तमान में बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
- अशोक गहलोत, पूर्व सीएम, राजस्थान

पार्टी का शानदार प्रदर्शन

पंजाब के हर कोने में हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहेगा।
-अरविंद केजरीवाल, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

करंट अफेयर

ईरान परमाणु हथियारों की होड़ शुरू कर सकता है: वेंस

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने कहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होने से विश्व स्तर पर ' 'परमाणु हथियारों की होड़'' शुरू हो जाएगी। वेंस ने साथ ही कहा कि अगर तेहरान शांति समझौते पर पहुंचने में विफल रहता है तो अमेरिका सैन्य अभियान फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंगलवार को व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में वेंस ने यह टिप्पणी तब की जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले फिर से शुरू करने के फैसले को एक दिन पहले टाल दिया था। यह फैसला कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य अरब देशों के अनुरोध पर लिया गया। उन देशों ने कहा था कि शांति वार्ता में तेहरान 'उचित रवैया' अपना रहा है।

उपराष्ट्रपति ने कहा, 'हमारा मानना है कि ईरानी समझौता करना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमसे सद्भावनापूर्वक बातचीत करने का आग्रह किया और हमने ठीक वैसा ही किया है।' वेंस ने बताया कि प्रेस वार्ता में आने से पहले उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा, हम उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हैं और इसमें सक्षम हैं। वेंस ने कहा कि अमेरिका के पास एक सरल प्रस्ताव है और आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं।

ऑफ बीट

ब्रह्माण्ड स्वयं को क्यों खंडित कर रहा है?

ब्रह्मांड किससे बना है? यह प्रश्न सैकड़ों वर्षों से खगोलविदों को उद्वेलित करता रहा है। पिछली एक चौथाई सदी से, वैज्ञानिकों का मानना है कि

परमाणु और अणु जैसी 'सामान्य' चीजें जो आपको, मुझे, पृथ्वी और लगभग हर चीज को बनाती हैं जिसे हम देख सकते हैं, ब्रह्मांड का केवल 5 प्रतिशत हिस्सा है। अन्य 25 प्रतिशत 'डार्क मैटर' है, एक अज्ञात पदार्थ जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम यह पता लगा सकते हैं कि यह गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से सामान्य पदार्थ को कैसे प्रभावित करता है। ब्रह्मांड का शेष 70 प्रतिशत भाग 'डार्क एनर्जी' से बना है। 1998 में खोजा गया, यह ऊर्जा का एक अज्ञात रूप है जिसके बारे में माना जाता है कि यह ब्रह्मांड का लगातार बढ़ती दर से विस्तार कर रहा है। एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में जल्द ही प्रकाशित होने वाले एक नए अध्ययन में, हमने डार्क एनर्जी के गुणों को पहले से कहीं अधिक विस्तार से मापा है। हमारे नतीजे दिखाते हैं कि यह एक काल्पनिक वैक्यूम ऊर्जा हो सकती है जिसके बारे में सबसे पहले आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया था - या यह कुछ अजीब और अधिक जटिल हो सकता है जो समय के साथ बदलता रहता है। एक सदी पहले जब आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत विकसित किया।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

कंपन्या भारतीय, नफा अमेरिकेला

''**अर्था'चा अमृतयोग!**' हे संपादकीय (२० मे) वाचले. सर्व काही कायदेशीर होते तर मग ३,६५० कोटी रुपये मोजून तडजोड का करावी लागली? 'व्यवहार दुबईत झाला, इराणशी संबंध माहिती नव्हते,' हा युक्तिवाद आणि दुसरीकडे गपचूप एवढा प्रचंड दंड भरणे यातली विसंगती सहज दिसते. सामान्य माणसाने बँकेचे हप्ते थकवले किंवा थोडासा कर भरणे टाळले, तर यंत्रणा त्याचे जगणे कठीण करतात; मात्र बड्या उद्योगपतींना परदेशी न्यायालयांमध्ये हजारो कोटी मोजून कायदेशीर अभय मिळवण्याचा 'अमृतयोग' साधता येतो, हे विदारक आहे. ट्रम्प यांचे वकील टॉड ब्लान्च यांनीच अदानींचे वकीलपत्र घेतले, यावरून हा खेळ किती उच्च स्तरावर खेळला गेला हे स्पष्ट होते. लोकशाहीचा आव आणणारी अमेरिका पैशांच्या बळावर गुन्हे कसे 'मिटवून' घेते, हे या प्रकरणाने दाखवून दिले.

भारतीय कंपन्या भारतातून अफाट नफा कमावतात, पण तो पैसा मायदेशाच्या विकासासाठी गुंतवण्याऐवजी, अमेरिकेसारख्या देशात का वळवला जातो? अमेरिकेकडून अपमानकारक वागणूक मिळूनही, केवळ डॉलरच्या मोहापायी आणि तिथल्या बाजारपेठेच्या अपरिहार्यतेमुळे भारतीय भांडवल तिकडेच पळत आहे. ट्रम्प यांची मर्जी राखण्यातच हे उद्योगपती धन्यता मानतात. उद्योगपतींसाठी आणि संबंधित व्यवस्थेसाठी हा 'अर्थाचा अमृतयोग' असेलही, पण प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या आणि प्रगतीची वाट पाहणाऱ्या सामान्य भारतीय नागरिकासाठी मात्र हे अत्यंत निराशाजनक चित्र आहे.

■ **प्रवीण डोईबळे,** अंबरनाथ (ठाणे)

'अमृतकाळ' केवळ अदानींसाठीच!

''**अर्था'चा अमृतयोग!**' हे संपादकीय (२० मे) वाचले. भारतातील अदानींची अल्पावधीतील प्रगती पाहता फक्त आणि फक्त तेच 'अमृतकाळ' अनुभवत आहेत असे दिसते. अमेरिका मात्र अदानींना वेसण घालून आपल्याला हवे ते पदरात पाडून घेत आहे. एकीकडे आरोप झाले की ते नाकारायचे आणि मागच्या दाराने 'सेटलमेंट'साठी प्रयत्न करायचे हा दुटप्पीपणाच अदानी समूहाचा पाया आहे. अमेरिकी सरकारने रिलायन्सवरही इराणकडून तेल मागवले म्हणून त्या समूहाशीही 'डील' करून त्यांना अमेरिकेत रिफायनरीसाठी मोठी गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. अदानीही त्याच वाटेवर आहेत. अमेरिकेने कितीही अपमान केला तरी त्यांच्याच पायाशी लोळण घेतली जाते आहे कारण रुपयाची 'शंभरी' भरत आली आहे. पाच ट्रिलियन डॉलरचा फुगाही फुटला आहे.

■ **प्रा. डॉ. गिरीश नाईक,** कोल्हापूर

उडवाउडवीची, असंबद्ध उत्तरे

'**नॉर्वेच्या पत्रकारास** अधिकारी सामोरे' ही बातमी (लोकसत्ता- २० मे) वाचली. भारतीय पंतप्रधानांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी परदेशात पत्रकारांना उत्तरे द्यावीत की नाही, कशी द्यावीत, वगैरे बाबी या वर्तमान सरकारच्या विदेश नीतीवर आणि नीतिमत्तेवर सोडून दिल्या तरी या बातमीवर अनेक प्रश्न उद्भवतात.

पीटीआयच्या या वृत्तानुसार भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी चोख आणि सविस्तर उत्तर दिल्याचे म्हटले आहे; परंतु त्यांनी दिलेली उत्तरे ही चोख नसून उडवाउडवीची आणि असंबद्ध आहेत, असे दिसून येते. अल्पसंख्याकांवरील, अनुसूचित जाती-जमातींवरील अमानवी अन्याय, मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्या लोकांना अर्बन नक्षल ठरवून नाहक तुरुंगात डांबणे या पार्श्वभूमीवर मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत पत्रकाराने प्रश्न विचारला होता. त्यास उत्तर देताना भारताच्या सभ्यतेचे आणि संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे गुणगान परराष्ट्र सचिव करत बसले. देशात संविधान मोडीत काढण्याचे प्रयत्न करत असताना देशाबाहेर मात्र त्या संविधानाचा ढालीसारखा उपयोग करून ज्वलंत प्रश्नांना टोलवण्याची वेळ या सरकारवर येते, हा काव्यात्मक न्याय आहे.

परराष्ट्र सचिव म्हणतात, शतकानुशतके आमच्या येथे लोकशाही आहे. हे विधान तर धादांत खोटे आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा ब्रिटिशांच्या अमलाखालील या भूभागावर ५६२ संस्थाने/ राजेशाही होत्या. मुघल काळात लोकशाही नव्हती. त्याआधीही शतकानुशतके इथे विविध राजे राज्य करीत होते. मग लोकशाही नक्की कुठे आणि कधी होती? देशातील लोकांना खोटे-नाटे ऐकण्याची सवय झाली असली तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आजच्या माहितीच्या युगात एवढे रेटून खोटे बोलणे हे देशाला कमीपणा आणणारे आहे. भारत हा एक उत्तम सभ्यता असलेला देश आहे, असे सांगताना कोट्यवधी लोकांवर शतकानुशतके लादलेली अस्पृश्यता, शूद्रता आणि त्यांच्यावर आजतागायत केले जात असलेले अमानवी अत्याचार ही त्यांच्या मते उत्तम सभ्यता आहे काय? एकंदरीत या परदेश सचिवांच्या उत्तरांनी वर्तमान सरकारची आणि पर्यायाने देशाची मान खाली गेली आहे.

■ **उत्तम जोगदंड**, कल्याण

उत्तरदायित्वाचे भान देणारी टीका हवी

'**नॉर्वेच्या पत्रकारास** अधिकारी सामोरे' हे वृत्त वाचले. या घटनेमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न पुढे येतो 'लोकशाहीत पत्रकार प्रश्न विचारणार नाहीत, तर मग कोण विचारणार?' जगातील विकसित देशांमध्ये पत्रकार परिषद ही केवळ औपचारिकता नसते, तर ते सत्ताधाऱ्यांना थेट जाब विचारण्याचे व्यासपीठ असते. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांना पत्रकार अनेकदा कठोर आणि अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारतात. फ्रान्स, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन यांसारख्या युरोपीय देशांमध्ये पत्रकार थेट प्रश्न विचारतात; कारण तिथे पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते. सरकारवर टीका झाली तरी तो देशद्रोह मानला जात नाही, तर लोकशाहीची ताकद समजली जाते.

'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स २०२५' मध्ये भारताचा क्रमांक खूप मागे आहे. नॉर्वे, एस्टोनिया, नेदरलँड्स, स्वीडन आणि डेन्मार्क हे देश माध्यम स्वातंत्र्यात अव्वल मानले जातात. या देशांमध्ये पत्रकारांवर राजकीय दबाव कमी असतो, माध्यम मालकीत पारदर्शकता असते आणि पत्रकारांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाते. भारतात मात्र पत्रकारांवर दबाव, खटले, ट्रोलिंग, जाहिरातींचे राजकारण आणि माध्यमांचे केंद्रीकरण या गोष्टींबाबत सातत्याने चिंता व्यक्त केली जाते. भारतात आजही हजारो वृत्तपत्रे, शेकडो वृत्त वाहिन्या आणि डिजिटल मंच सक्रिय आहेत, पण खरी लोकशाही केवळ माध्यम संस्थांच्या संख्येवरून ठरत नाही; तर पत्रकार किती निर्भयपणे प्रश्न विचारू शकतात, यावर ठरते.

भारतात मात्र कठोर प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांनाच अनेकदा लक्ष्य केले जाते, ही चिंतेची बाब आहे. लोकशाही मजबूत ठेवायची असेल, तर सरकार, पत्रकार आणि नागरिक या तिन्ही घटकांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. पत्रकारांनीही निष्पक्षता जपली पाहिजे आणि सरकारने टीकेला शत्रुत्व न मानता उत्तरदायित्व मानले पाहिजे.

■ **प्रवीण परदेशी,** स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी, सदाशिव पेठ (पुणे)

'आरसीसी'चे नवे घटक

***आरसीसी बांधकामाला** सिव्हिल इंजिनीअरिंगमध्ये अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. यात सिमेंट, वाळू, खडी याचे प्रमाण एकास-दोनास-चार असे असते. पाणी आणि अर्थातच स्टील आवश्यक असते.*

परंतु आता बदललेल्या परिस्थितीमध्ये याची नव्याने व्याख्या करणे आवश्यक आहे. नवीन प्रकारच्या आरसीसीमध्ये याचे प्रमाण एकास-विसास-चाळीस ठेवावे. यातला पहिला भाग म्हणजे लवकरात लवकर श्रीमंत होण्याची इच्छा. दुसरा भाग लबाडी आणि तिसरा भाग काळ्या पैशाची उपलब्धता हे तीन घटक महत्त्वाचे आहेत. यांचे योग्य मिश्रण होण्यासाठी राजकीय जवळिकीचे पाणी योग्य प्रमाणात घालावे. यानंतर महत्त्वाचा घटक म्हणजे अर्थातच स्टील! नीतिमत्तेचा अभाव असणारे अत्यंत तकलादू व्यक्तिमत्त्व हे स्टील म्हणून वापरता येईल.

अशा रीतीने तयार होणारे बांधकाम घट्ट होण्यासाठी वर उल्लेख केलेले पाणी वारंवार वापरावे लागेल. अशा प्रकारे तयार झालेले नवे आरसीसी बांधकाम हे इतके मजबूत असेल की ते फक्त ईडी किंवा सीबीआय यांच्या टेस्टमध्येच उद्ध्वस्त होऊ शकेल. तसे झाले तर मात्र या ढिगाऱ्याखाली काही लाख निरपराध मुलांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो.

■ ***व्यं. ग. चित्रे,*** डोंबिवली

चित्रपट महोत्सवांचे लोकशाहीकरण कधी?

भारतीय चित्रपट महोत्सवांना खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक व्हायचे असेल, तर त्यांना जागतिक आणि स्वतंत्र प्रयोगांतून शिकावे लागेल. प्रस्थापित महोत्सवांनी केवळ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व न देता दलित, बहुजन आणि आदिवासी पार्श्वभूमीच्या निर्मात्यांशी, तंत्रज्ञांशी आणि कलाकारांशी व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत...

हरीश स. वानखेडे
'जेएनयू'तील सहयोगी प्राध्यापक
enarish@gmail.com

सिनेकारण

चित्रपट महोत्सव आणि पुरस्कार सोहळे म्हणजे केवळ चकाकणारे रेड कार्पेट किंवा नटांची मांदियाळी नसते. मुळात या संस्था समाजातील उत्कृष्ट कलाकृती आणि प्रतिभावान कलाकार कोण, हे ठरवणाऱ्या महत्त्वाच्या द्वारपाल असतात. जागतिक स्तरावर आपण ऑस्करकडे (अकॅडमी अवॉर्ड्स) सिनेमातील गुणवत्तेचा मापदंड म्हणून पाहतो, कारण या पुरस्कारांनी चित्रपटाला एक जबाबदार कलाप्रकार म्हणून प्रतिष्ठा मिळवून दिली. भारतातही राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांनी अशा कलाकारांचा गौरव करण्याची परंपरा जपली आहे, ज्यांनी वास्तववादी सिनेमा आणि उत्कृष्ट अभिनयाद्वारे भारतीय कलेचा दर्जा उंचावला.

परंतु, गेल्या काही वर्षांत या प्रस्थापित संस्थांवर कडक टीका होत आहे. हे महोत्सव 'एलिट' (अतिउच्चभ्रू) आणि 'एक्सक्लुसिव्ह' (काही ठरावीक लोकांपुरते मर्यादित) असल्याचे आरोप होत आहेत. जेव्हा हे महोत्सव उपेक्षित सामाजिक गटांचे सर्जनशील योगदान नाकारतात, तेव्हा ते खऱ्या सामाजिक वास्तवाचे दर्शन घडवण्याऐवजी केवळ समाजातील प्रभावशाली वर्गाचेच प्रतिबिंब मांडण्याचे काम करतात.

जागतिक स्तरावरील परिवर्तनाची लाट

'हॅशटॅगऑस्कर्ससोव्हाइट' ही २०१५मध्ये सुरू झालेली मोहीम जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचे वळण ठरली. या मोहिमेने हे उघड केले की ऑस्करवर ऐतिहासिक काळापासून केवळ गोऱ्या पुरुषांचेच वर्चस्व राहिले आहे. यातून हॉलीवूडमध्ये वांशिक, सामाजिक विविधतेला स्थान देण्याची क्रांती सुरू झाली. भारतात अशा प्रकारची व्यापक जाणीवजागृती अद्यापही दिसत नाही. प्रबळ दलित चळवळी आहेत व सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेतही सामाजिक समावेशकतेच्या गप्पा मारल्या जातात, तरीही चित्रपट महोत्सवांचे वर्तुळ आजही पारंपरिक विशेषाधिकारांच्या चौकटीतच वावरताना दिसते. यात दलित, बहुजन आणि आदिवासी समाजातील कथा, त्यांची जगण्याची शैली आणि त्यांच्या चित्रपट निर्मितीतील कौशल्याकडे वारंवार दुर्लक्ष केले जाते.

सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी माध्यम

चित्रपट महोत्सवांमध्ये सर्वांना स्थान मिळणे का महत्त्वाचे आहे, हे समजून घेण्यासाठी प्रथम सिनेमाचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. सिनेमा हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नाही, तर ते आपल्या सामूहिक कल्पनाशक्तीचे मुख्य साधन आहे. चित्रपट आपल्याला एका गुंतागुंतीच्या आणि कधी कधी क्रूर जगामध्ये स्वतःचे अस्तित्व शोधण्यासाठी एक वैचारिक आरसा उपलब्ध करून देतो. जेव्हा सिनेमा सर्वसमावेशक असतो, तेव्हा तो सामाजिक अन्याय, विषमता आणि संघर्षाचे दाहक वास्तव समोर आणतो. त्याच वेळी, संकटावर मात करण्यासाठी लागणारे धैर्य आणि जिद्द याचेही दर्शन तो घडवतो.

जेव्हा चित्रपट महोत्सव उपेक्षितांचे आवाज उंचावणाऱ्या कलाकारांकडे किंवा त्यांच्या कलेकडे दुर्लक्ष करतात, तेव्हा ते केवळ चित्रपट नाकारत नाहीत, तर त्या समाजाचा इतिहास, त्यांच्या दंतकथा आणि त्यांचा संघर्ष राष्ट्रीय स्मृतीतून पुसून टाकतात. सामाजिक वास्तवाला प्राधान्य देणाऱ्या सिनेमाचा गौरव करणे म्हणजे केवळ विविधतेचा कोटा पूर्ण करणे नव्हे, तर ती कलेच्या आत्म्याची पुनर्प्राप्ती असते. चित्रपटसृष्टीला खऱ्या अर्थाने परिवर्तनवादी व्हायचे असेल, तर राज्यसंस्था व चित्रपट क्षेत्रातील धुरिणांनी वंचित पार्श्वभूमीच्या कलाकारांशी संवाद साधला पाहिजे आणि त्यांना परिघाबाहेर न ठेवता मुख्य प्रवाहात स्थान दिले पाहिजे.

विविधतेचे जागतिक आदर्श

प्रस्थापित महोत्सवांमध्ये जेव्हा प्रतिनिधित्वाची कमतरता असते, तेव्हा पर्यायी महोत्सव कसे काम करू शकतात, याचा एक उत्तम आदर्श अमेरिकेने घालून दिला आहे. 'ऑस्कर' आणि 'गोल्डन ग्लोब'सारख्या मोठ्या सोहळ्यांशिवाय, मियामीमधील 'अमेरिकन ब्लॅक फिल्म फेस्टिव्हल' (एबीएफएफ) महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. हा महोत्सव ठामपणे सांगतो की कृष्णवर्णीय कलाकार चित्रपट उद्योगाचा अविभाज्य भाग आहेत. या उपक्रमाला मोठ्या कंपन्या आणि माध्यम क्षेत्रातील प्रभावी व्यक्तींचाही पाठिंबा मिळतो. भारतात अशा प्रकारच्या मोठ्या संस्थात्मक हस्तक्षेपाची उणीव असली तरी, काही स्वतंत्र उपक्रमांद्वारे आता बदलाचे वारे वाहू लागले आहेत. हे महोत्सव केवळ चित्रपट दाखवत नाहीत, तर ते एक पर्यायी राजकीय आणि सांस्कृतिक शब्दकोश तयार करत आहेत.

जागतिक मानवी हक्क चळवळींतून प्रेरणा घेऊन २०१९ मध्ये कोलंबिया विद्यापीठात 'दलित चित्रपट आणि सांस्कृतिक महोत्सव' (डीएएलआयएफएफ) आयोजित करण्यात आला होता. ती एक ऐतिहासिक घटना होती, ज्याने सिनेमा, जातीचा प्रश्न आणि सांस्कृतिक अभिव्यक्तीमध्ये दलितांच्या मुख्य भूमिकेवर सखोल चर्चा केली. पा. रंजित, नागराज मंजुळे आणि नीरज घेवान यांसारख्या मान्यवरांच्या उपस्थितीने भविष्यातील अशा कार्यक्रमांसाठी एक पाया रचला. यातून हे सिद्ध झाले की दलित सिनेमा ही एक स्वतंत्र सौंदर्यवादी चळवळ आहे, जी जगाकडे दलित-वंचितांच्या नजरेतून (द गेझ फ्रॉम बीलो) पाहते. हे लोण आता २०२४ पर्यंत अधिक विस्तारले आहे. 'नॉटिंगहॅम ट्रेंट युनिव्हर्सिटी'ने डिजिटल दलित चित्रपट महोत्सव आयोजित केला, तर भारतात आयआयटी दिल्लीसारख्या संस्थांनी या वर्षी 'जय भीम सप्ताहा' अंतर्गत दलित जीवनसंघर्ष आणि यशाच्या गाथा सांगणाऱ्या चित्रपटांचे स्क्रीनिंग केले. जरी हे चित्रपट महोत्सव सध्या शैक्षणिक वा मर्यादित स्तरावर असले तरी, त्यांनी मुख्य प्रवाहात अदृश्य असलेल्या कलाकारांना ओळख मिळवून देण्याची एक महत्त्वाची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

पी. के. रोझी फिल्म फेस्टिव्हल

या प्रवासातील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे पा. रंजित यांच्या 'नीलम कल्चरल सेंटर'तर्फे २०२१ पासून आयोजित केला जाणारा 'पी.के. रोझी फिल्म फेस्टिव्हल'. पी.के. रोझी या मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील पहिल्या दलित अभिनेत्री होत्या, ज्यांना त्यांच्या जातीमुळे चित्रपटसृष्टीतून हुसकावून लावले गेले होते. त्यांच्या नावाने हा महोत्सव सुरू करणे ही एक प्रतीकात्मक कृती आहे. हा महोत्सव केवळ तांत्रिक कौशल्यांपेक्षा कलात्मक जबाबदारी आणि उपेक्षितांचे जीवन मांडणाऱ्या जागतिक सिनेमांना व्यासपीठ देतो. भारतीय सिनेमातील ऐतिहासिक पूर्वग्रह दूर करण्यासाठी हा महोत्सव एक सुधारणात्मक पाऊल म्हणून काम करत आहे. इतर राज्यांनी आणि चित्रपटप्रेमींनीदेखील या महोत्सवाच्या यशातून प्रेरणा घेतली पाहिजे आणि लोकप्रिय चित्रपट संस्कृतीच्या जडणघडणीत दलित आणि आदिवासींच्या योगदानाचा गौरव करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजेत.

महोत्सवांच्या भविष्याची पुनर्रचना

जर भारतीय चित्रपट महोत्सवांना खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक व्हायचे असेल, तर त्यांना या जागतिक आणि स्वतंत्र प्रयोगांतून शिकावे लागेल. प्रस्थापित महोत्सवांनी केवळ नावापुरते प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व न देता दलित, बहुजन आणि आदिवासी पार्श्वभूमीच्या निर्मात्यांशी, तंत्रज्ञांशी आणि कलाकारांशी व्यावसायिक संबंध प्रस्थापित केले पाहिजेत. शोषित आणि उपेक्षित सामाजिक समूहातून येणाऱ्या कलाकारांकडे अनेकदा सामाजिक भांडवल, व्यावसायिक नेटवर्क आणि त्यांच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करण्यासाठी आर्थिक ताकदीचा अभाव असतो; म्हणूनच, चित्रपट क्षेत्रातील प्रस्थापित उच्चभ्रूंनी त्यांना हात धरून पुढे आणणे आणि त्यांना बाजारपेठेत समान संधी उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे.

आज अशा स्वतंत्र महोत्सवांची आणि पुरस्कार सोहळ्यांची नितांत गरज आहे, जिथे विविध सामाजिक पार्श्वभूमीचे निर्माते एकत्र येऊन एक पर्यायी सांस्कृतिक अवकाश निर्माण करू शकतील. मुख्य प्रवाहातील सांस्कृतिक वातावरण हे सामाजिक न्यायाच्या आदर्शांना जपणारे आणि उपेक्षितांच्या सांस्कृतिक मूल्यांना सन्मानाचे स्थान देणारे असावे.

शेवटी, उपेक्षित समाजांनीही सिनेमाकडे केवळ मनोरंजन म्हणून न पाहता, त्याकडे एक वैचारिक सत्ता म्हणून पाहिले पाहिजे. सिनेमाचा आपल्या मनावर असलेला पगडा समजून घेऊन, त्यात आपला वाटा मागण्याची वेळ आली आहे. चित्रपटसृष्टी ही केवळ पारंपरिक उच्चभ्रूंच्या राजकीय आणि सांस्कृतिक वर्चस्वाचे साधन राहू नये, तर ती जनतेच्या सांस्कृतिक हिताचे प्रतिनिधित्व करणारी असावी. जेव्हा आपण चित्रपट महोत्सव सर्वसमावेशक करतो, तेव्हा आपण केवळ पडद्यावरचे चेहरे बदलत नाही, तर आपण कोणाला स्वप्न पाहण्याचा अधिकार आहे, हेदेखील बदलतो.

कुतूहल

सामन्याआधी व्यायाम का करतात?

कुठल्याही स्पर्धात्मक खेळाच्या सामन्याआधी खेळाडू नेहमीच सराव करताना दिसतात. जॉगिंग, हात-पाय ताणणं, उड्या मारणं, सांध्यांच्या विविध हालचाली करणं या प्रकारचे व्यायाम केले जातात. या व्यायाम प्रकारांना 'वॉर्म अप' असं म्हटलं जातं. टेनिससारख्या खेळात सामन्याआधीचा ठरावीक वेळ अशा सरावासाठी राखून ठेवलेला असतो. या वेळेत खेळाडू टेनिसमधील शॉट पूर्ण ताकदीने न खेळता हळूहळू खेळताना आपण टीव्हीवर पाहिलं असेलच. आपल्याला सामना कधी सुरू होतो याची उत्कंठा असते पण खेळाडू मात्र कोर्टवर लगेच खेळायला सुरुवात न करता असे लुटुपुटुचे फटके खेळत असतात.

'वॉर्म अप'चा शब्दशः अर्थ 'गरम करणं' असा आहे. आपण जेव्हा हालचाल करत नसतो, तेव्हा आपलं शरीर थंड असतं. जेव्हा आपण कुठलाही व्यायाम करतो, तेव्हा शरीर गरम होतं. थंड तापमानापासून गरम होण्यापर्यंतच्या काळात, शरीराला या बदलाशी जुळवून घ्यावं लागतं. व्यायामामुळे शरीर अचानक गरम होतं. असं झाल्यास त्यामुळे वेगवेगळे त्रास होऊ शकतात. ते टाळण्यासाठी प्रत्येकानेच खेळाआधी सराव करणं आवश्यक आहे.

सराव करण्यामुळे हळूहळू हृदयगती वाढते, श्वासाचा वेग वाढतो. यामुळे हृदयावर अचानक येणारा ताण टाळता येतो. रक्तवाहिन्या मोकळ्या होतात. शरीरात आणि मुख्यतः स्नायूंमध्ये रक्ताभिसरण सुधारतं. फुप्फुसांतून ऑक्सिजन रक्तावाटे स्नायूंपर्यंत पोचतो. तसंच रक्तातून शर्कराही स्नायूंना उपलब्ध होते. खेळताना होणाऱ्या श्रमांसाठी स्नायूंमध्ये जास्त प्रमाणात ऊर्जानिर्मिती आवश्यक असते. ती या साखरेतून मिळते. रक्ताभिसरणामुळे कार्बन डायॉक्साईड आणि लॅक्टिक आम्लासारखे टाकाऊ पदार्थ स्नायूंमधून लवकर बाहेर पडण्यास मदत होते. स्नायूंमध्ये येणारा थकवा टाळता येतो. स्नायूंचं तापमान वाढतं. गरम झालेले स्नायू जास्त वेगाने आकुंचन पावतात आणि शिथिलही होतात. यामुळे खेळासाठी आवश्यक लवचीकता येते. स्नायू आखडण्याची शक्यता कमी होते. यातून खेळताना अपेक्षित वेग, ताकद आणि चपळाई येते. स्नायू व सांध्यांना दुखापत होणंही टाळता येतं. खेळाआधीच्या सरावामुळे स्नायूंची कार्यक्षमता जास्त काळ टिकवता येते.

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे खेळाआधी व्यायाम केल्यामुळे खेळाडूची एकाग्रता वाढते. व्यायामामुळे त्याचं खेळाकडे लक्ष केंद्रित होतं. त्याच्यावरचं दडपण कमी होतं आणि त्याला खेळात अपेक्षित असलेल्या स्पर्धेला तोंड देण्याचा आत्मविश्वास मिळतो. अशा प्रकारे वॉर्म अपमुळे शरीर आणि मन यांच्यात समन्वय साधला जाऊ शकतो. तेव्हा आपल्याला जर कोणत्याही खेळात खेळाडूंची सर्वोत्तम कामगिरी बघायची असेल तर आपली सामना सुरू होण्याची उत्कंठा थोडी ताणून धरावी आणि खेळाडूंना त्यांचा सराव पूर्ण करू द्यावा!

– डॉ. राजेश पुसाळकर
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

पाकिस्तानची खेळी

***सकाळी समाजमाध्यमांवरची** ती बातमी वाचल्यापासून तात्या कमालीचे अस्वस्थ होते. मन रमावे म्हणून त्यांनी टीव्ही सुरू केला. इंधनटंचाईच्या बातम्या बघून त्यांना आणखी अस्वस्थ वाटू लागले. या देशातल्या लोकांना दीर्घकालीन संकटाचा विचारच करता येत नाही, असे उद्वेगाने म्हणत त्यांनी तो बंद केला. मग त्यांचे मन पुन्हा त्याच बातमीवर स्थिरावले. म्हटले तर टिकलीएवढा हा शेजारचा पाकिस्तान. तिथल्या चौक व रस्त्यांना हिंदू नावे देऊन भारताला आव्हान देतो. तेही अप्रत्यक्षपणे. कुठलीही प्रतिक्रिया न देता. तरीही 'राष्ट्र प्रथम' अशी शपथ घेणाऱ्या भारतीयांचे रक्त खवळत नाही. कुणी त्यावर साधी प्रतिक्रियाही देत नाही. यामागचा संभाव्य धोका यांच्या लक्षात कसा येत नाही या प्रश्नांनी तात्यांच्या मनात काहूर माजवलेले.*

तेवढ्यात काकूंनी नाश्ता आणला पण तो खाण्याची इच्छाच त्यांना होईना! २०१४ ला सत्तेचे स्वप्न साकार झाल्यावर गुलामीची मानसिकता दर्शवणाऱ्या मुस्लीम शासकांची प्रत्येक खूण पुसण्यासाठी घेतलेला पुढाकार त्यांना आठवला. वय झाल्याने भलेही आपण सक्रिय सहभाग नोंदवू शकलो नाही पण कोणत्या रस्त्याला, शहराला, चौकाला कुठले नाव द्यायचे हे अगदी वरिष्ठांपर्यंत सुचवले. सांगितलेली पर्यायी नावे काही ठिकाणी दिलीही गेलीत. त्याबद्दल परिवाराकडून कौतुकाचे पत्रही आले. आता याच्या पुढची पायरी म्हणजे अखंड भारताचे स्वप्न साकार करणे. त्यासाठी वेगवेगळ्या ग्रुपवर प्रबोधन, उद्बोधनाचे काम सुरू असताना पाकिस्तानने ही खेळी केली. त्याला जोरदार प्रत्युत्तर देण्याऐवजी सारे शांत बसलेत. अरे, उद्या त्यांनी अखंड पाकिस्तानची मागणी केली तर काय? या प्रश्नासरशी ते थबकले.

मग त्यांनी वरिष्ठांना थेट फोन लावायला सुरुवात केली. एकदोघांचे 'बघू' हे उत्तर वगळता कुणीही त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकून घेतले नाही. अमेरिका-इराण युद्धात मध्यस्थी केल्यापासून तशीही पाकिस्तानची प्रतिमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उंचावलीच आहे. या निर्णयामुळे आम्ही अल्पसंख्याक हिंदूंचे हित जपतो, असे ते जगाला आणखी ओरडून सांगतील. इंग्रजांच्या राजवटीखाली सारेच होते मग अखंड भारतच का पाकिस्तान का नाही असा युक्तिवाद त्यांनी केला तर काय? त्यांचा हा दावा किती तकलादू आहे. मूळ देश भारतच कसा होता, इतिहासात तसे दाखले कसे नोंदवले गेले आहेत, भारतातून फुटून निघालेल्या भागाला अखंड म्हणण्याचा अधिकारच कसा नाही याची उत्तरे आतापासूनच तयार करायला हवी. मात्र कुणी मनावर घ्यायलाच तयार नाही.

विचार करता करता तात्यांची तगमग आणखी वाढली. दुपारी कसेबसे दोन घास पोटात ढकलल्यावर ते घरासमोर शतपावली करू लागले. तेवढ्यात शेजारचे पुरोगामी नाना बाहेर आले व पाकिस्तानमधील नामकरणाची बातमी वाचली की नाही असे छद्मीपणे म्हणत तात्यांच्या जखमेवर मीठ चोळून गेले. तात्यांनी लगेच घरात येत दार घट्ट बंद करून घेतले. पाकिस्तानचा एकदाच सोक्षमोक्ष लावूनच टाकायला हवा. 'ना रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी'. त्यांची ही अस्वस्थता बघून शेवटी काकूंना राहावले नाही. काय झाले म्हणून त्यांनी विचारलेच. तात्यांनी सर्व घटनाक्रम सांगितला. त्यावर काकू म्हणाल्या. 'अहो, त्यात काय एवढे? लग्नानंतर तुम्हीही माझे नाव बदललेच की. तरीही अनेक जण मला आजही जुन्याच नावाने हाक मारतात.' हे ऐकून तात्यांना हसावे की रडावे हेच समजेना!

राजवाडे विचारविश्व

'परिचारिके'प्रमाणे कागदपत्रांची 'शुश्रूषा'

ऐतिहासिक साधनांचा पाचवा खंड राजवाड्यांनी १९०२ साली कोल्हापूरमधून प्रकाशित केला. २९८ पानी त्या खंडामध्ये खर्ड्याच्या लढाईनंतर मराठे व निजाम यांच्यात झालेल्या तहाच्या बोलण्यांसंबंधीचा वृत्तांत समाविष्ट होता, तशीच गोविंदराव कृष्ण काळे यांच्याकडून सवाई माधवराव, नाना फडणवीस यांना आलेली निवडक २४२ पत्रेही समाविष्ट होती.

ती पत्रे होती तब्बल दहा-बारा हजार पत्रांमधून निवडलेली. पंतप्रधान नारायणराव यांचे हैदराबाद येथील वकील गोविंदराव कृष्ण काळे यांनी पाठवलेली १७८६ ते १७९८ पर्यंतच्या अवधीतली ती हजारो पत्रे त्यांचे वंशज बापूसाहेब काळे यांनी आपल्या बारामती येथील दफ्तरातून काढून राजवाडे यांच्या हवाली केली होती. मूळ पत्रे पाठवणाऱ्याने पत्रांचे जावक यथोचित पद्धतीने नोंदवले होते आणि ती पत्रे सेक्शन बाइंडिंगने बांधून सुरेख, वळणदार व टपोऱ्या अक्षरांनी लिहून अतिसुरक्षित अशा आपल्या दफ्तरखान्यात ठेवण्याची खबरदारी घेतली होती.

तथापि पुढे काय काय झाले, त्याचे वर्णन करताना राजवाड्यांनी संयम पाळून लिहिले, 'गोविंदराव कृष्ण यांच्या मृत्यूनंतर ८० वर्षांपर्यंत ही जावके अंधारात लोळत पडून सुमारे दोन वर्षांपूर्वी श्रीमंत बापूसाहेब यांच्या हस्ते त्यांची झाडपूस झाली. उंदीर, घुशी, वाळवी, कोळी, पाऊस, वारा आणि आळशी व अज्ञ कारकून यांच्या तडाख्याखाली या जावकपत्रांच्या पुस्तकांच्या निव्वळ भाकऱ्या बनून गेल्या होत्या. कित्येक जावके आरपार पोखरून गेली होती व कित्येकांचा तर भुगा होऊन गेला होता... आरपार पोखरून हैराण झालेली पुस्तके थंड पाण्याच्या घड्यांच्या नाजूक उपचाराने पुन्हा थोडी बहुत बोलू लागली व पहिल्या वर्गातील भाकऱ्यांवरील चिकटा आधणाच्या वाफाऱ्याने धुऊन काढल्यावर आतील पत्रे पुन्हा ताजीतवानी झाली. अशा मोठ्या दुर्धर प्रसंगातून ही पत्रे सोडवलेली आहेत.'

हे राजवाड्यांचे तक्रारवजा निवेदन मुद्दामच इथे उद्धृत केले आहे. साधने हाती लागावीत म्हणून एखाद्या परिचारिकेसारखी त्यांनी हजारो कागदपत्रांची अगदी मनोभावे शुश्रूषा केली; कुणाच्या कपाळावर थंड पाण्याच्या घड्या ठेवून किंवा कुणाला गरम पाण्याचा वाफारा देऊन त्यांनी अगणित कागदपत्रांना 'बरे केले, आजारपणातून बाहेर काढले.' आणि एवढी सारी तपश्चर्या केल्यानंतर फळ म्हणून हाती काय लागले? तर बारामती दफ्तरातल्या त्या मूळच्या दहा-बारा हजार जावक पत्रांपैकी जेमतेम २४२ पत्रे. हजारो पत्रे धुंडाळल्यानंतर जर एवढ्या क्षुल्लक प्रमाणातच 'ऐवज' हाती लागत असेल, तर सामान्य माणूस सगळा उत्साह गमावून बसल्याशिवाय राहणार नाही. पण राजवाड्यांची हाती घेतलेल्या कामावरची निष्ठा एवढी दुर्दम्य होती की, त्यांनी आपल्या त्याच छोटेखानी प्रस्तावनेमध्ये पुढे इच्छा प्रदर्शित केली, 'सध्या तर कोठे चार खंड साधने छापून झाली आहेत, मला तर अद्यापि शंभर- दीडशे खंड छापावयाचे आहेत.'

आपली इच्छा व्यक्त करतानाच राजवाड्यांनी हेसुद्धा स्पष्ट केले की, ही कागदपत्रे प्रकाशित झाली आणि ती स्वदेशप्रीतीने प्रेरित झालेल्या काहीजणांनी वाचली म्हणजे सगळा कार्यभाग साध्य झाला, असे होणार नाही. त्या कागदपत्रांतून ज्या इतिहासाचे दर्शन घडते, तो इतिहास समजून घेणे महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी तसा वाचकवर्ग तयार हवा. त्यांनी लिहिले, 'शेवटपर्यंत तग धरणारा, स्तुतिनिंदेला न जुमानणारा, (सर्वसामान्य) लोकांच्या औदासीन्याला भीक न घालणारा, मत्सरभावनेने दूषित न होणारा असा वाचकसमूह जवळ केल्याशिवाय तरणोपाय नाही, अशी पक्की खात्री झाल्यामुळे मी या पत्रांचा सत्कार (नीट अभ्यास) करण्याची विनंती महाराष्ट्रातील इतिहासज्ञांना करीत आहे'... आणि अशा साधनांच्या छपाईखर्चाबाबत सहकार्याचे आवाहन करीत राजवाड्यांनी म्हटले, 'मराठी दफ्तरे छापण्याचा खर्च देण्यास आपल्या देशातील सार्वभौम किंवा मांडलिक सरकारे कोणी तयार होतील, असा अद्याप तरी रंग दिसत नाही, तेव्हा हे काम आपले आपणच केले पाहिजे.'

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

युद्धाने केली सुटका...

‘मेक इन इंडिया’च्या एका तपानंतरही आपली निर्यात वाढत नसेल, परिणामी रुपयाही लंगडत असेल तर त्याचे खापर केवळ लोकांच्या सोने- इंधन तेल वापरावर कसे फोडणार?

ज्याप्रमाणे भारताच्या २०१६ पासून सुरू झालेल्या अर्थघसरणीस ‘करोना’ने बहाणा दिला त्याचप्रमाणे आधीच मंदावलेल्या आपल्या अर्थव्यवस्थेची गती विद्यमान इराणयुद्ध अधिक मंद करत आहे असे म्हटल्यास ते अजिबात वावगे ठरणारे नाही. आपले आर्थिक नाकर्तेपण झाकण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी ज्याप्रमाणे कोविड साथ कामी आली त्याचप्रमाणे युद्धाच्या ‘हिजाबा’खाली आपली आर्थिक धोरणधरसोड दडवण्याचा प्रयत्न होईल. तथापि त्या प्रयत्नांवर विश्वास ठेवून विचारशून्यावस्थेत कर्दमी लोळणाऱ्या महिर्षींप्रमाणे आध्यात्मिक आनंद मिळवणाऱ्यांस वगळून अन्यांसाठी आपले ढासळते वास्तव सादर करणे हे या प्रसंगी कर्तव्य ठरते. या कर्तव्याची जाणीव पूर्वी राजयक्ष्मा-बाधिताच्या दिवसागणिकच्या रोडावण्याप्रमाणे सध्या तासातासाला संकोचणारा रुपया करून देतो. ही रुपयाची घसरण पाहावत नाही. पण ती अपरिहार्य आहे आणि या अपरिहार्यतेस सध्याचे इराण युद्ध पूर्णांशाने जबाबदार नाही. त्याआधीपासूनच वर्षापेक्षा अधिक काळ रुपयाची संततधार सुरू आहे. व्यक्ती असो वा देश, त्यांवरील काही संकटांची तीव्रता काळानुसार कमी होते. आपल्या अर्थव्यवस्थेबाबत सरकारी दृष्टिकोन हा असा होता. निवडणुकांत बाजी मारण्यासाठी नियामकांसह सर्व यंत्रणा मदत करतील, अमेरिकेशी व्यापार करार होईल आणि मग जगातील चवथ्या अर्थव्यवस्थेवर आकाशातून पावसाचा कृपाप्रसाद बरसून सर्व काही सुरळीत होईल असा विचार सरकारने केला नसेलच, असे नाही. पण ‘अगली बार...’चा नारा देऊनही ट्रम्प आडवे आले आणि इस्रायलच्या नरसंहारी नेतान्याहू यांनी मध्येच युद्धाचा घाट घातला. मग सगळेच इमले कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला. त्यामुळे ज्या वाईट गोष्टी जनतेस अजिबात सांगाव्या लागणार नाहीत, त्या सर्वांबाबत जाहीर इशारे देण्याची वेळ खुद्द पंतप्रधानांवर आली. सोने खरेदी करू नका, परदेशी जाऊ नका इत्यादी हाकाऱ्यांमागील कारण हे.

ते लक्षात घेतल्यास २०२५-२६ हे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील धोके दिसत होते हे जाणवेल. विद्यमान सत्ताधीशांनी त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले तरी परदेशी गुंतवणूकदारांनी मात्र ते वेळीच ओळखले. त्याचमुळे आपल्या भांडवली बाजारातील गुंतवणूक सोडवून घेण्याचा त्यांनी सपाटा लावला. हे निरीक्षण नाही. त्यास ठोस आकडेवारीचा पुरावा आहे. यंदाच्या ३१ मार्चला संपलेल्या आर्थिक वर्षात परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी तब्बल १.८१ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेतली. यंदाच्या पहिल्या दोन महिन्यांतच ८४ हजार २८२ कोटी रुपये आपल्या बाजारातून गेले आहेत. हा बाह्यदेशी प्रवास डॉलरच्या रूपातून झाला. म्हणजे डॉलर या देशातून काढता पाय घेतच होता. पण त्या तुलनेत नवी गुंतवणूक नाही. यंदाच्या मार्च महिन्यात संपलेल्या वर्षात ही गुंतवणूक फक्त ६३० कोटी डॉलर इतकी(च) असल्याचे सरकारी आकडेवारीच सांगते. त्या तुलनेत सात-आठ वर्षांपूर्वी ही परकीय गुंतवणूक ४४०० कोटी डॉलर्सपर्यंत गेली होती. याचा अर्थ उघड आहे. डॉलरचे देशाबाहेर जाणे वाढले. पण त्या तुलनेत येणाऱ्या डॉलर्सची संख्या चांगलीच आटली. या बहिर्गमनाचा थेट परिणाम काय?

रुपयाची घसरगुंडी हा तो परिणाम. रुपयाचे हे घसरणे राष्ट्राभिमानी राज्यकर्त्यांस आवडणार नाही, ते रागावतील या भीतीने असेल; पण ही घसरण थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आपल्या तिजोरीतील डॉलर बाजारात विकत गेली. रुपयाची इभ्रत वाचवण्यासाठी अवघ्या गेल्या चार महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेने तीन हजार कोटी डॉलर्सचा खुर्दा केला. परिणाम परकीय चलनाची गंगाजळी विक्रमी ७३,००० कोटी डॉलरवरून ६९,००० कोटी डॉलर इतकी घसरली. पण रुपया सावरला नाही तो नाहीच. उलट आणखी घसरत गेला. त्यास पहिली गती दिली ती अमेरिकेच्या ट्रम्प यांनी.

अमेरिकेबरोबरचा लटकलेला व्यापार करार, परदेशी संस्थांनी गुंतवणूक काढून घेणे, रिझर्व्ह बँकेने केवळ रुपयाचे मूल्य सावरण्यासाठी डॉलर ओतणे... हे सारे इराणवर क्षेपणास्त्रे डागली जाण्याच्या आधीपासूनचेच...

त्यांच्या आयातशुल्क वाढीचा दणका आपल्याला बसला. त्यापाठोपाठ नरसंहारी नेतान्याहूंमुळे वाहिलेल्या रक्ताच्या पाटाने रुपयांस आणखी घसरवले. वास्तविक हे ट्रम्प काय वा नरसंहारी नेतान्याहू काय, दोघेही आपल्या शासकांचे घनिष्ठ मित्र. पण त्या मैत्रीने रुपयास काही हात दिला नाही. तो बिचारा हेलपांडत राहिला. आज तर त्याने डॉलरच्या तुलनेत ९७ च्या मूल्यांगणात पाऊल टाकले. तज्ज्ञांच्या मते लवकरच तो शतकाचा विक्रम नोंदवून ऐतिहासिक टप्पा गाठेल. ‘सोने खरेदी करू नका, खनिज तेल वाचवा’ हे पंतप्रधानांचे आवाहन आले ते या पार्श्वभूमीवर. कारण दोन्हींची किंमत चुकवण्यासाठी डॉलर खर्च करावे लागतात. आणि ज्या वेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरतो त्या वेळी पिंपभर तेलासाठी आपणास अधिक डॉलर वेचावे लागतात. तीच बाब सोन्याचीही. खरे तर ती खनिज तेलापेक्षाही गंभीर. कारण खनिज तेल आपल्या गरजेच्या ९० टक्के आयात करावे लागते; तर सोने १०० टक्के. म्हणजे भारतीय आभूषणातील बांगड्या- पाटल्या- तोडे आणि इतकेच काय मंगळसूत्रेही तयार होतात ती परदेशातून विकत आणलेल्या सोन्यातून. एकेकाळी सोन्याची कौले वा सोन्याचा धूर इत्यादी इत्यादी होते/ निघत होते त्या देशात गेल्या वर्षात ५२०० कोटी डॉलरचे सोने आयात झाले. वजनात हे ७२१ टन इतके भरावे. ही सर्व खरेदी डॉलरमध्ये झाली. म्हणजे त्या वजनाखाली आपला रुपया आणखी चेपला गेला. तो यापुढेही अधिक चेपला जाईल.

यामागील साधे तर्कशास्त्र असे की ज्या ज्या वेळी नागरिकांचा- मग ते कोणत्याही देशांतील असोत- मायभूमीच्या चलनावर, मायदेशीच्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास कमी होतो वा उडतो त्या त्या वेळी त्या प्रदेशातील नागरिक आपली गुंतवणूक सोन्यात करतात. हे सत्य केवळ व्यक्तीलाच नव्हे; तर देशांनाही लागू पडते. म्हणूनच स्वित्झर्लंडसारख्या श्रीमंत देशानेही मोठ्या प्रमाणावर सोने खरेदी केले. म्हणजे जी बाब सरकार स्वतः टाळू शकत नाही, किंबहुना सरकारला स्वतःस जी गोष्ट संकट-समयी करावी लागते ती करू नका असे नागरिकांस सांगणे किती सयुक्तिक आणि प्रामाणिकपणाचे हा खरा यातील प्रश्न. ज्या काळात चलनवाढ अपरिहार्य आहे, त्यामुळे रुपयाचे मूल्य कमी होत जाणे अपरिहार्य आहे, जगणे अधिकाधिक महाग होत जाणे अपरिहार्य आहे, भांडवली बाजारातील अनिश्चितता अपरिहार्य आहे त्या काळात अशा प्रदेशातील नागरिकांस गुंजभरापासून ते काही तोळे सोन्यात आपल्या भविष्याची बेगमी करावी असे वाटणे, हेही तितकेच अपरिहार्य आहे. सबब खुद्द सरकारेच सोन्यात गुंतवणूक करत असताना आर्थिक स्थैर्याच्या शोधातील नागरिकांस सोने खरेदी करू नका असे सांगणे कितपत व्यवहार्य हा प्रश्न.

त्याचे उत्तर डॉलर कमाईसाठी सरकारने स्वतः काय काय उपाय योजले याच्या तपशिलात आहे. पण ते दिले जाणार नाही कारण तेथे दाखवण्यासारखे भरीव फारसे काही नाही. तसे ते असते तर जगातील चौथ्या (आणि आता सहाव्या) इत्यादी अर्थव्यवस्थेवर भलत्याच्याच युद्धांमुळे असे फाफलण्याची वेळ अवघ्या दोन-अडीच महिन्यांत येती ना. ‘मेक इन इंडिया’ आदी चकचकीत कार्यक्रमाच्या एका तपानंतरही आपली निर्यात वाढत नसेल आणि परिणामी रुपयाही लंगडत असेल तर त्याचे खापर लोकांच्या सोने-इंधन तेल वापरावर फोडता येणार नाही. युद्ध झाले नसते तरी कमीअधिक प्रमाणात आपणास या आर्थिक वास्तवाचे चटके बसलेच असते हे त्रिवार सत्य. काही नाही तर अमेरिकेबरोबरचा लटकलेला व्यापार करार हा मुद्दा होता. आणि अजूनही आहे. खरी कारणे सांगण्यापासून सरकारची ‘युद्धाने केली सुटका’ हे जरी खरे असले तरी ‘‘अर्था’ने छळले होते’ हे वास्तव बदलणारे नाही.

शी यांच्या सांगण्यातला गर्भितार्थ

प्रवीण साहनी
ज्येष्ठ संरक्षणतज्ज्ञ
pravin@forceindia.net

समर-विवेक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीन-भेटीत किती करार झाले किंवा व्यापार/ गुंतवणूक/ निर्बंध यांबद्दल काय काय ठरले यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न निराळाच होता. चीन ही आपल्या बरोबरीची महासत्ता आहे, हे अमेरिका मान्य करते का आणि मान्य असल्यास, चीनला बरोबरीच्या नात्याने वागवले जाते का, हा तो प्रश्न. यासारखा प्रश्न शतकातून एखाद्याच वेळी होत असलेल्या जागतिक बदलामुळे उद्भवतो, म्हणूनच तो महत्त्वाचा ठरतो.

या कळीच्या प्रश्नावर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनीच पुढाकार घेतलेला दिसला. ट्रम्प यांच्या स्वागतपर भाषणात जिनपिंग यांनी ‘ज्याला ‘थुसिडिडीझ सापळा’ म्हटले जाते, तो ओलांडून अमेरिका व चीन पुढली वाटचाल करणार की नाही?’- असा स्वान्तोत्तरी (विचारणेतूनच उत्तरही सूचित करणारा) प्रश्न जाहीरपणे विचारला आणि एक प्रकारे, भेटीचा कृती-कार्यक्रमच जाहीर केला.

‘थुसिडिडीझ सापळा’ म्हणजे काय, हे अमेरिकी नेत्यांना चांगलेच माहीत असते. थुसिडिडीझ हा भले कधीतरी इसवी पाचव्या शतकातल्या ग्रीसमध्ये होऊन गेलेला इतिहासकार असेल; पण त्याच्या लिखाणातून, ‘प्रस्थापित सत्तेची जागा जेव्हा नवोदित सत्ता घेणार असते, तेव्हा त्या दोहोंत युद्ध अटळ ठरते’ हा सिद्धान्त निघत असल्याचे प्रतिपादन हार्वर्ड विद्यापीठातले राज्यशास्त्रज्ञ ॲलिसन ग्रॅहम यांनी थेट अमेरिका-चीन संबंधांबद्दलच, २०१७ सालच्या त्यांच्या पुस्तकात केलेले आहे. अमेरिका ही आजची प्रस्थापित महासत्ता, तर चीन नवोदित महासत्ता असल्याने आता चीन अमेरिकेची जागा घेऊ पाहणार, मग त्यांच्यात संघर्ष अटळ ठरणार आणि ते संभाव्य युद्ध बहुधा तैवानच्या मुद्द्यावरूनच होणार, अशी खूणगाठच अमेरिकनांनी बांधलेली दिसते.

पण हा अमेरिकी विचार झाला. खुद्द चीनला ‘अमेरिकेची जागा घेणे’ नकोच आहे. अमेरिका असूदे, पण आम्हीही आहोत आणि दोघे एकाच जगात राहणार आहोत, हे सांगण्याकडे चीनचा कल दिसतो.

अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धानंतर महासत्ता होणे आणि शीतयुद्धाच्या काळात महासत्ता म्हणून वाढणे आणि चीनचा गेल्या तीन दशकांत झालेला उदय यांतील मूलभूत फरक अमेरिकी धोरणकर्त्यांनी आणि धोरणसल्ला/विश्लेषण संस्थांनी समजून घ्यायला हवा. तो असा की, चीन काही अमेरिकेसारखा लष्करी बळावर महासत्ता झालेला नाही. चीनचा उदय त्या देशाच्या जागतिक व्यापारामुळे झालेला आहे. चीन हा जगातला सर्वांत मोठा उत्पादक देश आहेच

अमेरिकाप्रणीत जागतिक व्यवस्था ही निर्बंध, संघर्ष, वाद, लढाया यांवरच आधारलेली असल्याने विकासाच्या संधी संकोचतात आणि अशा जागतिक व्यवस्थेत चीन सहभागी होऊ इच्छित नाही; हे स्पष्ट करून ‘ब्रिक्स’मध्ये चीनने रस घेतला, या घडामोडींना १३ वर्षे होत असताना ट्रम्प चीनला गेले आणि जिनपिंग यांनी ‘उभयपक्षी लाभा’ची भाषा केली! पण या लाभांसाठी चीनने काही पूर्वअटी ठेवल्या आहेत...

आणि त्याची पुरवठा-साखळी केवळ व्यापारापुरती नव्हे तर औद्योगिक मालाच्या उपलब्धतेतही स्वयंपूर्ण आहे. आता तर जगातल्या १९३ देशांपैकी १४५ देश चीनप्रणीत ‘बेल्ट ॲण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ या पुरवठा-साखळी पुढाकारात सहभागी झालेले आहेत. याहून अधिक म्हणजे १५७ देशांचा चीन हा महत्त्वाचा व्यापारी भागीदार आहे. ‘तुम्ही हरलात तरच आम्ही जिंकू’ असा - ज्याला इंग्रजीत ‘झीरो सम गेम’ म्हणतात तसा विचार न करता चीन हा अन्य देशांनाही क्षमतेनुसार विकासाची संधी देऊन वाढू इच्छितो, हे आतापर्यंत दिसून आलेले आहे. आम्ही अमेरिकेला महासत्ता-स्थानावरून खाली खेचू इच्छित नाही, हे चीनने यापूर्वी वारंवार सांगितलेलेही आहे. पण अमेरिकेचा त्यावर विश्वास नव्हता आणि नाही. चीनबद्दल अमेरिका आजही साशंकच आहे.

अशाने काय होते, याची उदाहरणे गतकाळात अनेक आहेत. त्यांपैकी एक, ओबामा यांनी २००९ मध्ये अमेरिकी व्यूहरचनाकार झिबिग्न्यू ब्रेझिन्स्की यांच्यामार्फत सूचकपणेच, चीनला ‘जी-टू’ (फक्त दोघांचाच गट) मध्ये येण्याचे निमंत्रण दिले. याचा अर्थ असा की, अमेरिकेने स्वतःच दुसऱ्या महायुद्धानंतर भूराजकीय हिशेबांतून आकाराला आणलेली जागतिक व्यवस्था हाताळण्यात आता चीनलाही वाटेकरी करून घेण्याचा अमेरिकेचा बेत होता. पण चीनने विनम्र नकार दिला, याचे कारण चीनच्या हजारो वर्षांच्या संस्कृतीने कल्पिलेल्या जगातील चीनचे स्थान, चिनी संस्कृती-सभ्यतेतूनच आलेल्या प्रशासनिक, संस्थात्मक आणि व्यूहात्मक संकल्पना चीनला आजही टिकवायच्या आहेत.

त्यामुळेच क्षी जिनपिंग जेव्हा पहिल्यांदाच वॉशिंग्टनला गेले तेव्हा - जून २०१३ मध्ये ओबामांपुढे त्यांनी ‘महत्त्वाच्या देशाशी संबंधांचे नवे प्रारूप’ स्वीकारण्याचा प्रस्ताव ठेवला (ही कल्पना चीनने २००९ मध्येच, अमेरिकेशी द्विपक्षीय वाटाघाटींच्या पहिल्या फेरीत मांडली होती). तो प्रस्तावही साहचर्य आणि तरीही आपापला विकास असाच होता. याचा अर्थ अमेरिकाप्रणीत जागतिक व्यवस्था ही निर्बंध, संघर्ष, वाद, लढाया यांवरच आधारलेली असल्याने विकासाच्या संधी संकोचतात आणि अशा जागतिक व्यवस्थेत चीन सहभागी होऊ इच्छित नाही असाही होतो, हे मात्र अमेरिकेला उमगण्यास बराच उशीर झाला असे दिसते.

चीनला अमेरिकाप्रणीत जागतिक व्यवस्थेऐवजी नवी व्यवस्था हवी आहे, हे खरे तर उघड होते. जिनपिंग हे अमेरिकेच्या भेटीआधी, मार्च २०१३ रशियाला गेले तेव्हाच अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्यासह त्यांनी ‘ब्रिक्स’ या संघटनेचा मोठा सहभाग नवी जागतिक व्यवस्था साकारण्यात असू शकतो, असे म्हटले होते. ‘शतकातून एखाद्याच वेळी होत असलेल्या जागतिक बदला’ची पूर्वकल्पना खरे तर याच वेळी उघडपणे आलेली होती- चीनने रशियासह ‘फक्त दोघांचाच गट’ नव्हे, तर भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या विकसनशील (‘ग्लोबल साउथ’) जगातल्या मोठ्या देशांच्याही सहकार्याचा प्रस्ताव ठेवला होता आणि या ‘ब्रिक्स’मध्ये सहभागासाठी आज तर बहुतेक सारेच विकसनशील देश उत्सुक आहेत.

ट्रम्प यांच्या चीन-भेटीपुरतेच बोलायचे तर, क्षी जिनपिंग यांनी या अमेरिकी पाहुण्यास शोंगनानहाइ संकुलातल्या शांत जागी नेऊन ३०० वर्षांपूर्वीचे झाड दाखवले. अमेरिकेचा इतिहास २५० वर्षांचा आहे आणि यंदा २५० वा वर्धापनदिनही अमेरिका साजरा करणार आहे, पण चीन आणि त्याचा इतिहास त्याहून जुना आहे हे दाखवण्याची ती क्षी यांची रीत. चीनची विचार करण्याची पद्धतही अशीच, हजारो वर्षांच्या शहाणिवेचा आज लागू पडणारा अन्वयार्थ शोधणारी आहे. शोंगनानहाइ संकुलात इतक्या आतपर्यंत आपण ट्रम्प यांच्याखेरीज फक्त एकाच जागतिक नेत्याला आणले- तो नेता म्हणजे रशियाचे पुतिन, हेदेखील क्षी जिनपिंग यांनी सांगितले. थोडक्यात, अमेरिकेप्रमाणेच चीन आणि रशिया याही आजच्या बहुध्रुवीय जगातल्या महासत्ता आहेत, हे जिनपिंग यांना सुचवायचे होते. विचित्र भाग असा की हे सूचक अर्थ जाणून त्याबद्दल काहीएक प्रतिक्रिया देण्याऐवजी ट्रम्प महोदय त्यांचीच उथळ खळखळ करत राहिले!

अशा या ट्रम्प यांच्यापुढे जिनपिंग यांनी पुढले धोरणही स्पष्ट केलेच. वास्तविक जिनपिंग यांनी ‘विधायक व्यूहात्मक स्थैर्य’ हा शब्दप्रयोग करून भागले असते; पण ट्रम्प यांच्यासमोर त्यांनी याचा सरळ खुलासाही केला- ‘आपण भागीदार असले पाहिजे, स्पर्धक नव्हे’! ट्रम्प यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’चा उल्लेख करून जिनपिंग म्हणाले की चीनची १५वी पंचवार्षिक योजना २०२६ ते २०३० या काळासाठी आहे, तिची आणि ट्रम्प यांची उद्दिष्टे एकमेकांच्या साथीने फलद्रूप होऊ शकतात. जिनपिंग हे ट्रम्प यांच्यासमोर उभयपक्षी लाभांची भाषा करत होते; पण त्यासाठी उभयपक्षी ताळमेळ हवा आणि तोही उभयपक्षी आदरावरच आधारलेला हवा, हेही सूचित करत होते. जिनपिंग यांनी ‘उभयपक्षी आदरावर आधारलेले सहकार्य’ ही एक प्रकारे पूर्वअट म्हणून ट्रम्प यांच्यापुढे ठेवली. अशा सहकार्याचा परिणाम केवळ उभयपक्षी लाभांपुरता न राहता जगातील प्रश्न सोडवण्यासाठीही होऊ शकतो, असे जिनपिंग म्हणाले- त्याचा अर्थ इराणपर्यंत न्यावा की पुढल्या काळात असे संघर्ष होऊच नयेत असा घ्यावा, हे जिनपिंग यांनी विश्लेषकांवर सोडून दिले.

इराणच्या वाटेला जाऊन अमेरिकेने स्वतःचे मोठेच लष्करी नुकसान करून घेतले असताना- नेमकी ती वेळ साधूनच- चीनचे राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकी नेत्यापुढे उभयपक्षी सहकार्याबद्दल या सुरात बोलतात आणि दोघांचाही लाभ होऊ शकतो असे म्हणतात, याला व्यूहात्मक अर्थ आहे.

तो अर्थ ट्रम्प यांना कळो न कळो; पण अमेरिकेतल्या व्यूहात्मक विचारविश्वात वावरणाऱ्यांना तरी कळायला हवा आणि खरे तर भारतीय धोरणकर्त्यांच्याही ध्यानात यायलाच हवा. चीनला महत्त्वाचे स्थान असलेल्या नव्या जागतिक व्यवस्थेच्या उभारणीला ट्रम्प यांच्या या चीनभेटीमुळेच अधिक वेग येणार आहे, हा तो अर्थ!

अन्वयार्थ

खासगी प्रवासी सेवेसाठी समान धोरण आवश्यक

प्रवासाची सार्वजनिक सुविधा अपुरी पडू लागल्याने खासगी सेवा हा पर्याय निर्माण झाला, टिकला आणि हळूहळू स्थिरावलाही. वेगवेगळ्या खासगी कंपन्या या क्षेत्रात उतरल्याने तिकीट दरांत आणि अन्य काही सुविधांत स्पर्धा निर्माण होऊन ग्राहकाला आणखी पर्याय उपलब्ध झाले. ॲपआधारित आरक्षणाने तर आणखी सोय झाली. अल्पावधीतच ही समांतर व्यवस्था प्रत्यक्ष व्यवस्थेचा भाग झाली. मात्र, राज्यातील अनेक शहरांत या खासगी बस ऐन वाहतुकीच्या काळात प्रमुख रस्त्यांवर प्रवाशांसाठी ठाण मांडून बसायला लागल्याने कोंडीत भर पडत आहे. ती सोडविण्यासाठी मुंबई महापालिकेने एक उपाय प्रस्तावित केला आहे, त्याची सध्या चर्चा असून, त्यानिमित्ताने राज्यभरातच यावर तोडगा निघाला तर हवा आहे.

माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतून आणि इतर राज्यांतून दररोज मुंबईत येणाऱ्या हजारो खासगी प्रवासी बस वाहतूक कोंडीत भर घालत असल्याने त्या आता मुंबईच्या वेशीवर - जकात नाक्यांवर थांबविल्या जाणार आहेत. या गाड्यांतून येणाऱ्या प्रवाशांना त्यांच्या इच्छितस्थळी जाण्यासाठी मेट्रो, बस आणि कॅबची सुविधा जोडून दिली जाणार आहे. जेथे या खासगी प्रवासी गाड्या थांबतील, तेथे हॉटेल, वाहनतळ, खाण्याची व्यवस्था करण्याचे मुंबई महापालिकेचे नियोजन असल्याचे आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट केले आहे. जकात नाके नऊ वर्षांपूर्वी बंद झालेले असल्याने तेथील जागा या सुविधा उभ्या करण्यासाठी वापरता येईल, अशी ही योजना. थोडक्यात, या खासगी बस आता शहरात न येता वेशीवरच प्रवाशांना सोडतील आणि तेथूनच नवे प्रवासी घेऊन ज्या ठिकाणी जायचे आहे, तेथे प्रस्थान करतील.

मुंबईकरांना जेरीस आणणाऱ्या वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठीच्या उपायांपैकी हा एक उपाय असल्याचे सांगण्यात येते. पण, यानिमित्ताने राज्यातील अन्य शहरांतही खासगी प्रवासी सेवांबाबतच्या तक्रारी, त्यांचे नियंत्रण आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी धोरण करण्याची गरज आहे, हे सांगायला हवे. पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर अशा काही प्रमुख शहरांबरोबरच इतरही अनेक शहरांत खासगी प्रवासी सेवेचे पेव फुटले आहे. या बसच्या तिकिटांचे दर जास्त असले, तरी स्लीपर कोच, आरामदायी आसने, जलद प्रवासाचे आश्वासन आदी सुविधा ग्राहकाला आकर्षित करणाऱ्या असतात. त्यामुळे तिकडे ओढाही असतो. आणि, अनेकदा आयत्या वेळच्या प्रवासासाठी किंवा कितीही आधी प्रयत्न करूनही एसटी, रेल्वेचे आरक्षण उपलब्ध झाले नाही, तर ती गरजही बनते.

खासगी प्रवासी सेवा ही अशी गरज बनली असेल, तर ती सुविहितपणे चालावी, यासाठी धोरणात्मक पावले उचलणे क्रमप्राप्त. मुंबईसारखाच कोंडी टाळण्यासाठीचा उपाय मध्यंतरी पुण्यातही सुचविला गेला. ठरवून दिलेल्या मार्गांवरच सायंकाळी ६ ते रात्री १० या वेळात खासगी प्रवासी बसने शहरात ये-जा करावी आणि शहरातील थांब्यांवर तीन मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ थांबू नये, अशा सूचना होत्या. मात्र, त्यावर अजूनही कार्यवाही झालेली नाही.

एसटी बसला असते, तसे खासगी प्रवासी बस वा गाड्यांना थांबण्यासाठी निश्चित स्थानक नसल्याने या गाड्या त्या-त्या शहरानुसार प्रवाशांना त्यातल्या त्यात सोयीच्या ठिकाणी आपला डेरा जमवतात. मात्र, बहुतेकदा या ठिकाणी वाहते रस्ते असल्याने त्यांचे तेथे थांबणे अडथळा ठरते. मुंबईतील प्रस्तावित उपायांनुसार सर्वच शहरांत खासगी बसना असे वेशीवरचे थांबे तयार झाले, तर काही प्रमाणात हा प्रश्न सुटू शकतो. या गाड्यांतून येणाऱ्या प्रवाशांना शहरात आणण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्याचा मुद्दाही स्वागतार्ह, पण त्यासाठी ती सोय सक्षम हवी.

खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांबाबत इतरही प्रश्न आहेत. तिकीट दरांबाबत मनमानी, क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहणे, गाड्यांच्या परवान्यांबाबत व त्यांच्या नूतनीकरणाबाबत अनास्था, बेदरकार चालक, बसमधील असुरक्षितता इत्यादी. प्रादेशिक परिवहन विभाग, पोलिसांचा वाहतूक विभाग यांचे हात या अनियमिततेवर कारवाई करायला बांधले जाऊ नयेत, हीसुद्धा यानिमित्ताने अपेक्षा. मुंबई जर वाहतूक कोंडी सोडविण्याच्या उद्देशाने खासगी प्रवासी वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी एक पाऊल टाकत असेल, तर आनुषंगिक इतर प्रश्नांवरही तोडगे काढण्यासाठी राज्याचेच एक समान धोरण झाले, तर अधिक उत्तम.

साखर निर्यातबंदीमुळे उद्योग अडचणीत येणार?

विश्लेषण

दत्ता जाधव
dattatray.jadhav@expressindia.com

केंद्र सरकारच्या साखर निर्यातबंदीमुळे अगोदरच अडचणीत असलेल्या या उद्योगासमोरील आर्थिक अडचणी वाढणार असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे सरकारने हा निर्णय अचानक का घेतला, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.

केंद्र सरकारचा नेमका निर्णय काय?

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांनी १३ मे रोजी एक परिपत्रक काढून ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. सरकारने रिफाईंड (पांढरी) आणि कच्च्या (तांबूस) साखरेवर तातडीने निर्यात बंदी लागू केली आहे. ज्यांचे निर्यातीचे करार झाले आहेत, निर्यात प्रक्रिया सुरू आहे, साखर जहाजांवर चढवली गेली आहे किंवा निर्यातीसाठी कस्टम विभागाकडे गेली आहे, अशा साखरेच्या निर्यातीला सूट दिली आहे.

केंद्राच्या साखर निर्यात धोरणात संभ्रम का?

देशातील २०२४ मधील शिल्लक साखर साठा, २०२५ तील साखरेचे उत्पादन व खप याचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकारने १४ नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशाद्वारे साखर हंगाम २०२५-२६ दरम्यान १५ लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अतिरिक्त पाच लाख टन निर्यातीला परवानगी दिली होती. पण साखर कारखान्यांनी जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत फक्त अंदाजे १.९७ लाख टन साखर निर्यात केली आहे. तर अंदाजे २.७२ लाख टन साखर निर्यात करण्याचे करार केले आहेत. कमी निर्यात होत असल्यामुळे निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आजपर्यंत स्वीकारले गेले होते. सरकार आणि साखर कारखान्यांना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ७.५ ते ८ लाख टन साखर निर्यातीची अपेक्षा होती, पण निर्यातबंदीच्या आदेशामुळे ती मावळली आहे.

अपेक्षित साखर निर्यात का झाली नाही?

केंद्र सरकारने दोन टप्प्यांत मिळून २० लाख टन साखरेच्या निर्यातीला परवानगी दिली होती. पण प्रत्यक्षात अपेक्षित निर्यात झाली नाही. जागतिक बाजारापेक्षा देशांतर्गत बाजारातच साखरेचे दर अधिक असल्यामुळे निर्यातीचा कोटा वाढविण्याचा फारसा फायदा कारखान्यांना झाला नाही. जागतिक बाजारात साखरेचा प्रति टनाचा दर सुमारे ३,६२५ रुपयांच्या दरम्यान होता. भारतीय बाजारात साखरेचे दर ३७०० ते ३८०० रुपयांपर्यंत गेले होते. घाऊक बाजारातील एस ३० ग्रेड साखरेचा दर क्विंटलला ४ ते ४,०२५ रुपयांवर होता. त्यामुळे अपेक्षित निर्यात होऊ शकली नाही. कारखान्यांनी प्रयत्नही केला नाही. एप्रिल महिन्यापासून ब्राझीलचा नवीन साखर हंगाम सुरू होईल. त्यामुळे या वर्षी एकूणच साखर निर्यातीला फारसे पोषक वातावरण राहणार नाही, अशी शक्यता असल्यामुळे उद्योगाकडून केंद्र सरकारकडे वाढीव साखर निर्यात कोटा देण्याऐवजी इंधनांमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे २७ टक्क्यांपर्यंत मिश्रण वाढविण्याची मागणी करण्यात आली होती.

साखर निर्यातीवर बंदी घालण्यामागील कारण काय?

देशात २०२५-२६ च्या हंगामात ३२९ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात ते २७९ लाख टनांपर्यंत झाले आहे. राज्यात गतवर्षी ८०.९३ लाख टन उत्पादन झाले होते. यंदा ११० लाख टनांचा अंदाज होता, तर ते १०० लाख टनांवर थांबले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये या हंगामात ८९.६५ लाख टन उत्पादन झाले आहे. कर्नाटकमध्ये गतवर्षी ४०.४० लाख टन, तर यंदा ४८.०१ लाख टन झाले आहे. उर्वरित राज्यांत फारसे साखर उत्पादन होत नाही. अंदाजापेक्षा सुमारे ५० लाख टन कमी साखर उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने तातडीने निर्यातबंदी लागू केली आहे. आखाती युद्धामुळे खनिज तेलाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे सर्वच अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात वाढ झाली आहे. त्यात साखरेच्या दरवाढ नको म्हणून केंद्राने हा निर्णय तातडीने आणि अचानक घेतला असल्याचे दिसते.

एल निनो, कमी पावसाच्या अंदाजाचा परिणाम?

यंदा देशातील मोसमी पावसावर एल निनोचे सावट आहे. भारतीय हवामान विभागाने यंदा सरासरीपेक्षा कमी, ९२ टक्के पाऊस राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तसे झाल्यास पावसाळ्यानंतरही पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता आहे. ऊस हे भरपूर पाण्याची गरज असणारे पीक आहे. बहुतांश भागात उसाला पाटाने आणि पारंपरिक पद्धतीनेच पाणी दिले जाते. पाऊस कमी झाला तर ऊस उत्पादनात मोठी घट येण्याची शक्यता आहे. शिवाय दुष्काळजन्य परिस्थितीत उसाचा चारा म्हणून वापर केला जातो. अशा अडचणीच्या काळात ऊस उत्पादन, गाळप आणि साखरेच्या उताऱ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संभाव्य एल निनो आणि कमी पावसाच्या शक्यता गृहीत धरून सरकारने निर्यातबंदी केल्याचे सांगितले जात आहे.

राज्यातील कारखान्यांची आर्थिक अडचण वाढली?

केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात साखर निर्यातीचा १५ लाख ९० हजार टन कोटा जाहीर केल्यानंतर निर्यातदारांनी ८ लाख टन निर्यातीचे सौदे केले होते. त्यापैकी ६ लाख टनांची निर्यातही झाली नाही. आता सरकारने अचानक निर्यातबंदी केल्यामुळे निर्यातदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दुसरीकडे केंद्र सरकारने साखरेच्या एफआरपीत प्रति टन शंभर रुपयांची वाढ केली आहे. यंदा १०.२५ टक्के साखर उताऱ्याला प्रति टन ३,६५० रुपये द्यावे लागणार आहेत. साखरेचे विक्री मूल्य २०१९ पासून ३१ रुपयांवर स्थिर आहे. एकीकडे एफआरपी वाढत आहे, साखरेचे विक्री मूल्य स्थिर आहे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे प्रति टन साखरेचा उत्पादन खर्च ३,३०० ते ३,५०० रुपयांवर गेला आहे. इथेनॉलसारख्या अन्य उपपदार्थांची निर्मिती होत असली तरीही आजवर साखर कारखान्यांचे ६० ते ७० टक्के आर्थिक उत्पन्न साखर विक्रीतून येते, त्यामुळे कारखान्यांना एफआरपी देण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहेत. अशा स्थितीत साखर निर्यातीवर बंदी घातल्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत येऊन पुढील वर्षी ते सुरू होऊ शकणार नाहीत, अशी स्थिती आहे.

संपादकीय

जलदरोडेखोरीचे संकट

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील पाणीसंकट, वाढते उष्णतामान, टंचाई याबद्दल चिंता व्यक्त झाली. अर्थात, चिंताप्रदर्शनाची ही पहिलीच वेळ नाही. निसर्गस्रोतांच्याही मर्यादा आहेत याचे भान ठेवून गेल्या सहा-सात दशकांमध्ये भ्रष्टाचारविरहित आणि तंत्रशुद्ध असे नियोजन केले गेले असते, तर आठ-पंधरा दिवसांतून एकदा पिण्याचे पाणी मिळते अशी वेळ गाव-शहरांवर आली नसती. पाणी योजनांची कंत्राटदाराभिमुख आणि राजकारण्यांच्या मनमानीतून निर्माण झालेली व्यवस्था हे भीषण पाणीटंचाईचे मूळ आहे. जलसंपदा असो की जलसंधारण वा पाणीपुरवठा विभाग, जनतेप्रतिच्या उत्तरदायित्वात निव्वळ नापास झालेल्या आहेत. पाण्याच्या हजारो योजनांवर आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा पाण्याच्या उपलब्धतेशी पारदर्शक मेळ बसला असता तर महाराष्ट्र सुजलाम्, सुफलाम् झाला असता. मात्र, वर्षानुवर्षे जी जलदरोडेखोरी झाली तिने महाराष्ट्राच्या पाण्याची वाट लावली. एकेका गाव-शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या योजनांमधील घोटाळ्यांची एक स्वतंत्र कहाणी आहे. ७० हजार कोटींच्या घोटाळ्यांची चर्चाच खूप झाली, त्यातून काहीही समोर येऊ शकले नाही. एवढ्या गंभीर आरोपांबाबत ही स्थिती असेल तर गावोगावच्या जलघोटाळ्यांच्या कहाण्या कधीच समोर येण्याची शक्यता नाही. एखादे मोठे धरण बांधण्याला सुरुवात केली तेव्हा काही शे कोटी रुपयांमध्येच ते बांधून पूर्ण होईल, असे सांगितले गेले. मात्र, या ना त्या कारणाने धरणाचे बांधकाम रेंगाळत गेले. तीन वर्षांत ते पूर्ण करू हा दिलेला शब्द हवेतच विरला आणि प्रत्यक्षात वीस-पंचवीस वर्षे झाली तरी प्रकल्पाचे काम सुरूच राहिले. त्यातून खर्चाचा आकडा काही हजार कोटी रुपयांवर गेला. या दीर्घ कालावधीत प्रकल्पातून कृषी सिंचन, पिण्याचे पाणी वा उद्योगांना पाणी मिळू शकले नाही; पण कंत्राटदार, अधिकारी आणि नेत्यांचे खिसे भरले गेले. ही एक-दोन नाही तर बहुतेक मध्यम आणि मोठ्या सिंचन प्रकल्पांची कटू कहाणी आहे. महाराष्ट्राच्या सिंचन प्रकल्पांमधील गैरव्यवहारांच्या तळाशी एक शब्द आहे. त्या शब्दातून या प्रकल्पांमधील खाबूगिरीची व्युत्पत्ती होते. तो शब्द म्हणजे, 'सुप्रमा'. त्याचा फुलफॉर्म आहे, 'सुधारित प्रशासकीय मान्यता'. राज्यात आजच्या घडीला एकही असा सिंचन प्रकल्प नाही ज्याची सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेतली गेली नाही. सुरुवातीलाच निर्धारित केलेल्या कालावधीत आपण प्रकल्प उभारू शकलो नाही, प्रकल्प रेंगाळत गेला मग त्याची किंमत भरमसाठ वाढत गेली आणि आधी त्यासाठी जेवढ्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता दिली गेली ती रक्कम अगदीच कमी पडत असल्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचे दार उघडले गेले. या दारातून जात मग प्रकल्पावर हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याचा संबंधित यंत्रणांना जणू परवानाच मिळाला. सुधारित प्रशासकीय मान्यता हे संपूर्ण यंत्रणेचे अपयश अधोरेखित करणारे आहे. हजारो कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभारायचे की गाव-तालुका यावर केंद्रित असे छोटे तलाव, जलसाठे तयार करायचे, याबाबत नेहमीच वाद होत राहिला आहे. जमिनीचा जसा सातबारा असतो तसा प्रत्येक गावाचा 'जल सातबारा' असला पाहिजे आणि त्यावरील नोंदींच्या आधारे पाण्याचे नियोजन झाले पाहिजे असा विचार अलीकडील काळात होऊ लागला असला तरी तो प्रत्यक्षात आणण्याची सरकारची मानसिकता मात्र दिसत नाही. जल सातबारा म्हणजे एक विशिष्ट गाव आणि गावाच्या परिसरात पडणारा पाऊस, त्याच्या साठवणुकीसाठी कोणत्या उपाययोजना केलेल्या आहेत, तसेच गावावर पडणाऱ्या पावसाची मालकी त्या गावाची आहे हे गृहीत धरून त्या गावाला त्या पाण्याचा फायदा व्हावा यासाठी काय काय केले जाते या सर्वच गोष्टींचा लेखाजोखा. पूर्वी उन्हाचा कहर हा विदर्भातील काही जिल्ह्यांपुरता मर्यादित होता. आज तो मराठवाड्यापासून उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचला आहे. यंदाही सरासरीपेक्षा पाऊस कमी पडण्याचा हवामान खात्याचा अंदाज असून, दुष्काळाची भीतीदेखील व्यक्त केली जात आहे. जलसाठे आटत चालले आहेत. या संभाव्य टंचाई आणि दुष्काळाला रोखण्यासाठी सरकार उपाययोजना करेलच, पण हे आता दरवर्षीचेच झाले आहे. नदीजोड प्रकल्पांपासून तर नद्यांच्या पुनरुज्जीवनापर्यंतच्या दीर्घकालीन उपाययोजना सरकारने हाती घेतल्या असल्या तरी, पूर्वानुभव लक्षात घेता त्यापासूनचे प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत एखाद-दीड दशक प्रतीक्षाच करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाण्याअभावी होणारे हाल, दुष्काळ निवारणाच्या नावाखाली कंत्राटदार-अधिकारी-नेत्यांची दुकानदारी अशीच सुरू राहील हेच आजचे कटू सत्य आहे.

अतिवेगवान बुलेट ट्रेन हा 'पांढरा हत्ती' ठरणार का?

पंतप्रधानांनी देशातील इतर शहरे बुलेट ट्रेनने जोडण्याची बोली केली खरी; पण पहिली बुलेट ट्रेन व्यवहार्य कशी होईल, हाच पेच अजून सुटलेला नाही.

हरीष गुप्ता
नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

सरकारचे अतिवेगवान रेल्वेचे महत्त्वाकांक्षी स्वप्न पुढे तर सरकते आहे; परंतु एक मोठा प्रश्न पाठ सोडत नाही- बुलेट ट्रेन व्यवहार्य कशी करावी? मुंबई-अहमदाबाद अतिवेगवान रेल्वे कॉरिडॉर हा देशातला पहिला ताशी ३२० किलोमीटर वेगाचा प्रकल्प आहे. पूर्वी त्याचा खर्च ९० हजार कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला होता. आता मात्र तो दोन लाख कोटींच्या घरात पोहोचल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे तंत्रज्ञानातली ही उडी एक गंभीर आर्थिक कोडे झाल्यासारखे आहे.

जमीन संपादनातील दिरंगाई, कोविड-१९ मुळे पडलेला खंड आणि वाढता बांधकाम खर्च या सगळ्यांमुळे हा ५०८ किलोमीटरचा कॉरिडॉर महाग होत गेला. जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीने या प्रकल्पाचे मूळ भांडवल पुरवले आहे. प्रकल्पाला प्रारंभी जो खर्च येणार होता त्याच्या ८१ टक्के रक्कम ही एजन्सी दीर्घ मुदतीचे कर्ज म्हणून उचलणार असे ठरले आहे; परंतु टोकियोने आता स्पष्ट केले आहे की वाढता खर्च एजन्सी उचलणार नाही. त्यामुळे त्याचा भार नवी दिल्लीवर पडणार आहे. स्वाभाविकच या पार्श्वभूमीवर आता हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य करावयाचा कसा यावर सरकारमध्ये घनघोर चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षीय टीकाकारांनी आधीपासूनच याला 'पांढरा हत्ती' असे संबोधायला सुरुवात केलेली होती. सामान्य प्रवाशाच्या खिशाला मुळीच परवडणार नाही अशी या गाडीची तिकिटे असतील असा त्यांचा दावा आहे; तर समर्थकांचे म्हणणे असे की, ही चर्चा इतक्यात नको.

या मार्गावर दिवसाला ३५ गाड्या धावणार आहेत. वर्षाला १.६ कोटी प्रवासी वाहून नेले जातील. वेळेची मोठी बचत होणार असल्याने या दोन महत्त्वाच्या व्यापारी शहरांना त्याचा लाभ होईल. ऑगस्ट २०२७ मध्ये सुरत आणि बिलीमोरियापर्यंत झालेल्या कामाची चाचणी घेतली जाईल; परंतु वाढत्या खर्चाचा प्रश्न हा केवळ एका प्रकल्पापुरता नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील इतर शहरे बुलेट ट्रेनने जोडण्याची बोली केली आहे. भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन व्यवहार्य कशी होईल असा पेच असेल तर इतर कशा सुरू होतील?- या विषयावर एक अंतर्गत गट नेमण्यात आला असून तो बुलेट ट्रेनचा प्रवास व्यवहार्य कसा होईल, यावर विचार करत आहे.

निर्मला सीतारामन कुठे आहेत?

चलनवाढ, रुपयाची घसरण, उपभोग मंदावणे यांसारख्या दडपणांचा सामना भारतीय अर्थव्यवस्था करत असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या फारशा लोकांसमोर येत नाहीत. यापूर्वीचे अर्थमंत्री जेव्हा परिस्थिती गडबडलेली असेल तेव्हा आक्रमकपणे लोकांना काही ना काही सांगताना दिसायचे. सीतारामन यांनी मात्र मौन आणि सबुरी बाळगायचे ठरवले आहे.

वाढत्या किमती, छोट्या उद्योगांवर येणारा ताण, घरगुती बचत कमी होणे यांसारख्या मुद्द्यांनी अर्थमंत्रालयाला लक्ष्य करण्यासाठी विरोधकांना पुरेसा दारूगोळा पुरवला आहे. असे असले तरी त्यांचे समर्थक म्हणतात की, सर्वसाधारण आर्थिक चित्र स्थिर आहे. जगातील इतर अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारतातील आर्थिक घडी तेवढी विस्कटलेली नाही. जागतिक पातळीवर अस्थिरता असली तरी देशात या गोष्टी पुष्कळ चांगल्या स्थितीत आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे.

सीतारामन या राजकीय नेत्या कधीच नव्हत्या. त्यांनी कधी मोठी राजकीय भूमिका घेतली असेही दिसत नाही. जवळपास आठ वर्षे त्या अर्थ खाते सांभाळताना गरज असेल तेव्हाच बोलण्याचा लौकिक त्यांनी प्राप्त केला आहे. सरकारमधील सूत्रांचे म्हणणे असे की, पंतप्रधानांचे कार्यालय आर्थिक संदेश काय जातो आहे याकडे बारीक लक्ष ठेवून असते. सीतारामन 'साऊथ ब्लॉक'ला काय सांगायचे ते सांगू देण्यात स्वतःला सुरक्षित मानतात. आता आर्थिक चिंता वाढलेल्या असताना तर अर्थमंत्र्यांनी आणखीच कोशात जाणे पसंत केलेले दिसते.

प्रतीक्षा लांबली

गेल्या जानेवारीत नितीन नवीन यांनी भाजपचे अध्यक्ष म्हणून सूत्रे हाते घेतली. त्यानंतर पाच महिने उलटले तरी अजून त्यांना त्यांचा संघ मिळालेला नाही. नव्या चमूमध्ये आधीचे काही, नव्या पिढीतलेही सदस्य असावेत असा विचार आहे म्हणतात. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये तरुण चेहरे असावेत यासाठी कमाल वयोमर्यादा ६० ठरवण्याचा एक विचार पुढे आला आहे. सुनील बन्सल, विनोद तावडे हे दोघेही सरचिटणीस आहेत. त्यांच्यासह बी. एल. संतोष यांनाही पुढे चाल मिळेल अशी चिन्हे आहेत. आधी राम माधव यांचे नाव घेतले जात होते; परंतु त्यांना कोणते काम मिळेल, याविषयीची खात्री कोणी देत नाही. राधा मोहनदास अग्रवाल, तरुण चुग, दुष्यंत गौतम आणि अरुण सिंग यांच्यासारख्या सरचिटणीसांना दुसरे काम दिले जाईल, अशी शक्यता आहे; पण तूर्त हे सगळे टांगणीलाच लागलेले आहे आणि नितीन नवीन काही बोलायला तयार नाहीत.

harish.gupta@lokmat.com

अन्वयार्थ

अमेरिका उतरणीला, तर चीन उदयाला येत आहे...

डोनाल्ड ट्रम्प पहिल्या कार्यकाळात आले, तेव्हा चीनमध्ये त्यांचे जोरदार स्वागत झाले. यावेळी मात्र ना चीनने त्यांना फार महत्त्व दिले, ना माध्यमांनी!

सुवर्णा साधू
चिनी राजकारण-समाजकारण यांच्या अभ्यासक

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा २०१७ मधील चीनचा दौरा त्यांच्या अध्यक्षीय कार्यकाळातील अत्यंत महत्त्वाचा दौरा म्हणून गणला जातो. दौऱ्यात झालेले त्यांचे भव्य स्वागत, अब्जावधी डॉलर करारांच्या घोषणा आणि 'ट्रम्प - शी जिनपिंग' यांच्यातील मैत्रीचे प्रदर्शन.. या त्यावेळच्या काही ठळक गोष्टी. चिनी माध्यमांनीदेखील ट्रम्पसारख्या प्रतिष्ठित पाहुण्यांचे स्वागत शक्तिशाली आणि आत्मविश्वासू चीन करीत आहे, असे दाखविले. हे एक अत्यंत काळजीपूर्वक आखलेले राजनैतिक नाट्य होते, ज्यातून चीनचा वाढता आत्मविश्वास आणि शी जिनपिंग यांची मजबूत राजकीय पकड जगासमोर आली. जिनपिंग शांत, संयमी आणि आत्मविश्वासपूर्ण दिसत होते, तर ट्रम्प समारंभांच्या भव्यतेने प्रभावित झालेले.

जवळ-जवळ एका दशकानंतर, मागच्या आठवड्यात ट्रम्प पुन्हा चीनला गेले. जागतिक युद्धे, इंधनटंचाई, रशिया - चीनचा इराणला पाठिंबा आणि ट्रम्प सरकारने चीनवर लागू केलेले शुल्क या पार्श्वभूमीवर या भेटीदरम्यान चीनने निराळे धोरण अंगीकारले. चिनी प्रसारमाध्यमांनी या भेटीला फारसे महत्त्व दिले नाही. अमेरिकेतील प्रभावशाली उद्योगपतींच्या मोठ्या प्रतिनिधी मंडळासह झालेल्या या भेटीतून माफक आर्थिक करार निष्पन्न झाले; कोणतेही मोठे यश किंवा ठोस आश्वासने मिळाली नाहीत. ट्रम्प यांची ही भेट अत्यंत निरस आणि कंटाळवाणी ठरली. शी यांनी चीनच्या संवेदनशील बाबींवर चर्चा टाळली. तैवान, लोकशाही, मानवाधिकार याबाबतीत काही चर्चा झाल्या का, असे एका पत्रकाराने ट्रम्पना विचारल्यावर त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले. हे त्यांच्या स्वभावाच्या विपरीत आहे!

१४ मे रोजी 'टेंपल ऑफ हेवन'च्या भेटीला प्रतीकात्मक महत्त्व होते. राष्ट्रीय समृद्धी आणि सौहार्दासाठी, प्राचीन सम्राट प्रार्थना करीत असलेल्या या ऐतिहासिक स्थळाचा उपयोग अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी जाणीवपूर्वक केला असावा तो ट्रम्पना 'शांतता, सौहार्द आणि सहअस्तित्व' या पारंपरिक चिनी तत्त्वज्ञानाची ओळख करून देण्यासाठी. द्विपक्षीय संबंध हे स्पर्धेवर आधारित नसून, स्थिरतेवर आधारित असायला हवेत याचा पुनरुच्चार जिनपिंग यांनी केला.

प्रस्थापित आणि एका उदयोन्मुख महासत्तेमध्ये होणाऱ्या संघर्षाच्या सापळ्यात अडकण्यापासून दूर राहिले पाहिजे, असे जिनपिंग यांनी परत एकदा ठसवले. बीजिंगमध्ये झालेली बैठक केवळ द्विपक्षीय राजनैतिक भेट नाही, तर वाढत्या प्रमाणात जागतिक व्यवस्थेला आकार देणाऱ्या संरचनात्मक सत्तांतराचे व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न होता.

या चर्चांमधून अमेरिकेतील महत्त्वाच्या उद्योगांवरील चीनची वाढती पकड स्पष्ट झाली. चीनचा वाढता आर्थिक प्रभाव अमेरिकेसाठी आव्हान आहे. तैवानच्या प्रश्नाचे चुकीचे व्यवस्थापन द्विपक्षीय संबंधांना संघर्षाच्या दिशेने ढकलू शकते, असा इशारादेखील चीनने दिला. एकेकाळी प्रगत सेमिकंडक्टर चिप्ससाठी अमेरिकेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेला चीन आज अनेक महत्त्वाच्या तांत्रिक क्षेत्रांत, सुमारे ४५% स्वयंपूर्णतेकडे पोहोचला आहे. अमेरिकेने लादलेल्या निर्बंध आणि शुल्कांना प्रत्युत्तर म्हणून चीनने 'रेअर अर्थ' संसाधनांचा प्रभावी वापर केला. हेच निर्बंध आणि शुल्कांनी चीनला तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल सर्किट्स आणि उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे ढकलले.

पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या प्रश्नावर चीनची भूमिका स्पष्ट आणि आहे. चीनने होर्मुझ बंद होण्याच्या परिस्थितीसाठी अमेरिकेलाच जबाबदार धरले. मात्र, चीन स्वतःही या परिस्थितीबद्दल सावध आहे. चीनकडे प्रचंड मोठे तेलसाठे असले, तरी होर्मुझ कायमस्वरूपी बंद राहणे चीनलाही परवडणारे नाही. म्हणूनच चीन 'freedom of navigation' आणि कोणताही अतिरिक्त टोल न लावण्याच्या भूमिकेचा आग्रह धरतो आहे.

चीनने जागतिक पुरवठा साखळीवर प्रचंड पकड निर्माण केली आहे. जगातील जवळपास एक-तृतीयांश औद्योगिक उत्पादन चीनमध्ये तयार होते आणि २०३० पर्यंत हा वाटा ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. नव्या ऊर्जा व्यवस्थेकडे होणाऱ्या संक्रमणात- विशेषतः इलेक्ट्रिक आणि ऊर्जा-आधारित वाहनांमध्ये चीन जगातील सर्वांत मोठा उत्पादक बनला आहे. चीनने पश्चिमी अर्थव्यवस्थेवरील अवलंबित्व झुगारून, स्वतःची जागतिक प्रतिमा उभी केली आहे. "अमेरिका उतरणीला लागली आहे, तर चीन उदयाला येत आहे," या जिनपिंग यांच्या वक्तव्याला ट्रम्प यांनीही दुजोरा दिला. बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेत चीन स्वतःला केंद्रस्थानी पाहू इच्छितो. टेंपल ऑफ हेवनला दिलेली भेट ही केवळ सांस्कृतिक नव्हे तर, राजनैतिकदृष्ट्याही त्याच संदेशाचे प्रतीक होती, हेच खरे.

suvarna_sadhu@yahoo.com

जगभर

ट्रम्प यांनी चिनी भेटवस्तू फेकल्या कचराकुंडीत!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नुकतेच चीनच्या बहुचर्चित दौऱ्यावर जाऊन आले. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जीनपिंग यांच्याशीही त्यांची भेट झाली आणि काही विषयांवर त्यांनी 'पडद्याआड' चर्चाही केली. मात्र, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प बीजिंगहून परतण्यापूर्वी अशी एक घटना घडली, जिनं सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं.

दौरा आटोपल्यावर ट्रम्प एअरफोर्स वनमधून आपल्या देशाकडे रवाना झाले. मात्र, तत्पूर्वी त्यांना चीनकडून आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याकडून मिळालेल्या सर्व मौल्यवान भेटी त्यांनी विमानतळावरील कचराकुंडीत टाकल्या! या घटनेमुळे सगळ्या जगानं आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. विमानात बसण्यापूर्वी व्हाइट हाऊसच्या कर्मचाऱ्यांनी चिनी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेली क्रेडेन्शियल्स, बर्नर फोन, डेलीगेशन पिन आणि इतर सर्व साहित्य एकत्र करून फेकून दिलं. -का केलं त्यांनी असं?

ट्रम्प यांच्यासोबत बीजिंग दौऱ्यावर गेलेल्या न्यूयॉर्क पोस्टच्या व्हाइट हाऊस प्रतिनिधी एमिली गुडिन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर आपल्या पूल डिस्पॅचमध्ये लिहिलं, 'अमेरिकी कर्मचाऱ्यांनी चिनी अधिकाऱ्यांनी दिलेलं सगळं साहित्य एअरफोर्स वन (AF1) मध्ये बसण्यापूर्वी जिन्याखाली ठेवलेल्या कचरापेटीत फेकून दिलं. कारण चीनशी संबंधित कोणतीही वस्तू विमानात नेण्याची परवानगी नव्हती. चीन दौऱ्यादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाला मिळालेल्या भेटवस्तू कचरापेटीत फेकण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे चीनकडून सायबर हेरगिरी आणि इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंगचा गंभीर संशय होता. अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणांनी कडक निर्देश दिले होते की, चीनकडून मिळालेली कोणतीही वस्तू एअरफोर्स वनमध्ये (राष्ट्राध्यक्षांचं विमान) नेली

जाणार नाही. त्यामुळेच या साऱ्या वस्तू कचराकुंडीत फेकून देण्यात आल्या.

मीडिया रिपोर्टनुसार, हे पाऊल अमेरिकेच्या उच्चस्तरीय सुरक्षा आणि काउंटर-इंटेलिजन्स प्रोटोकॉलचा भाग होता. अमेरिका अनेकदा रणनीतिक प्रतिस्पर्धी मानल्या जाणाऱ्या देशांच्या दौऱ्यादरम्यान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं आणि संवेदनशील साहित्य नष्ट करतं किंवा जमा करतं, जेणेकरून हेरगिरीचा धोका टाळता येतो.

ट्रम्प यांनी आपला चीन दौरा आणि चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत झालेली बैठक सौहार्दपूर्ण असल्याचं सांगितलं असलं, तरी अमेरिका आणि चीन यांच्यात व्यापार असमतोल, तंत्रज्ञान स्पर्धा, तैवान आणि इराण युद्ध यांसारख्या मुद्द्यांवर गंभीर मतभेद अजूनही कायम आहेत. अमेरिकन सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी हे पाऊल यासाठी उचललं, जेणेकरून चिनी भेटवस्तूंमार्फत कोणतंही ट्रॅकिंग डिव्हाइस, मालवेअर किंवा स्पायवेअर अमेरिकन पथकासोबत परत येऊ नये.

'बर्नर फोन' म्हणजे असा मोबाइल फोन, जो कमी काळासाठी वापरून नंतर टाकून दिला जातो किंवा त्याचा वापर बंद केला जातो. गोपनीयतेच्या कारणासाठी हे फोन वापरले जातात. स्पॅम कॉल्स किंवा डेटा लिकपासून बचावासाठी, तसंच गुन्हेगारी वापर किंवा ट्रॅकिंग टाळण्यासाठी मोठे राजकीय नेते हा फोन वापरतात. काम झाल्यावर लगेच हे फोन नष्ट केले जातात. हे पाऊल अमेरिका आणि चीन यांच्यामधील वाढत्या अविश्वासाचं प्रतीक तसंच तांत्रिक युद्धाचा एक भाग मानलं जात आहे.

जनमन

श्रीमंतीचे 'अधिक' प्रदर्शन कशासाठी?

एआय इमेज

गेल्या वेळेसचा अधिक महिना म्हणजे एक इव्हेंटच होता. आमच्या आयुष्यात पहिल्यांदाच अधिक महिना आलाय असं वाटत होतं. काय ते जावई-मुलींची फुलांच्या वाटेवरून एन्ट्री, मुलीला दिल्या जाणाऱ्या महागड्या साड्या, दागिने, जावयाला सोनं-चांदी, महागडे पोशाख, फळांच्या, गोड पदार्थांच्या टोकऱ्या, घरादाराला जेवणावळी, एवढं कमी होतं की काय, तर काहींनी मुली - जावयांना गाड्यासुद्धा दिल्या. यंदाही काही जणांनी जावयाला चांदीच्या चपला दिल्याचं वर्तमानपत्रात वाचलं.

तुम्ही खूप काही करू शकता तुमच्या मुली-जावयांसाठी, मान्य आहे. करा तुमच्याकडे आहे तर, पण ते जरा खासगी ठेवा ना...! ज्या आई-वडिलांची परिस्थिती जेमतेम आहे त्या बिचाऱ्यांनी कुठून करायचं हे सर्व? त्यांनी कुठून करावा एवढा डामडौल? हे सर्व पाहून अनेक जण अशीच अपेक्षा करायला लागतात सासूरवाडीकडून! मलाही एवढ्या भेटवस्तू मिळतील म्हणून. आणि तसं नाही झालं की, झाला त्या मुलीला सासूरवास चालू...

कुणा आई - वडिलांना तुमच्या दिखाव्यामुळे मान खाली घालावी लागली, अपमान झाला त्यांचा, त्यांच्या परिस्थितीचा, कुणा मुलीचा संसार मोडला, अशा चुकांमुळे, पैशांच्या अशा प्रदर्शनामुळे, तर त्याला जबाबदार कोण? कसलं समाधान मिळवतोय आपण हा सगळा दिखावा करून? अधिक महिना म्हणजे लेकी-जावयाचं कौतुक करायचा सण. साडी-चोळी, पोशाख, दीपदान, अनारशाच भरलेलं ताट, तांब्याचा दिवा हे सगळं देऊन आपले संस्कार जपा. दिखाऊपणाला भुलून दुसऱ्यांना त्रास होईल असं वागू नका. रितीरिवाज पाळा, पण आपल्या असलेल्या, नसलेल्या श्रीमंतीचे प्रदर्शन कशासाठी?...

- स्वाती किसन भिसे, पिंपळे सौदागर

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

सेतू

निवृत्त जेनी जेव्हा सरकारी लायब्ररीत स्वयंसेवक म्हणून येते..

लायब्ररीत स्वयंसेवक म्हणून काम करणारी जेनी आणि तिच्या मैत्रिणी. ऑस्ट्रेलियात अशा अनेक कामांमध्ये स्वयंसेवकांना सामावून घेतले जाते.

हिमानी नीलेश
सीनिअर लायब्ररी ऑफिसर, ॲडलेड, ऑस्ट्रेलिया

मी ऑस्ट्रेलियात आमच्या अडलेड या गावी सीनिअर लायब्ररी ऑफिसर म्हणून काम करते. आज आमच्या लायब्ररीत जेनी आणि अजून तीन जणी पुस्तकांची वर्गवारी करून ती मांडणीवर रचून ठेवत होत्या. हे सकाळी दोन तास केल्यावर त्या त्यांच्या नेमून दिलेल्या लायब्ररीच्या ग्राहकाकडे त्याच्यासाठी खास निवडून ठेवलेली पुस्तकं पोचती करणार होत्या. मग ताई-ची व्यायामाचा क्लास आणि मग सगळ्यांचे मिळून छानशा कॅफेमधे एकत्र जेवण असा भरगच्च कार्यक्रम होता.

यांची वय वर्षे सत्तरीपुढची ! इथले ज्येष्ठ नागरिक अशा पद्धतीच्या स्वयंसेवी कामांमध्ये इतके व्यग्र असतात की, विचारू नका. इथली सार्वजनिक ग्रंथालयं चकटफू असतात; पण त्यातले कर्मचारी शासनाचे अधिकारी म्हणून पगारी काम करतात. आमच्या ग्रंथालयात दिवसाला सरासरी हजारेक लोकांची आवक असते. त्यामुळे कामाचा रगाडा प्रचंड. जेनीसारखे अशा संस्थांचा अविभाज्य घटक असतात.

आमची जेनी. निवृत्त झाल्यानंतर तिला रोज उठून काही करण्यास प्रयोजन हवं, शारीरिक हालचाल हवी, मानसिक चालना हवी आणि या सगळ्यात एक नियमितता हवी ही माणूस म्हणून तिची गरज होती. तिच्यासारखे लाखो ज्येष्ठ नागरिक हे काम अत्यंत आनंदाने आणि उमेदीने करतात. नोटरीचं काम इथले काही स्वयंसेवक जस्टिस ऑफ पीस या नात्याने करतात. त्यासाठी विशेष पात्रता लागते. ज्येष्ठांसाठी स्कॅम ओळखण्याचे प्रशिक्षणवर्ग चालवणारे, तसेच

जेनी तिच्या मैत्रिणींसोबत ॲडलेडच्या ग्रंथालयात.

एखाद्या कामाचा करिअर म्हणून विचार करणारे, पण सध्या शिक्षण घेत घेत संस्थेत काम करणारे तरुण स्वयंसेवक असतात. मानसिक, शारीरिक व्यंग असलेल्या स्वयंसेवकांना सुयोग्य कामे दिली जातात.

मी सध्या लायब्ररीत नेहमीच्या कामाव्यतिरिक्त या स्वयंसेवकांचं व्यवस्थापानही बघते. मला आठवतो जेनी आल्याचा पहिला दिवस... शिरस्त्यानुसार तिनं आधी स्वयंसेवक म्हणून कामासाठी अर्ज केला होता. तिचं नाव, पत्ता याची नोंदणी झाल्यावर हे काम तिला शारीरिक, मानसिकरीत्या पेलू शकेल का, याचा बातचीत करून अंदाज घेतला गेला. शासनाच्या अधिपत्याखाली स्वयंसेवा करण्यास ती सुयोग्य आहे, असं पोलिसांमार्फत शिफारसपत्र तिनं आधीच आणलं होतं. आता दोन दिवस तिचं इतरांबरोबर काम कसं करायचं याचं शिबिर झालं. कामाची उपकरणं हाताळतानाची काळजी कशी घ्यायची, याचं रीतसर मार्गदर्शन केलं गेलं. जेवणाची खोली, स्वच्छतागृह, आपत्कालीन काळात घ्यायची खबरदारी याची माहिती सविस्तर दिली गेली. आठवड्यात संस्था आणि जेनीला कुठले दिवस व वेळा सोयीच्या आहेत हे पाहून त्यांचा वेळापत्रकात समावेश केला गेला. इथले स्वयंसेवक त्या वेळा, दिवस अत्यंत काटेकोरपणे पाळतात. जमणार नसेल तर शक्यतो आधी कळवतात. जेनी आणि मैत्रिणी तर कुणाला जमणार नसेल तर आपणहून ती जागा भरून काढत असत. आमच्या लायब्ररीत येऊन एक वर्ष झाल्यावर त्यांचा एक छानसा कौतुक सोहळा करण्यात आला. त्यात त्या मस्त नाचल्या-गायल्या. त्यांना मिळलेला स्वयंसेवकांचा बिल्ला त्या त्यांच्या नातवंडांना अभिमानानं दाखवत होत्या आणि नातवंडं आणि त्याची मुलं यांना त्याचं कोण कौतुक होतं...

himaninilesh123@gmail.com

सेतू : जगभरातील मराठी माणसांच्या जगण्यातले रूपरंग शोधणारा हा स्तंभ. तुम्ही स्वत:, तुमचे आप्त परदेशात राहात असाल, तर तुमचे अनुभव जरूर पाठवा. निवडक लेखनाला प्रसिद्धी. **ईमेल करा :** setu@lokmat.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.)
'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 21 मई 2026

दुनिया को मिलकर काम करना सीखना होगा, नहीं तो मानवता को नुकसान होगा।
– ड्वाइट आइजनहावर, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति

BRICS में नई जान!

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन सितंबर में BRICS शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे। माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग भी इस दौरान दिल्ली आ सकते हैं। इन दोनों नेताओं का दौरा BRICS की अहमियत को फिर से स्थापित करने वाला है। साथ ही, हाल में दुनिया जिस तरह से बदली है, उसे देखते हुए यह इनके आपसी रिश्तों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।

समझौते का मंच । पूतिन पिछले साल दिसंबर में भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन के लिए भारत आए थे। वहीं, शी का आखिरी दौरा 2019 में हुआ था। 2020 में गलवान के टकराव के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते चले गए। जब भारत-चीन में कूटनीतिक और सैन्य तनाव चरम पर था, तब भी BRICS ही प्रेशर रिलीज करने का जरिया बना। अक्टूबर 2024 में रूस में BRICS सम्मेलन के इतर पीएम नरेंद्र मोदी और शी की मुलाकात हुई थी। इसके बाद रिश्ते सामान्य करने के लिए कई कदम उठाए गए।

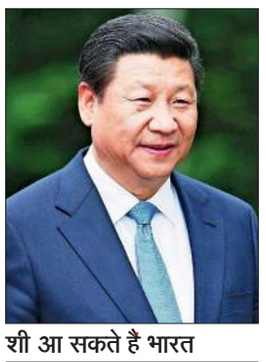
शी आ सकते हैं भारत

सुधार का मौका । BRICS की अहमियत अब इसके सदस्य देशों से आगे पूरी दुनिया के लिए है। पश्चिम एशिया संकट की वजह से जो अस्थिरता आई है, उसे संभालने में यह मंच अहम भूमिका निभा सकता है। इसी महीने दिल्ली में BRICS देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत ने इस दिशा में प्रयास भी किया, हालांकि कोई सहमति नहीं बन पाई। इस समय अध्यक्षता भारत के पास है और सितंबर में असहमतियों को दूर करने का सुनहरा मौका होगा।

बहुध्रुवीय व्यवस्था । एक समय भारत-चीन के बीच तल्खी, यूक्रेन युद्ध और ट्रंप की धमकियों की वजह से BRICS प्रासंगिकता खोता लग रहा था। खासतौर पर ट्रंप नहीं चाहते कि यह मंच मजबूत हो, क्योंकि इससे उन्हें डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती मिलती दिख रही है। लेकिन, ट्रंप फिलहाल आक्रामक रुख अपनाने की स्थिति में नहीं दिख रहे। रूस के प्रति वह नरम पड़ चुके हैं और चीन से दोस्ती को बेकरार हैं। BRICS के उभरने का यह बिल्कुल सही समय है। इससे किसी एक देश के एकाधिकार को तोड़ने और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

आपसी सहयोग । इस मंच के इतर भारत, रूस और चीन के रिश्तों के बदलते डायनेमिक्स के लिए भी सितंबर दौरा महत्वपूर्ण है। व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर तीनों अर्थव्यवस्थाओं को एक-दूसरे का साथ चाहिए। आपसी प्रतिस्पर्धा के बावजूद इनके बीच सहयोग बेहद अहम है। नया वर्ल्ड ऑर्डर कितना संतुलित होता है और कैसा आकार लेता है, बहुत कुछ इन तीनों देशों के आपसी समीकरण पर निर्भर करेगा।

गुस्ताख़ी माफ़

वाद पर विवाद

'एक के बाद एक परीक्षा का परचा लीक हुआ जा रहा है। इस तरह तो व्यवस्था से ही भरोसा उठ जाएगा भाई साब।' श्रीमान क ने सुबह-सुबह पार्क में मिलते ही कहा। मैं अंतरराष्ट्रीय चिंताओं पर मंथन कर रहा था। लेकिन श्रीमान क के चेहरे पर उभरी चिंता के सामने दुनिया की फिक्र काफी हल्की जान पड़ी।

अखिलेश प्रताप सिंह

श्रीमान क सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलने वाले हुए। सबेरे-सबेरे बच्चे को स्कूल बस तक छोड़कर पार्क में टहलना वर्षों से उनका नियमित कार्यक्रम रहा। वक्त पर ऑफिस पहुंचना, बॉस की पुतली घूमने से पहले फाइलें निपटाना और शाम को लौटते समय सब्जी का थैला लिए घर पहुंचना उनके रूटीन ठहरा। ऐसे तो मासूम से हुए वो। पर आज वह परीक्षा पे चर्चा के मूड में थे क्योंकि बिटिया को दोबारा इम्तिहान में बैठना था। मैंने उन्हें ढांढस बंधाया कि कोचिंग में लगे तीन लाख रुपये पर भरोसा न हो, तो कम से कम बिटिया की काबिलियत पर भरोसा रखें। पर उनका चेहरा ऐसे कैप्टन जैसा हुआ जा रहा था जिसकी टीम जीतने वाली हो और ऐन वक्त पर बारिश से पॉइंट बांटने की नौबत आ जाए।

'कुछ लोगों की वजह से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है भाई साब। इन्हें तो सूली पर टांग दिया जाए, तो कुछ सबक मिले।' श्रीमान क ने गुस्से से कहा। 'लेकिन सूली पर चढ़ाएगा कौन?' सवाल सुन श्रीमान क अचकचा गए। उनके चेहरे पर निल बटे सन्नाटा देख मैंने हंसाने की कोशिश में कहा, 'पहले वाला जमाना ही ठीक था। सबको मौका मिलता था। एग्जाम सेंटर की चारदीवारी पर हुजूम लगा रहता। बच्चे खिड़की से पर्चा फेंकते। किसी के भी हाथ लगता, सॉल्व किया जाता था सबके लिए। फिर बाप, भाई, दोस्त किसी ओलंपियन की तरह जवाब वाले पन्ने को गेंद बनाकर अंदर फेंकते। पूरा समाजवाद था। आज तो सारा खेल कुछ लोगों के हाथ में चला गया है। पूंजीवाद में यही तो खराबी है।' श्रीमान क कुछ कहना चाहते थे, पर किचकिचा कर रह गए।

एकदा

संकलन : **ललित गर्ग**

मज़दूरों का साथ

महापुरुषों की महानता उनके व्यवहार और विनम्रता में छिपी होती है। ऐसी ही एक कहानी अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन से जुड़ी है। एक दिन घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर लकड़ी के एक भारी लट्ठे को ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। पास में ठेकेदार खड़ा था, जो मजदूरों पर चिल्ला रहा था कि वे एक काम नहीं कर पा रहे। वॉशिंगटन उस ठेकेदार के पास पहुंचे और नम्र आवाज में कहा, 'अगर आप भी हाथ बंटा दें, तो काम आसान हो जाएगा।' इस पर ठेकेदार को गुस्सा आ गया। वह ऊंचे स्वर में बोला, 'मैं अधिकारी हूं, मेरा काम आदेश देना है, मजदूरी करना नहीं।' यह सुनते ही वॉशिंगटन तुरंत घोड़े से उतरे और खुद मजदूरों के साथ कंधा मिलाकर लट्ठा उठाने में मदद करने लगे। कुछ ही देर में काम पूरा हो गया। जाते समय उन्होंने मुस्कुराकर ठेकेदार से कहा, 'अगली बार जब एक आदमी कम पड़े, तो मुझे बुला लेना। मेरा नाम जॉर्ज वॉशिंगटन है।' ठेकेदार ने उनसे माफी मांगी। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची महानता पद में नहीं, विनम्रता और संवेदनशील व्यवहार में है।

Subrata Dhar

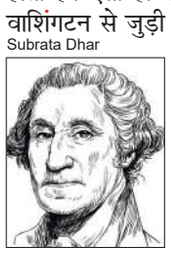

सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश व्यावहारिक नहीं

स्ट्रे डॉग्स से जुड़े फ़ैसले पर अमल हो पाएगा?

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से थोड़ी राहत मिली है। अदालत ने माना कि आवारा कुत्तों को बेवजह मारना समाधान नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम और पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम जारी रहेंगे ताकि इंसानों की सुरक्षा के साथ पशु संरक्षण भी हो सके।

शालीन अत्रे

कई चुनौतियां । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए टीकाकरण और नसबंदी ही रास्ता है। अदालत ने राज्यों से वेटरनरी सुविधाएं बढ़ाने, ABC केंद्रों को मजबूत करने, कचरा प्रबंधन सुधारने और सार्वजनिक स्थानों से हटाए गए कुत्तों का टीकाकरण व नसबंदी करने को कहा है। कागजी तौर पर तो यह आदेश मजबूत दिख रहा है, पर चुनौती इस पर अमल में आएगी।

मुश्किल काम । देश में आज भी ABC इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। ऐसे में बड़े पैमाने पर कुत्तों को पकड़ना, उनकी नसबंदी, टीकाकरण व निगरानी आसान नहीं होगा। देश में आवारा कुत्तों के सही आंकड़े भी नहीं हैं, यह भी एक दिक्कत है।

व्यापक असर । खैर, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों की मौजूदगी कामकाज में बाधा पैदा कर सकती है। इसीलिए उन्हें वहां से हटाया जाए। लेकिन, भारत जैसे देश में इसे लागू करना आसान नहीं। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थान पूरी तरह बंद नहीं होते, इसीलिए कुत्तों को हटाने के बाद दूसरे जानवर वहां आ सकते हैं।

कई सवाल । सबसे बड़ा सवाल है कि हटाए गए कुत्तों को कहां रखा जाएगा, उनका इलाज कौन कराएगा और उन्हें खाना कौन देगा? कौन निगरानी करेगा और कौन खर्च उठाएगा? बड़े स्तर पर कुत्तों को बंद स्थान पर रखने से बीमारियां फैलने का खतरा है। अदालत ने यह तो कहा कि मौजूदा बुनियादी ढांचा आदेश पर अमल करने में सक्षम है। लेकिन, नगरपालिकाएं आज तक पर्याप्त ABC सेंटर, नसबंदी और टीकाकरण की व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाई हैं।

निगरानी जरूरी । असल सवाल है कि मौजूदा व्यवस्था कमजोर है। वह अचानक इतना बड़ा बोझ कैसे संभालेगी? सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और ABC सेंटर से जुड़ी कुछ गड़बड़ियों को माना है, लेकिन सिर्फ चिंता जताना समाधान नहीं। कई ABC सेंटर में भीड़भाड़, फर्जी नसबंदी के आंकड़े, गैरकानूनी दया मृत्यु, जानवरों के लापता होने और वित्तीय अनियमितताएं जैसी शिकायतें पहले से हैं। अगर अब भी मजबूत और स्वतंत्र निगरानी नहीं की गई, तो बड़े स्तर पर यही समस्याएं दोहराई जा सकती हैं।

संकट बढ़ने का खतरा

- ABC सेंटर, नसबंदी व टीकाकरण की व्यवस्था अपर्याप्त
- बड़े पैमाने पर आवारा कुत्तों को रखने की जगह नहीं
- वित्तीय अनियमितता व जानवरों से क्रूरता की शिकायतें

अस्पष्ट आंकड़े । भारत में कुत्तों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर भी उलझन है। अलग-अलग सरकारी रिपोर्ट में अलग आंकड़े मिलते हैं, जिससे सचाई सामने नहीं आ पाती। कई बार एंटी रेबीज वैक्सीन के इस्तेमाल के आंकड़ों को ही डॉग बाइट की घटनाओं का आधार मान लिया जाता है। यह भी पता नहीं चलता कि वे कुत्ते पालतू थे या आवारा।

कमजोर रिपोर्टिंग । यह तब और मुश्किल हो जाता है जब काटने के आंकड़ों को रेबीज से होने वाली मौतों के साथ जोड़ दिया जाता है। क्योंकि, रेबीज से होने वाली मौतों में भी हर साल बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। कई राज्यों में एक भी मौत दर्ज नहीं की जाती और आंकड़ों को अधूरा माना जाता है। 2018 और 2019 की रिपोर्ट में मौतों की संख्या लगभग एक जैसी रही- 116 और 118। इसलिए, विशेषज्ञों को लगता है कि मौतों में दिख रही कमी सुधार नहीं, बल्कि कमजोर रिपोर्टिंग का नतीजा हो सकती है।

नए नियम से चिंता । रेबीज नियंत्रण और कुत्तों की आबादी रोकना दो अलग मुद्दे हैं, पर आमतौर पर इन्हें जोड़कर देखा जाता है। इससे गलत नीतियां बनती हैं। पहले ABC नियमों के तहत नसबंदी और टीकाकरण के बाद सामान्य आवारा कुत्तों को उनके इलाके में दोबारा छोड़ दिया जाता था। अब नई व्यवस्था में ऐसे कुत्तों को भी सार्वजनिक स्थानों और संस्थानों से पूरी तरह हटाया जा सकता है, भले उन्होंने कभी किसी को नुकसान न पहुंचाया हो।

जवाबदेही जरूरी । अब कई आवारा कुत्तों का भविष्य उनके व्यवहार से नहीं, बल्कि उनकी मौजूदगी कहां है, इससे तय होगा। भारत धीरे-धीरे ऐसे मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहां भीड़भाड़ वाले शेल्टर और अधूरी नसबंदी पर जोर है, जबकि असल समस्या जस की तस है। स्थायी समाधान के लिए पारदर्शी डेटा, लगातार टीकाकरण, बेहतर कचरा प्रबंधन, रेबीज के प्रति जागरूकता और सरकारी जवाबदेही जरूरी है, वरना संकट और बढ़ सकता है।

(लेखिका सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े मुद्दों पर शोध करती हैं)

कांटे की बात

यह समझना मुश्किल है कि आखिर कौन-सी मजबूरी सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से रोक रही है? नफरत की राजनीति, मॉब लिंचिंग, गाय के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या और मुसलमानों को बदनाम करने का अभियान अब समाप्त होना चाहिए।

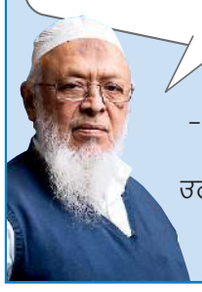
-अरशद मदनी, *जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष*

भारत में ICC की बोर्ड मीटिंग है, इसमें PCB प्रमुख मोहसिन नकवी को भी बुलावा गया है। पाकिस्तान को लगा कि नकवी को IPL फाइनल देखने भी बुलाया जा रहा। फर्ज कीजिए अगर इस गफलत को सच बनाने नकवी जाएं अटल बिहारी वाजपेयी के पास।

नक़वी से पाकिस्तानी मीडिया का प्रैंक

AI Image

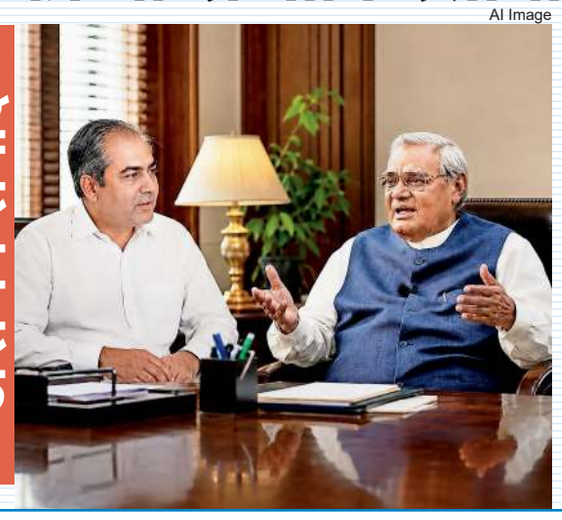

'हया चली जाए तो लफ्ज मीठे भी बेअसर लगते हैं, फिर इंसान सिर्फ चेहरा रह जाता है, किरदार नहीं।' नकवी को तसल्ली न हुई, 'बेहया होने में हमें मसला नहीं। समस्या है कि IPL फाइनल का कॉम्प्लिमेंट्री टिकट उम्मीद बंधाकर नहीं मिला। हमारे मीडिया ने कहा कि जाओ, मैच अच्छे से एंजॉय करना। पर मेल में केवल मीटिंग नोट्स थे।' 'यह अक्लमंदी तो तुम्हारी हुई, हम क्या करें?' 'भावनाएं समझिए। अरमान जाग गए थे कि VIP बॉक्स में बैठ कर मैच देखूंगा, सारे कैमरे मुझ पर होंगे, सभी से बात होगी और टीम इंडिया के साथ कोई सीरीज झटक लूंगा। लेकिन, प्रैंक हो गया। आपने क्रिकेट डिप्लोमेसी की थी, मेरी भी मदद कीजिए।' 'सच्ची हो नीयत तो राह खुलती है, ट्रोफी रखने से कोई विजेता नहीं बनता।' ***-शैलेंद्र पांडेय***

जनता जंक्शन

इरफ़ान

करोलबाग से गायब हो गईं उर्दू और पंजाबी

साड्डी दिल्ली

जब आप मेट्रो स्टेशन से उतरकर करोलबाग में कदम रखते हैं, तो पहली नजर में लगता है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। चारों तरफ खुश चेहरे, हॉकर्स की आवाज, ग्राहकों की भीड़ और बाजार की हलचल। लेकिन, आगे बढ़ने पर बदलाव साफ दिखने लगता है।

विवेक शुक्ला

गायब हुई उर्दू । पुरानी दुकानों के बोर्ड से उर्दू बिल्कुल गायब हो गई है। साल 2000 के शुरू तक उर्दू आम थी। अब वह तो चली गई, पंजाबी भी बहुत कम सुनाई देती है। यहां के ज्यादातर दुकानदार बंटवारे के बाद सरहद पार से आए थे। उनकी मातृभाषा पंजाबी ही थी। अब उसकी जगह हिंदी ने ले ली है। फिर भी करोलबाग और अजमल खान रोड की चमक, गफ्फार मार्केट की धड़कन और संकरी गलियों में कपड़े-जूते-खाने का सामान बेचने वालों की गर्मजोशी मिलकर इस बाजार को खास बनाती है। इसने दिल्ली की कई पीढ़ियों को अनगिनत यादगार लम्हे दिए हैं।

जाम की समस्या । करोलबाग के लिए लंबे समय से पार्किंग समस्या बनी हुई है। शास्त्री पार्क में मल्टी-लेवल पार्किंग प्रॉजेक्ट दशकों से अटका पड़ा है। 500 से ज्यादा गाड़ियों की क्षमता वाला यह प्रॉजेक्ट अगर पूरा हो जाता तो स्थिति बेहतर होती। अभी ट्रैफिक जाम की वजह से लोग यहां आने से बचने लगे हैं।

बंटवारे का इतिहास । देश के बंटवारे तक करोलबाग झाड़ियों और जंगली घास से भरा हुआ इलाका था। यहां आबादी का बड़ा हिस्सा मुसलमानों का था। पाकिस्तानी क्रिकेटर सिकंदर बख्त की फैमिली भी यहीं रहती थी। बंटवारे के बाद करोलबाग की किस्मत बदल गई। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को यहां शरण मिली। मुसलमान इधर से चले गए और उनके घरों में शरणार्थी बस गए। इन्हीं शरणार्थियों में महाशय धर्मपाल गुलाटी भी थे, जो बाद में MDH मसालों के संस्थापक बने।

समावेशी संस्कृति । करोलबाग का मूल स्वभाव हमेशा समावेशी रहा। यहां दक्षिण भारतीय रेस्तरां भी कई थे। अमृता प्रीतम, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता डॉ. हरभजन सिंह, महेंद्र कौर गिल, करतार सिंह दुग्गल, हरनाम सिंह जैसे पंजाबी साहित्य के बड़े हस्ताक्षर साउथ इंडियन कॉफी हाउस में बैठकर बहस करते। हरनाम सिंह के साथ गुलजार भी करोलबाग में रहते थे।

नई शुरुआत । करोलबाग की बहुत-सी नामवर दुकानों की जगह बड़े ब्रैंड्स ने ले ली है, लेकिन यह इलाका सिर्फ शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं, इतिहास की जीती-जागती किताब है। यहां विभाजन के दर्द, हिम्मत और नई शुरुआत की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। राजेश वाच्छर जैसे बुजुर्गों से सुना है कि यहीं आर.के. धवन कंघियां बेचा करते थे, जो बाद में देश के सबसे प्रभावशाली लोगों में शुमार हुए। आर्य समाज रोड पर मॉरीशस के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ भी बार-बार अपने समधी के घर आया करते थे। अब वक्त आ गया है कि करोलबाग को उसकी पुरानी रौनक वापस दिलाई जाए।

सुबह की मीठी नींद आपको कहीं आलसी तो नहीं बना रही

विनोद कुमार यादव

गर्मी की छुट्टियां बच्चों और उनके पैरंट्स के लिए आराम व मनोरंजन का समय मानी जाती हैं, लेकिन यही समय जीवन को नई दिशा देने का अवसर बन सकता है। छुट्टियों में कई लोग अपनी दिनचर्या को अधिक अनुशासित बनाने का संकल्प लेते हैं। सुबह जल्दी उठने, व्यायाम करने, पढ़ने और स्वयं को बेहतर बनाने की योजनाएं बनाई जाती हैं। अलार्म भी लगाया जाता है, उत्साह भी रहता है, लेकिन जैसे ही सुबह की मीठी नींद और आराम सामने आता है, मन बहाने बनाने लगता है, 'आज नहीं, कल।' यही वह क्षण होता है, जब मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु सामने आता है - आलस्य।सुखद और सफल जीवन की राह में तीन बड़ी बाधाएं हैं - असावधानी, अभिमान और आलस्य। असावधानी थोड़ी सतर्कता से दूर हो जाती है और अभिमान समझदारी आने पर समाप्त हो जाता है, लेकिन आलस्य सबसे खतरनाक बाधा है। यह धीरे-धीरे मनुष्य की ऊर्जा, मेहनत करने की इच्छा और आगे बढ़ने के संकल्प को कमजोर कर देता है।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

जब कोई विद्यार्थी पुस्तक लेकर पढ़ने बैठता है, तो कुछ समय बाद उसका मन भटकने लगता है और नींद आंखों पर हावी हो जाती है। इसी तरह, जो व्यक्ति सुबह व्यायाम करना तय करता है, वह अलार्म बजने पर थोड़ी देर और सोने का बहाना ढूंढ़ लेता है। यही 'थोड़ी देर' कई बार घंटों में बदल जाती है और अच्छे संकल्प अधूरे रह जाते हैं।

आलस्य का सबसे बड़ा साथी बहानेबाजी है। आलसी व्यक्ति काम टालता है और असफलता के लिए तरह-तरह के तर्क देता है। धीरे-धीरे वह पुरुषार्थ छोड़कर भाग्य के भरोसे जीने लगता है। सत्य यही है कि सफलता, अच्छा स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति केवल उन्हीं को मिलती है, जो आलस्य पर विजय पाकर अनुशासन और कर्म को अपनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के परिव्राजक जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। यात्रा के दौरान जब भूख, प्यास या शारीरिक कमजोरी उन्हें थका देती थी, तब वह थोड़ी देर विश्राम के बाद फिर उठ खड़े होते थे। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपने संकल्प को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया।

भोजशाला के सच पर अदालत ने लगाई मुहर

लंबे विवाद, पुरातत्व सर्वेक्षण और कानूनी सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि धार की भोजशाला राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला और मंदिर है। अदालत ने वहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया। लेकिन, कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस नेताओं और वामपंथी इतिहासकारों ने सवाल खड़े किए हैं।

शुभम केवलिया

गलत दावा । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह ASI का संरक्षित स्मारक है, इसीलिए यहां पूजा नहीं की जा सकती। हालांकि 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम (AMASR Act) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कानून में स्मारक को नुकसान नहीं पहुंचने की बात कही गई है। देश के कई संरक्षित स्मारकों में आज भी पूजा-अर्चना की जाती है। विश्व धरोहर में शामिल बृहदेश्वर मंदिर भी इसका उदाहरण है।

बॉम्बे गजेटियर में उल्लेख । भोजशाला विवाद से जुड़े सभी दस्तावेज में 1896 में प्रकाशित बंबई गजेटियर का खास महत्व है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि धार में मौजूद मस्जिद उसी स्थान पर बनी है, जहां कभी परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। गजेटियर में यह भी लिखा है कि राजा भोज के बाद उनके वंशज नरवर्मन समेत अन्य शासकों ने इस विद्यालय की देखभाल की। दस्तावेज में एक कुएं का भी जिक्र है, जिसे तब सरस्वती कुआं या अक्ल कुआं कहा जाता था। किंवदंती है कि इसका पानी पीने से बुद्धि बढ़ती है। इस मान्यता से स्पष्ट होता है कि भले ही वहां मस्जिद निर्मित कर दी गई, मगर 1896 तक वहां संस्कृत विद्यालय ही था।

अभिलेख में दर्ज । भोजशाला विवाद में पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। विभाग द्वारा प्रकाशित कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडीकेरम-7 (परमार अभिलेख) में उल्लेख है कि मौजूदा मस्जिद राजा भोज द्वारा बनवाए गए संस्कृत विद्यालय का परिवर्तित स्वरूप है। इस विवाद में केके लेले जैसे पुराविद की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने 1903 के अपने सर्वेक्षण के आधार पर इस स्थान को विद्यालय या मंदिर बताया था।

पुरानी रिपोर्ट । कुछ इतिहासकारों का आरोप है कि ASI विभाग सरकार के प्रभाव में काम करता है। मगर 1984-85 में प्रकाशित विभागीय रिपोर्ट में भोजशाला को मूल रूप से देवी सरस्वती का हिंदू मंदिर बताया गया था, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने करवाया था। रिपोर्ट में इसका भी उल्लेख है कि मौजूदा मस्जिद के उत्तर और पश्चिम भाग में मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद हैं। खास बात यह है कि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। यदि विभाग केवल सरकार के निर्देशों पर काम करता, तो उस दौर में भोजशाला को मंदिर नहीं बताया जाता। अंग्रेजों के समय से लेकर आज तक उपलब्ध कई दस्तावेजों और रिपोर्ट में यही उल्लेख मिलता है कि वहां राजा भोज की संस्कृत पाठशाला और सरस्वती मंदिर था, जिसका बाद में स्वरूप बदला गया। अदालत का फैसला भी इन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर दिया गया है।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य हैं)

रीडर्स मेल

अतिरिक्त बोझ

CBSE को तीन भाषा पढ़ाने का जो फॉर्म्युला 2031 से लागू करना था, वह इसी सत्र से 9वीं और 10वीं कक्षा से लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बच्चे पहले ही सात-सात विषय का बोझ ढो रहे हैं। उन पर यह अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि तीसरी भाषा संस्कृत होगी जो लगभग चलन से बाहर है। दैनिक जीवन में इसका कितना इस्तेमाल होगा, यह देखने वाली बात होगी। यदि इसे लागू करना था, तो पहले इसकी तैयारी निचली कक्षा से होनी चाहिए थी।

गैलेक्सी धिगान, जीटीबी नगर

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। यह समाचार पत्र स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित, आशीष पांडे द्वारा संपादित (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी) तथा मनीष सिन्हा द्वारा, **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, 13/1 & 2, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद (उ.प्र.)** से और नवनीत आहूजा द्वारा, प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर-11, IMT मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122051 से मुद्रित। फोन: 23302000, पंजीकृत कार्यालय: दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क: 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य: सोमवार से शनिवार: नेपाली 5 रु.; रविवार: नेपाली 6 रु.

प्रेरणा

किसी का प्यार पाकर ताकत मिलती है और किसी को प्यार देकर हिम्मत। - लाओ त्जू

संपादकीय

भीषण गर्मी में भी काम करने वालों के बारे में सोचें

केंद्र ने राज्यों को भीषण गर्मी के संकट की तैयारी करने की सलाह दी है यानी शेड, पानी, लू से बीमारों के लिए अस्पतालों में बंदोबस्त आदि। लेकिन यह सलाह बाध्यकारी नहीं है। मौसम विभाग ने सतर्क किया है कि अब हीट वेव अपने रौद्र रूप में होगी, जो मानसून काल में भी जारी रह सकती है। इसका कारण होगा दोनों वेदर पैटर्न्स- एल नीनो (जो मानसून कम करता है) और ला नीना (जो मानसून बढ़ाता है)- का हिन्द महासागर में प्रभाव-परिवर्तन। लू के लम्बे काल तक चलने का मतलब होगा खरीफ पर दुष्प्रभाव। असंगठित क्षेत्र के 48-50 करोड़ कामगारों में से भी कई करोड़ शहरों में रोजी कमाते हैं। नीति आयोग और आर्थिक सर्वे के अनुसार गिग वर्कर्स की संख्या 1.10 करोड़ है जबकि एक निजी आकलन के अनुसार मिश्रित-कर्मियों (जो इसके अलावा भी अन्य काम से आय बढ़ाते हैं) और अन्य फील्ड-सेवाओं में लगे कर्मियों को जोड़ लें तो गिग वर्कर्स 5-6 करोड़ हैं। बहरहाल गिग वर्कर्स की आय इनकी डिलीवरी एल्गोरिदम से जुड़ी होती है यानी इनके स्कूटर का पहिया जितना चलेगा, उतनी ही कमाई होगी। जरा सोचें, दोपहर में जब उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित सुविधाभोगी वर्ग एसी कमरों में भी ठंड से जूझने के लिए आइसक्रीम का आर्डर दे रहा होगा तो उसे पूरा करने के लिए स्कूटी-सवार ये कर्मी 45 डिग्री तामपान और लू के थपेड़ों के बीच डिलीवरी-दर-डिलीवरी भाग रहे होंगे। यही कारण है कि 18वें वित्त आयोग ने दो माह पहले सरकार से हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की सलाह दी थी।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

एक-दूसरे की देह का शोषण काम-ऊर्जा का दुरुपयोग है

अपराध वेश बदलने में बड़ा माहिर होता है। हर दौर में अपराध नई-नई शक्ल लेकर आता है। दार्शनिकों ने कहा है अपराध मिटता नहीं है, छुप जाता है और मौका मिलने पर सामने आ जाता है। आज राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। हमने एक पूर्व प्रधानमंत्री को इस दिन खोया था। आतंकवाद भी अपराध का एक चेहरा है। उस पर तो सरकार जैसे-तैसे काबू पा रही है, लेकिन इन दिनों एक नई शक्ल सामने आ रही है। किशोर और तरुण उम्र के युवक-युवती दैहिक अपराध में लिप्त हो रहे हैं। एक-दूसरे के शरीर का शोषण काम-ऊर्जा का दुरुपयोग है। स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी करनी चाहिए, लेकिन पीड़ा तब हो रही है जब स्त्रियां अपराध के क्षेत्र में भी पुरुषों से बराबरी कर रही हैं। अब तो लड़कियां भी छात्रा के रूप में किसी और की परीक्षा दे देती हैं। ये शिक्षा जगत का बड़ा अपराध है। न्याय-व्यवस्था के भीतर भी द्वंद्व है इस बात को लेकर कि पॉक्सो में 90% केस ऐसे सामने आए, जिसमें युवती की स्वीकृति थी और बाद में उसे अपराध की शक्ल दी गई। ये लक्षण देश के दिव्य देह-स्वरूप पर कोढ़ की तरह हैं। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

शब्दों का जादू

संघर्ष को उपमाएं

बनाऊंगा चींटियों को अपना आदर्श
लगाऊंगा दौड़ गदहों से
क्षितिज के अंतिम छोर तक।
ढूंढकर मारूंगा उस सांप को
जिसने पिया है मेरे हिस्से का अमरत्व।

अपनी कहानी में
खुद को बनाऊंगा एक पंछी
रोज खिलाऊंगा
किसी कौवे को भरपेट खाना
और जतन से बचाऊंगा
संसार में प्रेम।

मैं भी उठाऊंगा बोझ
कांधे पर,
चढ़ूंगा आकाश
डाकूंगा बचा हुआ जीवन
अंत में घोषित करूंगा
अपना नैराश्य।
और अपने संघर्ष को दूंगा
अपनी उपमाएं।

-अमन त्रिपाठी, प्रतापगढ़
(मूल कविता के सम्पादित अंश)

पूरी कविता को पढ़ने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

भास्कर कविता उत्सव की शीर्ष 100 कविताओं में चयनित

पाठकों के पत्र

महिला कानूनों का सख्ती से पालन हो

कड़े कानूनों के बावजूद भी महिला उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लचीली कानून व्यवस्था, पुलिस का उदासीन रवैया, कम सजा दर और फास्ट ट्रैक अदालतों का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। - प्रकाश भगत, चांदपुरा, राजस्थान

विभागीय स्तर पर हों कार्य

हर साल राज्यों में विभागीय परियोजनाओं से जुड़ा बजट खर्च के अभाव में लैप्स होने के समाचार आते हैं। विभागीय अधिकारी सभी परियोजना कार्यों को अपने स्तर पर कराएं तो इनमें विलंब की गुंजाइश कम होगी। ठेकेदारों से सिर्फ श्रमिक, मशीनरी, वाहन किराए पर लिए जा सकते हैं। - मुकेश चौधरी, ईमेल पर

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

'2 अफ्रीका' है सबसे लंबी अंडर-सी केबल

'2 अफ्रीका' केबल दुनिया में समुद्र के नीचे बिछाया गया सबसे लंबा फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क है। यह केबल अपने 46 लैंडिंग स्टेशनों के जरिए भारत समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 33 देशों को आपस में जोड़ती है और उनमें हाई-स्पीड इंटरनेट मुहैया कराती है। दुनिया की 8 दिग्गज टेक कंपनियों ने इसे स्थापित किया है।
45000 किलोमीटर है '2अफ्रीका' केबल की लंबाई।

बामुलाहिजा • भारत के खिलाफ हर युद्ध में हारने के बावजूद पाकिस्तान जीत का दावा करता रहा है...

पाक की नियति बन चुकी है भुलावे में रहना

युद्धनीति

शेखर गुप्ता
एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिन्ट'
@ShekharGupta

भारत के साथ पाकिस्तान के युद्ध का इतिहास कैसा रहा है? सामरिक रूप से ठीक, लेकिन रणनीतिक रूप से नुकसानदायक। यही वजह है कि वह पूरी ताकत से शुरुआत करने के बावजूद हर युद्ध हारता है। लेकिन 1971 और कारगिल युद्ध को छोड़कर उसने ज्यादातर युद्धों में जीत का दावा किया है।

गत वर्ष की 87 घंटे की मुठभेड़ को ही देख लीजिए। मुनीर से लेकर पाकिस्तान की राजनीति के सबसे निचले स्तर तक पूरा पाकिस्तान मानता है कि इस बार जीत उसकी हुई; कि इसके बाद अमेरिका ने उसे फिर गले लगाया और इसे उसकी खुद की घोषित 'जीत' की मंजूरी माना गया। जबकि हकीकत यह है कि पहलगाम हत्याकांड के सिर्फ चार दिन पहले और ऑपरेशन सिंदूर के करीब दो हफ्ते पहले स्टीव विटकॉफ के बेटे जाक का दौरा और क्रिप्टो सौदा हो चुका था।

मुनीर को मालूम था कि भारत पहलगाम का जवाब देगा। इसलिए उन्होंने ट्रम्प परिवार के लालच का फायदा उठाने की चाल पहले ही तैयार कर ली थी। दुनिया में अधिकतर लोगों से पहले इस बात को समझने के लिए आप मुनीर की तारीफ कर सकते हैं या हो सकता है कि सऊदी अरब ने उन्हें पहले ही सावधान कर दिया हो।

लड़ाई शुरू होने से पहले ही उन्होंने ट्रम्प के 'सिस्टम' को अपने पक्ष में कर लिया था। एक हफ्ते पहले, 16 अप्रैल 2025 को विदेश में बसे पाकिस्तानियों को दिए उनके भाषण ने इसका संकेत दे दिया था। वह हत्याकांड भारत की जवाबी कार्रवाई देखने की उनकी योजना का हिस्सा था। ट्रम्प को अपने पक्ष में लाकर कश्मीर मुद्दे को उठाना उनका रणनीतिक लक्ष्य था। पहली चाल सफल रही, लेकिन दूसरी पूरी तरह नाकाम रही।

पाकिस्तान ने यह जानते हुए भारत को उकसाया था कि भारत जवाब में सैन्य कार्रवाई करेगा, इसलिए उसने यह भी अंदाजा लगाया होगा कि किन जगहों को निशाना बनाया जाएगा। वे यह भी जानते थे कि भारत कौन से हथियार इस्तेमाल करेगा। इसलिए भारतीय वायुसेना ने 7 मई की रात 1 बजकर 7 मिनट पर जब उड़ान भरी, तब वे तैयार थे। अपने अंदरूनी इलाकों में निशानों पर हमलों को वे रोक नहीं पाए, लेकिन यह उनका मकसद भी नहीं था। वे जवाब को हवाई मुठभेड़ तक सीमित रखना चाहते थे। एईडब्ल्यू विमानों और जे-10सी, जेएफ-17 के साथ पीएल-15 मिसाइलों को आगे रखकर इस कार्रवाई का पहले से अभ्यास किया गया था। उन्हें कुछ सफलता मिली और वे इसका जश्न मना रहे थे। भारत में उच्च स्तर पर कुछ विमानों के नुकसान की बात मानी गई है। पूर्व सीडीएस ने इसे 'सामरिक गलती' बताया, लेकिन आईएएफ ने हिसाब बराबर करने की योजना बनाई।

सबसे पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस को दबाव में लाने के लिए एंटी-रेडिएशन ड्रोनों से हमला किया गया। और आखिर में पीएएफ के सबसे सुरक्षित हवाई अड्डों पर लगातार हवाई हमले किए गए। पीएएफ का कोई भी विमान, या कितनी भी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल क्यों न हो, जवाब देने के लिए उड़ान नहीं भर सकी।

जब तक पाकिस्तान ने संघर्षविराम की मांग की, तब तक सिर्फ एक पक्ष के पास सबूत थे कि दूसरे पक्ष को कितना नुकसान हुआ है : व्यावसायिक उपग्रहों से मिली तस्वीरें बता रही थीं कि पीएएफ के कम-से-कम 13 हवाई अड्डे और तीन रडार नष्ट हो चुके थे। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी जीत का जश्न मना रहा है। एक भारतीय कमांडर ने कहा यह ऐसा ही था, जैसे भारत ने पाकिस्तान को हॉकी मैच में 3-1 से हरा दिया हो। बात इतनी थी कि उनके सेंटर फॉरवर्ड ने गोल किया और हमारे खिलाड़ियों ने तीन पेनल्टी को गोल में बदल दिया।

हमें नुकसान पहुंचाने के उनके दावों का कोई सबूत नहीं है। भारत के सभी हवाई अड्डों के पास शहर बसे हुए हैं, कुछ भी छिपा नहीं है, लेकिन कोई उपग्रह तस्वीर सामने नहीं आई है। पाकिस्तान के सभी दावे बेकार हैं। बहरहाल, यहां मैं हाल के इतिहास को दोहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपनी मुख्य बात पर जोर दे रहा हूं। वह यह है कि पाकिस्तानी फौजी दिमाग अच्छी तरह सोचता है, लेकिन सिर्फ सामरिक चालों के हिसाब से सोचता है। वह यह अंदाजा नहीं लगा पाता कि भारत किस तरह जवाब देगा। यह अंदरूनी कमजोरी, भारतीय सेना के प्रति अनादर या दोनों का मेल हो सकता है। यह विचार भी हमें पाकिस्तानी लेखक शुजा नवाज की किताब क्रॉस्ड सोर्ड्स से मिला है।

कारगिल युद्ध की बात करते हुए उन्होंने लिखा है कि भारत के साथ 'वार गेम' खेल रही पाकिस्तानी टीम ने बिल्कुल सही अनुमान लगाया था कि वाजपेयी सरकार किस तरह जवाब देगी। अगर उसे गंभीरता से लिया जाता, तो पाकिस्तान हार, पीछे हटने और बेइज्जती से बच सकता था, लेकिन उसका मजाक उड़ाया गया। सामरिक दृष्टि से कारगिल युद्ध शानदार था। धोखा, योजना, गोपनीयता, इलाके का चुनाव और जगह का महत्व, हर लिहाज से शानदार। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो..., भारत ने अगर मुकाबला किया तो? इसके लिए रणनीतिक सोच चाहिए, जिसकी पाकिस्तान में कमी है।

कारगिल इसलिए रणनीतिक हार साबित हुई, क्योंकि इसने नियंत्रण रेखा की वैश्विक मान्यता को मजबूत कर दिया। इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर थोड़ी देर रुकते हुए बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को कैमरे पर कहा था कि इस उपमहाद्वीप के नक्शे पर खींची गई सीमाओं को अब खून से नहीं बदला जा सकता। यह कहानी पहले भी पुरानी लड़ाइयों में दोहराई जा चुकी है। 1965 में छंब पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन जिब्राल्टर और इसके बाद अखनूर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाया गया, ताकि कश्मीर को भारत से काट दिया जाए। पाकिस्तानी सेना ने यह सोच लिया कि भारत कश्मीर छोड़ देगा और भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई पर ठीक से विचार नहीं किया गया। उसी युद्ध में खेमकरण में टैंकों से किया गया अप्रत्याशित हमला इस उपमहाद्वीप के सबसे साहसी हमलों में गिना जाता है। उस युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई पाकिस्तान की हार और उसके बेहतरीन टैंकों के नष्ट होने की थी। पाकिस्तान ने उस युद्ध में भी अपनी जीत का दावा किया था, लेकिन विडंबना यह है कि वह 6 सितंबर को 'डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे' के रूप में मनाता है!

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इतिहास का सबक है...

ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ने गलत सबक लिया है। ऐसे में हमें पाकिस्तान की अगली उकसाने वाली कार्रवाई का अंदाजा पहले ही लगाना होगा। इतिहास बताता है कि जब पाकिस्तानी सत्ता ऐसी स्थिति में पहुंचती है, तब वह सबसे खराब, और खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाले रणनीतिक फैसले करती है।

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

दूरदृष्टि • अमेरिका और चीन में तालमेल जरूरी

दुनिया की दो महाशक्तियों को साथ काम करना होगा

भू-राजनीति

पिनेलोपी गोल्डबर्ग
वर्ल्ड बैंक की पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट और येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर

बीजिंग में डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच हुई समिट में भले ही टैरिफ, ताइवान या ईरान युद्ध जैसे मुद्दों पर कोई निर्णायक चर्चा नहीं हुई हो, फिर भी जिस संयमित और सौहार्दपूर्ण तरीके से वह शिखर-वार्ता सम्पन्न हुई, उसने एक नए, व्यावहारिक दृष्टिकोण का संकेत दिया। इसने बताया कि दोनों महाशक्तियों को अब एक-दूसरे पर गहरी आर्थिक निर्भरता को स्वीकार करना होगा। यह तो स्पष्ट था कि बीजिंग में अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति द्विपक्षीय संबंधों को केवल भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चश्मे से नहीं देख रहे थे।

अगर अमेरिका चीन को एक ताकतवर आर्थिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्वीकार करता है तो इसका मतलब अपने रसूख को कम करना नहीं, बल्कि वास्तविकता का एहसास है। चीन के उदय पर अमेरिका में होने वाली बहसें वर्षों से एक सुपरिचित पैटर्न का पालन करती रही हैं : पहले तो वे इससे इनकार करते हैं, फिर इस पर नाराजी जताते हैं, और फिर अंततः इसे मान बैठते हैं। दोहरे अंकों वाली आर्थिक वृद्धि के युग के दौरान कई अमेरिकी विश्लेषकों ने आधिकारिक चीनी आंकड़ों को अविश्वसनीय या बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया हुआ बताकर खारिज कर दिया था। लेकिन जैसे-जैसे चीन के आर्थिक चमत्कार की अनदेखी करना मुश्किल होता गया, उसकी सफलता का श्रेय उसकी औद्योगिक नीति, बौद्धिक सम्पदा की चोरी और मुद्रा में हेरफेर जैसे अनुचित तौर-तरीकों को दिया जाने लगा।

लेकिन अब उन नैरेटिव को बनाए रखना मुश्किल है, क्योंकि चीन कई रणनीतिक उद्योगों में तकनीकी उत्कर्ष तक पहुंच गया है। सबसे खास बात यह है कि चीनी ईवी निर्माता कम लागत वाले मॉडलों से लेकर तेजी से परिष्कृत प्रीमियम ब्रांडों तक- बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के रूप में उभरे हैं। दवाइयों के क्षेत्र में चीनी फर्में इनोवेटिव हो गई हैं। सेमीकंडक्टर में भी चीन ने एडवांस्ड-चिप्स के उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, हालांकि यह अभी भी टीएसएमसी से पीछे है। ऐसे में चीन की तकनीकी प्रगति को नकारने या उसकी राह में अड़ंगे डालने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अमेरिका को स्वीकार करना चाहिए कि चीनी प्रतिस्पर्धा अब स्थायी रूप से बनी रहने वाली है और आर्थिक सह-अस्तित्व तथा सीमित सहयोग के लिए ढांचे स्थापित करने चाहिए।

ट्रम्प के साथ बीजिंग गए प्रमुख अमेरिकी सीईओ और बिजनेस-लीडर्स ने भी इस संदेश पर जोर दिया कि पूरी तरह से अलग-थलग हो जाना न तो यथार्थवादी होगा और न ही वांछनीय। एक अधिक संभावित मार्ग उस पारस्परिक निर्भरता में है, जो चुनिंदा क्षेत्रों में जारी रहनी चाहिए। शी ने अपनी ओर से थ्यूसीडाइड्स ट्रैप का हवाला देकर द्विपक्षीय संबंधों को परिभाषित किया है। यह शब्द राजनीतिक वैज्ञानिक ग्राहम एलिसन ने उस संघर्ष के खतरे को बताने के लिए गढ़ा था, जिसमें एक उभरती हुई ताकत किसी स्थापित शक्ति को बेदखल करने की चुनौती देती है।

आज अमेरिका और चीन एक जैसी ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं : तीव्र तकनीकी परिवर्तन, एआई, वित्तीय अस्थिरता, सामाजिक विषमता और जलवायु परिवर्तन। इनके समाधान भी उन्हें साथ मिलकर ही खोजने होंगे।

लेकिन अमेरिका के सामने मौजूद कई चुनौतियों के बावजूद उसे एक क्षीण होती ताकत के रूप में बताना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अमेरिका आज भी इनोवेशन और आंत्रप्रेन्योरशिप का दुनिया का अग्रणी केंद्र बना हुआ है, जिसने कंप्यूटिंग और इंटरनेट से लेकर स्मार्टफोन और एआई तक- पिछले सदी की कई परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजी का उत्पादन किया है। कोई भी अन्य देश अमेरिका के वैज्ञानिक नेतृत्व, पूंजी बाजार, उद्यमी संस्कृति और संस्थागत लचीलेपन के संयोजन का मुकाबला नहीं कर सकता। जैसा कि अरबपति निवेशक वॉरेन बफे ने एक बार कहा था, 1776 के बाद से अमेरिका के खिलाफ दांव लगाकर कोई भी कभी सफल नहीं हुआ है। ऐसे में दुनिया को दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता होगी।

(@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)

आधी आबादी • महिलाओं के लिए 'पिंक टिकट'

स्त्रियों के लिए फ्री बस टिकट चैरिटी नहीं, एक जरूरत है...

फेमिनिज्म

मेघना पंत
पुरस्कृत लेखिका, पत्रकार-वक्ता
meghnapant@yahoo.com

शाम होते ही भारत में बस स्टॉप पर खड़ी कोई महिला बस के रूट नंबर से पहले आसमान की ओर झांकने लगती है। इसलिए नहीं कि उसे बारिश की चिंता है, बल्कि इसलिए कि अंधेरे में यहां महिलाओं के लिए हर चीज के मायने बदल जाते हैं। रात को बाहर निकले किसी पुरुष को यहां यात्रा करने वाला एक आम इंसान माना जाता है, लेकिन सूरज ढलने के बाद कोई महिला बाहर निकले तो सवाल उठने लगते हैं। कहां जा रही है? अकेली क्यों है? कौन इंतजार कर रहा है?

इसीलिए बंगाल में हाल ही शुरू की गई महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के प्रावधान वाली योजनाएं अहम हैं। इनकी अहमियत इसलिए नहीं है कि बस का टिकट महंगा होता है, बल्कि इसलिए है कि भारत में महिलाओं के लिए बाहर निकलना आवाजाही की जरूरत से ज्यादा एक भावनात्मक विषय होता है। और यों देखें तो महज 40 रुपए भी लाखों महिलाओं के लिए कर्ज और सम्मान के बीच का फर्क हो सकते हैं।

कोई महिला घर से बाहर महज काम पर जाने के लिए ही नहीं निकलती। वह आत्मनिर्भरता और सम्भावनाओं की ओर भी जा रही हो सकती है। वह बिना किसी की इजाजत दुनिया में अपने अस्तित्व के अधिकार की ओर बढ़ रही हो सकती है। सम्भव है वह शहरभर में दो बसें बदलकर अपनी आर्थराइटिस से पीड़ित मां की देखभाल करने जा रही हो। सम्भवतः शादी के बाद छोड़ दिए गए किसी पाठ्यक्रम में उसका फिर दाखिला हो गया हो। या फिर शायद वो बेहतर कमाई वाली नौकरी के लिए यात्रा कर रही हो। या फिर किसी एब्यूसिव पति से दूर शांति से कुछ घड़ी बिताने अपनी बहन के यहां जा रही हो। और यह भी हो सकता है कि वह ऑफिस के बाद बस चंद पलों के सुकून के लिए समुद्र किनारे बैठ गई हो, क्योंकि घर लौटने पर सिंक भर कर बर्तन तो उसका इंतजार कर ही रहे हैं, जो उसका बिना वेतन वाला काम है।

खैर, बहुतेरे पुरुषों को यह बात समझ नहीं आती, क्योंकि भारत में सार्वजनिक जगहें हमेशा से उन्हीं की मानी गई हैं। आप हर जगह ऐसा देख सकते हैं। वे पूरे फुटपाथ पर वाहन पार्क कर देते हैं। जहां महिलाएं बच्चों की प्राम लेकर चलती हैं, वहां वे बाइक चलाते हैं। शहरों की दीवारों को तो उनमें से कइयों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए पब्लिक टॉयलेट मान ही लिया है। सड़कों, रेलवे स्टेशनों, सीढ़ियों और कोनों में वे अमूमन बिना किसी हिचकिचाहट थूकते-पीकते दिखलाई दे सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर हर तरफ आपको पुरुषों की मौजूदगी के निशान मिलेंगे- बुलंद, बिना किसी संकोच और सवाल के। वहीं महिलाओं को सिखाया जाता है कि खुद को सीमित रखो, आंख मिलाने से बचो, अंधेरा होने से पहले घर लौट आओ।

मुंबई जैसे कुछ शहरों को छोड़ दें- जहां सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की मौजूदगी अपेक्षाकृत सामान्य मानी जाती है- तो आज भी भारत के ज्यादातर शहर शाम छह-सात बजे बाद महिलाओं से खाली होने लगते हैं- अगर उनके साथ कोई पुरुष नहीं है तो। रात को अकेली महिला आज भी असामान्य, या उससे भी बदतर, एक निमंत्रण के जैसी मानी जाती है।

इसलिए जब सरकारें महिलाओं के लिए 'पिंक टिकट' यानी फ्री बस यात्रा जैसी योजनाएं शुरू करती हैं तो यह चैरिटी नहीं होती। यह फ्रीबी नहीं है। यह छोटा, किन्तु क्रान्तिकारी ऐलान है कि महिलाओं को भी आवाजाही का अधिकार है। उन्हें शहरों में रहने और नजर आने का हक है। लेकिन सुरक्षा सिर्फ टिकट तक ही सीमित नहीं हो सकती। पर्याप्त रोशनी वाले बस स्टॉप, सीसीटीवी, महिला कंडक्टर, सुरक्षाकर्मी, पैनिक बटन और अंतिम छोर तक भरोसेमंद कनेक्टिविटी भी चाहिए। क्योंकि अकसर किसी महिला के लिए सबसे जोखिमभरा सफर बस स्टॉप से अकेले घर तक जाना होता है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

किसी शहर की प्रगति इस पर निर्भर करती है कि वहां महिलाएं बिना किसी डर के घूमने-फिरने के लिए कितनी आजाद हैं। इसीलिए बहुत-सी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं भावनात्मक जुड़ाव वाली होती हैं।

डिफ्रेंट एंगल • मितव्ययिता से जीना कोई कमजोरी नहीं और भौतिकता से कुछ दूरी बनाना भी अज्ञानता नहीं...

क्या यह संकट बीतने के बाद भी हम सादगी का सबक याद रखेंगे?

किफायत

नन्दितेश निलय
वक्ता, एथिक्स प्रशिक्षक एवं लेखक
nanditeshnilay@gmail.com

ऊर्जा संकट के बीच देश में विभिन्न क्षेत्रों के लीडर्स अपनी बड़ी कारों और उसके काफिले को छोड़ साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सवारी करते दिखे। 1970 के दशक के दौरान भी वह दौर आया था, जब तेल संकट के बीच संसार के कई देशों में परिवहन व्यस्था में बदलाव आया। तब नीदरलैंड, डेनमार्क और यूरोप के कई देशों में साइकिल-लेन का विस्तार किया गया और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी गई। भारत में भी अब प्रधानमंत्री ने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने, मेट्रो और बसों का उपयोग करने या साइकिल चलाने का आग्रह किया है।

लेकिन यह बदलाव सिर्फ थोड़े समय के लिए है या यह भविष्य में इस देश का परिवहन-व्यवहार भी बन जाएगा? यह जो वीआईपी कल्चर है और जो गाड़ियों के काफिले धूल उड़ाते भागते हैं, क्या उनकी गति कुछ धीमी हो पाएगी? आखिर हमें मानना पड़ेगा कि वो सारे लोग जो अभी तक बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलते रहे, उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उपयोग में लाने से कोई गुरेज नहीं और न ही अपने प्राइवेट जेट को छोड़ आम उड़ान भरने से। यह कितना संतोषजनक होगा कि खास लोग भी आम लोगों की तरह घर से ऑफिस का सफर कर सकते हों और उन्हें किसी तरह का विशिष्टता-बोध नहीं हो।

लेकिन जिस दिन युद्ध रुकेगा, जिस दिन होर्मुज जहाजों को हंसते-हंसते विदा करेगा, क्या उसके बाद भी सफर का साधन वही साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा? क्या 'ऑस्टेरिटी' (मितव्ययिता) एक तात्कालिक बदलाव का ही पहलू नहीं बनेगा, बल्कि वह जीवन जीने का आचरण भी बन पाएगा? ऑस्टेरिटी को दो अर्थों में समझा जाता है- पहला जीवन-शैली के रूप में और दूसरा आर्थिक नीति के अर्थ में। जीवन-शैली के रूप में ऑस्टेरिटी का अर्थ हिंदी में सादगी, तपस्या, संयम और कठोरता जैसे गुण हैं। यानी भौतिक सुखों, फिजूल के खर्च और जरूरत से ज्यादा आराम को छोड़कर सादा जीवन जीना। आर्थिक संदर्भ में अगर हम देखें तो ऑस्टेरिटी का तात्पर्य यह है कि खर्च कम किया जाए और जो खर्च कर रहे हैं, उनमें भी कटौती की गुंजाइश रहे। लेकिन युद्ध के समाप्त होने के बाद ऑस्टेरिटी का कौन-सा अर्थ समाज में प्रासंगिक रह जाएगा? क्या हम जीवन को सादगी से जीने की कोशिश करेंगे और अपनी आदतों में अत्यधिक भौतिक सुखों और खर्चों से बचेंगे?

खैर, कोई भी संकट सकारात्मक बदलाव की गुंजाइश तो पैदा करता ही है। कोविड के समय हमने यह महसूस किया कि उपभोक्ता बना व्यक्ति कैसे अपने आप को उस मितव्ययिता के साथ रखना चाह रहा था, जो सादगी और संयम से तो निर्देशित हो ही रही थी, साथ-साथ हर तरह के आर्थिक आकर्षण से भी कोसों दूर थी। जीने की जिजीविषा थी और जीना एक साहसिक कार्य ही माना गया। वह दौर तमाम तरह के इंफ्लुएंसर्स को दिन-रात सुनता रहा और खुद को मोटिवेट भी करता रहा। कारें गैरेज में खड़ी रहीं और कभी-कभार गर कुछ घुमा तो वह साइकिल का पहिया ही था।

आज फिर हमारे देश में हर उस व्यक्ति के लिए यह एक मौका है कि वह भविष्य में भी अपने आप को उस मितव्ययिता के इर्द-गिर्द रखें। क्योंकि कहा जाता है कि हर बादल में चांदी की रेखा होती है। यह कितना कमाल का दृश्य होगा, जब तेल संकट के समाप्त होने के बाद भी एक आमजन की तरह लीडर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी साइकिल से आते-जाते दिखेंगे। किसी बड़ी कंपनी के चेयरमैन भी कभी मेट्रो में बैठे दिख जाएंगे। यह भी देखना संतोषजनक होगा कि संसाधनों में शक्ति ढूंढता समाज वास्तविक शक्ति सादगी वाली जीवनशैली में पा रहा होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

बिज़नेस भास्कर

Business Standard और TheEconomist की खबरों के साथ

नई दिल्ली, गुरुवार 21 मई , 2026

बिजनेस ब्रीफ

रुपया: 9वें दिन कमजोर, 97 प्रति डॉलर के करीब

मुंबई | पश्चिम एशिया संकट के चलते कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में उछाल से रुपया बुधवार को लगातार नौवें दिन कमजोर हुआ। यह गिरकर 96.83 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। इस बीच डॉलर इंडेक्स 99.42 पर और ब्रेंट क्रूड 109.95 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। विश्लेषकों के मुताबिक, अमेरिका में महंगाई की आशंका और ब्याज दर घटने की उम्मीदों पर पानी फिरने से रुपए पर दबाव बना रहेगा।

डार्क स्टोर बढ़े, जीएसटी के नियमों में ढील देने पर काम

नई दिल्ली| क्विक कॉमर्स कंपनियों के तेजी से फैलते डार्क स्टोर नेटवर्क ने जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। वित्त मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर हर नए डार्क स्टोर के लिए अलग पंजीयन संशोधन की अनिवार्यता में ढील देने पर विचार कर रहा है। अभी एक ही राज्य में हर नए गोदाम या डार्क स्टोर को जीएसटीआईएन में अतिरिक्त व्यापार स्थान के रूप में जोड़ना पड़ता है।

भारत की विकास दर 6.4% रह सकती है: संयुक्त राष्ट्र

नई दिल्ली| संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से घटाकर 6.4% कर दिया है। यूएन डेसा की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान संकट से तेल-गैस आयात महंगा हुआ है। भारत बड़ा एनर्जी आयातक होने के कारण इन झटकों से अछूता नहीं है। लेकिन घरेलू मांग, सरकारी निवेश और सर्विस निर्यात बढ़ने से वह दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बना हुआ है।

हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर इसी साल चालू होगा

हैदराबाद| भारत में माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर इसी साल जून तक चालू हो सकता है। हैदराबाद में बन रही यह सुविधा भारत में कंपनी के ₹1.6 लाख करोड़ निवेश का हिस्सा है। इन्फोसिस, टीसीएस और कॉग्निजेंट जैसी बड़ी भारतीय आईटी कंपनियां पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के कॉपिलॉट के 50,000-50,000 लाइसेंस ले चुकी हैं। कंपनी भारत में 22,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ काम कर रही है।

देश में इस साल दोपहिया बिक्री 5% तक बढ़ेगी: इक्रा

मुंबई| क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इक्रा ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत में दोपहिया की बिक्री 3-5% बढ़ने का अनुमान लगाया है। अप्रैल में बिक्री 29% बढ़कर 19 लाख दोपहिया हो गई। बीते महीने इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री 68% बढ़कर 1.54 लाख यूनिट और बाजार में पैठ 8% तक पहुंच गई। हालांकि कमजोर मानसून के अनुमान और कच्चे माल की बढ़ती महंगाई जोखिम बढ़ा रही है।

एसेट क्लास • गिरते शेयर बाजार में बुलियन मार्केट बना निवेशकों का सबसे मजबूत सहारा

चांदी नंबर-1 निवेश: एक साल में 179% रिटर्न, सोने का भी 69%, लेकिन शेयरों से 8% नुकसान

भास्कर न्यूज | मुंबई

चांदी निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद एसेट क्लास बन गई है। बीते एक साल में चांदी का रिटर्न सोने के मुकाबले ढाई गुना रहा है, जबकि इक्विटी (जैसे शेयर) में निवेश से नुकसान हुआ है। 19 मई 2025 से लेकर 20 मई 2026 के बीच चांदी ने रिटर्न 179% और सोने ने 69% रिटर्न दिया है। दूसरी तरफ सेंसेक्स में 8% गिरावट आई है।

हालांकि 2026 में अब सोने का रिटर्न चांदी से ज्यादा रहा है। आईबीजेए के आंकड़ों के मुताबिक, 31 दिसंबर से लेकर अब तक सोने के रिटर्न 19% रिटर्न के मुकाबले चांदी का रिटर्न 16% रहा। लेकिन इस दौरान सेंसेक्स -11.6% टूट गया। विश्लेषकों के मुताबिक गोल्ड-टू-सिल्वर रेशियो अब 50 के करीब आ गया है। इसका मतलब है कि आगामी महीनों में एक बार फिर चांदी कीमतें सोने के मुकाबले ज्यादा बढ़ने की संभावना है। यानी चांदी का रिटर्न ज्यादा रह सकता है। इसके उलट इक्विटी विश्लेषकों को शेयर बाजार में जल्द तेजी लौटने की उम्मीद कम है। सोना अब भी रिकॉर्ड लेवल से 9.6% और चांदी 30% कम भाव पर है।

भास्कर एनालिसिस

चांदी: 1 साल में निवेशकों की पूंजी ढाई गुना से ज्यादा हो गई

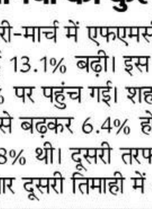

एसेट क्लास	19 मई-25	20 मई-26	रिटर्न
सोना	₹93,785	₹1,58,555	+69%
चांदी	₹95,755	₹2,67,302	+179%
सेंसेक्स	82,059	75,318	-8.21%

सोना: 2026 में अब तक चांदी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मिला

एसेट क्लास	31 दिसंबर-25	20 मई-26	रिटर्न
सोना	₹1,33,195	₹1,58,555	+19%
चांदी	₹2,30,420	₹2,67,302	+16%
सेंसेक्स	85,220.6	75,318	-11.6%

(सोना: प्रति 10 ग्राम, चांदी: प्रति किलो, • स्रोत: आईबीजेए, बीएसई)

चांदी एक बार फिर रिटर्न में सोने को मात दे सकती है

बुलियन मार्केट में गोल्ड-टू-सिल्वर रेशियो पर नजर रखी जाती है। अभी यह रेशियो 54.35:1 पर आ गया है। यानी एक किलो सोने के बदले 54.35 किलो चांदी मिल रही है। पिछले साल यह रेशियो 100:1 के आसपास था। यानी तब एक किलो सोना खरीदने के लिए 100 किलो से ज्यादा चांदी की जरूरत थी।

गोल्ड-टू-सिल्वर रेशियो घटने का आखिर मतलब है क्या...

- सोने के मुकाबले चांदी के फंडामेंटल्स अधिक मजबूत दिख रहे।
- गोल्ड-टू-सिल्वर रेशियो यदि आगे भी 54 के नीचे बना रहा तो चांदी में सोने से ज्यादा तेजी आएगी।
- यह रेशियो 40:1 तक आ सकता है, ऐसे में चांदी में उछाल आएगा।
- इसके 58 के ऊपर जाने पर चांदी की तेजी थम सकती है।

भास्कर नॉलेज

चांदी की सप्लाई में कमी इसे बेस्ट एसेट क्लास बना रही

1. चांदी कीमती धातु के तौर पर एसेट क्लास के साथ ही औद्योगिक धातु भी है, इसलिए दोतरफा मांग
2. सालाना खपत में 60% हिस्सेदारी सोलर पैनल, ईवी और सेमीकंडक्टर की
3. 2021 से ही सप्लाई डिमांड से कम, 2026 लगातार छठा ऐसा साल है
4. ग्रीन एनर्जी की डिमांड से चांदी की औद्योगिक मांग लगातार तेज हो रही

भास्कर एक्सपर्ट

कायनात चैनवाला, एवीपी-कमोडिटी रिसर्च, कोटक सिक्युरिटीज

माहौल चांदी में तेजी के पक्ष में

अमेरिका में महंगाई दर 3.8% रही, जो मई 2023 के बाद सबसे ऊंची है। इस बीच ट्रेजरी यील्ड 16 महीने के ऊंचे स्तर 4.7% पर पहुंच गई है। इस लिहाल से ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी केंद्रीय बैंक की सख्ती बनी रहेगी। गोल्ड मार्केट के लिए ये नकारात्मक हैं। ऐसे में चांदी का प्रदर्शन सोने से बेहतर रह सकता है।

परेशानी • रिपोर्टेड आय हमेशा खपत और बचत से कम निकली

75 साल बाद पहला आय सर्वे, पर 95% लोग बताने को तैयार नहीं

हिमांशी भारद्वाज | नई दिल्ली

सरकार ने 75 साल में पहली बार समर्पित घरेलू आय सर्वे शुरू किया है। लेकिन 95% लोग आय बताने में असहज हैं। अनौपचारिक रोजगार की जटिलता इसे सबसे मुश्किल सांख्यिकीय काम बना रही है।

राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण (एनएचआईएस) 2026 अप्रैल में शुरू हो चुका है। यह मार्च 2027 तक 4.5 लाख घरों में चलेगा। यह एनएसओ का पहला समर्पित आय सर्वेक्षण है। 1950 से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ने खपत, रोजगार, स्वास्थ्य - सब मापा, पर आय की सही तस्वीर हमेशा गायब रही। जब भी घरों की रिपोर्टेड आय जोड़ी गई, वह खपत और बचत के जोड़ से कम निकली। एनएचआईएस- 2026 कंप्यूटर-आधारित इंटरव्यू, 11 आय श्रेणियों और अंतरराष्ट्रीय मॉडलों के जरिए इस खाई को पाटने की कोशिश है।

सर्वे एक नजर में

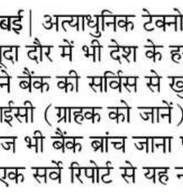

- **कवरेज:** 4.5 लाख घर
- **अवधि:** अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक
- **आय श्रेणियां:** 11 (वेतन से लेकर लाभांश तक)
- **प्रति घर समय:** 100 मिनट (औसत प्री-टेस्टिंग में)

सबसे बड़ी चुनौती: परिवारों के बीच खर्च ज्यादा, आय कम बताने का ट्रेंड

95% ने सर्वेक्षण को संवेदनशील बताया, आय से जुड़े सवालों का जवाब देने से इनकार किया।

22% को ही सर्वेक्षण का उद्देश्य ठीक से समझ में आया

45% को सवाल स्वाभाविक भी लगे।

- ग्रामीण और शहरी, परिवारों में घर खर्च ज्यादा और आय कम बताने की प्रवृत्ति है।
- गेटेड कॉलोनियों, अमीर तबके से डेटा मिलना मुश्किल, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से संपर्क की सिफारिश।

(स्रोत: एनएचआईएस- 2026 की प्री-टेस्टिंग रिपोर्ट)

*अगर हम निम्न और मध्यम वर्ग की आय का उचित अनुमान लगा सकें तो वह पर्याप्त होगा। ज्यादा आय वाले वर्ग का डेटा आयकर रिकॉर्ड से जोड़ा जा सकता है। – **प्रणब सेन**, पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद, केंद्र सरकार*

*मुझे नहीं लगता यह सर्वेक्षण आय वितरण के लिए ज्यादा सटीक होगा। आय के मामले में असमानता बढ़ी है। उच्च आय वर्ग को सही तरीके से कैप्चर करना संदिग्ध है। – **पीसी मोहनन**, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग*

एफएमसीजी • जनवरी-मार्च में शहरों में डिमांड 6.4% बढ़ी

पर्सनल, हाउसहोल्ड केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड अब सबसे ज्यादा बढ़ रही

शार्लिन डिसूज़ा | मुंबई

देश में इस साल पर्सनल, हाउसहोल्ड केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ रही है। 'वर्ल्डपैनल बाय न्यूमरेटर' की रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 में पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की खपत 3-5% और हाउसहोल्ड केयर प्रोडक्ट्स की 4-5% बढ़ सकती है। नए परिवारों के बीच वॉशिंग लिक्विड, फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। फर्श और टॉयलेट क्लीनर की बिक्री भी मामूली उतार-चढ़ाव के बाद लगातार बढ़ रही है।

साबुन, तेल, बिस्किट जैसे रोजाना इस्तेमाल के सामान (एफएमसीजी) की कुल खपत इस साल 5% तक बढ़ सकती है। यह कच्चे तेल के दाम 80-85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास स्थिर रहने और बेहतर मानसून पर निर्भर करेगी। अभी सामान महंगा होने से लोगों की जेब से कुल खर्च तो ज्यादा हो रहा है, पर घरों में आने वाले सामान की मात्रा कम बढ़ी है। हालांकि, कंपनियों द्वारा सीधे दाम न बढ़ाने से खपत और खर्च के बीच का यह अंतर धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद जताई गई है।

रेवेन्यू: जनवरी-मार्च में एफएमसीजी कंपनियों की कुल कमाई 13% बढ़ी

जनवरी-मार्च में एफएमसीजी कंपनियों की कुल कमाई 13.1% बढ़ी। इस दौरान कुल खपत बढ़कर 5.4% पर पहुंच गई। शहरी इलाकों में मांग ज्यादा तेजी से बढ़कर 6.4% हो गई, जो दिसंबर तिमाही में 4.8% थी। दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में मांग लगातार दूसरी तिमाही में 4% से ऊपर बनी हुई है।

डिमांड: फूड प्रोडक्ट्स की ग्रोथ सुस्त, इस साल 4 फीसदी रहने का अनुमान

फूड्स सेगमेंट की बिक्री इस साल 3-4% बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक, जरूरी राशन से सामान की कुल खपत तो बढ़ेगी, पर इसमें उछाल की गुंजाइश कम है। चॉकलेट, स्नैक्स जैसी चीजें लोग अब कम अंतराल पर खरीद रहे हैं। गर्मी और कम बारिश से सॉफ्ट ड्रिंक्स की बिक्री बढ़ सकती है।

जोखिम: कच्चा तेल और महंगा हुआ बढ़ेंगे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के दाम

कच्चा तेल महंगा होने पर खपत वृद्धि 4.5% तक सिमट सकती है। ऐसे में कंपनियां एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा सकती हैं। महंगाई बढ़ने से लोग सोच-समझकर खरीदारी करेंगे। अगर ईंधन के साथ खराब मौसम से खाने-पीने की चीजें भी महंगी हुईं, तो खपत घटकर 3 से 4% रह जाएगी।

टोक्यो से न्यूयॉर्क सिर्फ पौने दो घंटे में... अभी लगते हैं 14 घंटे

जापान ने किया आवाज से 5 गुना तेज उड़ने वाले एयरक्राफ्ट इंजन का सफल लैब टेस्ट

टोक्यो| एविएशन सेक्टर में दुनिया को चौंकाते हुए जापान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अंतरिक्ष एजेंसी 'जाक्सा' ने लैब के भीतर एक ऐसे नए इंजन का सफल परीक्षण किया है, जो भविष्य में ध्वनि से पांच गुना तेज (मैक-5) यानी 6,125 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्री विमान उड़ाने की राह निकालेगा। इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की मदद से टोक्यो से न्यूयॉर्क के बीच 10,830 किलोमीटर का सफर महज 1 घंटे 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। अभी इसमें 14 घंटे से ज्यादा लगते हैं। यह रफ्तार अमेरिकी कंपनी बूम सुपरसोनिक के आने वाले 'ओवरचर' विमान से भी तीन गुना ज्यादा तेज है।

1,000 डिग्री गर्मी झेलने में सक्षम

लैब में विमान के ढांचे को 1,000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर परखा गया। इसमें इसके अंदरूनी हिस्से और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित रहे।

क्या है तकनीक: विमान में कोई घूमने वाला पंखा नहीं होता। इसकी की रफ्तार हवा को दबाती है। तेज हवा लिक्विड हाइड्रोजन ईंधन के साथ मिलती है। धमाके से इंजन को ताकत मिलती है।

बिजनेस इंफो

देश में हर चार में 3 खातेदार बैंकों की सर्विस से खुश नहीं

मुंबई| अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी (जैसे एआई) के मौजूदा दौर में भी देश के हर 4 में से 3 ग्राहक अपने-अपने बैंक की सर्विस से खुश नहीं हैं। आम लोगों को केवाईसी (ग्राहक को जानें), कागजी कार्रवाई के लिए आज भी बैंक ब्रांच जाना पड़ता है। ईवाई इंडिया की एक सर्वे रिपोर्ट से यह नतीजा निकाला गया है।

अनुभव: बैंकिंग सर्विस पर राय

25% ने कहा- अनुभव बेहतरीन

75% ने कहा- अनुभव बहुत अच्छा नहीं

संतुष्टि: अकाउंट खोलना आसान

महिला वर्ग	बुजुर्ग वर्ग	युवा वर्ग
94%	93%	68%

युवा पेशेवर भी नियमित जा रहे बैंक

37%	शहरी पेशेवर
33%	ग्रामीण पेशेवर
9%	महत्वाकांक्षी पेशेवर

युवाओं को अब भी ये दिक्कतें

- खाता खोलने के लिए शाखा बुलाना
- लंबी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया
- ज्यादा पेपर वर्क

भरोसा: 40-55 साल के ग्राहक ब्रांच जाते हैं

ग्राहक वर्ग	ब्रांच जाने का कारण	कितने
ग्रामीण ग्राहक	जमा-निकासी	56%
संपन्न शहरी	बुनियादी काम	52%
वर्किंग वुमन	नियमित सेवाएं	45%

डिजिटल: एप पर भरोसा, चैटबॉट से दूरी

ग्राहक वर्ग	संतुष्टि का स्तर	कितने
संपन्न शहरी	सर्वश्रेष्ठ एप अनुभव	79%
महत्वाकांक्षी युवा	बेहतर मोबाइल बैंकिंग	74%
युवा प्रोफेशनल	बेहतर एप संतुष्टि	74%

भविष्य: एआई की सलाह मानने को तैयार

ग्राहक वर्ग	बैंकिंग में एआई पर राय	कितने
महिला	एआई चैटबॉट से सहज	73%
कारोबारी	एआई वित्तीय सलाह पसंद	51%
युवा	एआई बजटिंग टूल पसंद	49%

प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए ये जरूरी...

1. ग्राहकों के प्रति सहानुभूति रखना 2. सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना 3. ग्राहकों को हर स्तर पर उनकी जरूरतों के मुताबिक सुविधाएं देना 4. ग्राहकों के सशक्तीकरण के लिए पर्याप्त कदम उठाना 5. ग्राहकों की हर बात पर गौर करना।

(स्रोत: ईवाई)

ये रिस्की • अधूरी मरम्मत पर उड़ानों की मंजूरी

लापरवाही पर सख्ती, विमानों की फिटनेस जांच 35% बढ़ी

एम. रियाज हाशमी | नई दिल्ली

डीजीसीए ने इस साल विमानों की निगरानी के लिए 5,435 जांचें तय की हैं। यह 2025 के 4,630 और 2024 के 4,027 से 35% ज्यादा है। लेकिन डीजीसीए जिन खतरों पर नजर रखने की बात कर रहा है, वे 3 साल से जारी हैं। लेकिन सुधार नहीं हुआ। रात में अधूरी मरम्मत के बाद विमान को उड़ान भरने की मंजूरी इनमें शामिल है। अहमदाबाद हादसे ने इस खामी की गहराई दिखाई। संसद में दिए सरकारी जवाब से पता चला कि दुर्घटनाग्रस्त उड़ान ए1-171 से पहले उसी विमान की पिछली उड़ान की तकनीकी लॉगबुक में स्टेबलाइजर सेंसर में खराबी दर्ज गई थी। प्रक्रिया के तहत उसे ठीक करके विमान उड़ाया गया।

रात में विमानों की औचक जांच अब अनिवार्य

अब हर महीने 'नाइट सर्विलांस' अनिवार्य किया गया है, ताकि रात में अधूरी प्रक्रियाओं से विमान न उड़ाए जाएं। सीमित खराबी के बावजूद अस्थायी उड़ान की अनुमति के प्रावधान के दुरुपयोग पर भी फोकस है। गंभीर उल्लंघन पर लाइसेंस का निलंबन भी हो सकता है।

आरबीआई आज बैंकिंग सिस्टम में 1.25 लाख करोड़ कैश डालेगा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में नकदी की स्थिति बेहतर बनाने के लिए गुरुवार को ओवरनाइट वेरिएबल रेट रेपो (वीआरआर) की नीलामी करेगा। इसके जरिए आरबीआई बैंकों में 1.25 लाख करोड़ रुपए का कैश डालेगा। बहरहाल बुधवार को हुई वीआरआर नीलामी में सिर्फ 16,435 करोड़ रुपए की बोली लगी, जबकि अधिसूचित राशि 1.5 लाख करोड़ रुपए थी। मंगलवार तक की स्थिति के मुताबिक, देश के बैंकिंग सिस्टम में 1.50 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस कैश था। इसके चलते वेटेड एवरेज कॉल रेट 5.24% के स्तर पर आ गया, जो रेपो रेट 5.25% से थोड़ा नीचे है। वीआरआर नीलामी के माध्यम से बैंक सरकारी बॉन्ड के बदले बाजार दर पर आरबीआई से उधार ले सकते हैं। रिजर्व बैंक इन ऑपरेशंस के जरिए वेटेड एवरेज कॉल रेट को रेपो रेट के करीब बनाए रखता है। इससे बैंकों और ग्राहकों के लिए लोन लेना-देना आसान हो जाता है।

अब बनने से पहले ही 'कार्टेल' पकड़ने की तैयारी कर रहा कैग

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) सरकारी खरीद में मिलीभगत और बाजार में प्रतिस्पर्धा बिगाड़ने जैसी गतिविधियों पर शुरुआती स्तर पर ही रोक लगाना चाहता है। इसके कैग ने प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के साथ ज्यादा मजबूत संस्थागत सहयोग की जरूरत बताई है। सीसीआई के सालाना कार्यक्रम में कैग संजय मूर्ति ने कहा कि ऑडिट और प्रतिस्पर्धा कानून का प्रवर्तन अलग-अलग नहीं, बल्कि एक-दूसरे को मजबूत करने वाले उपकरण हैं। इनका संयुक्त इस्तेमाल सार्वजनिक धन की सुरक्षा और बाजार की निष्पक्षता बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद में कीमत तय करने या बिड रिगिंग करने वाले आपूर्तिकर्ता सिर्फ प्रतिस्पर्धा कानून नहीं तोड़ते, बल्कि सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मामलों की जल्द पहचान से सार्वजनिक संसाधनों की बेहतर सुरक्षा संभव है।

आईपीओ: इस महीने 13 छोटी कंपनियों के इश्यू, बड़ी गायब

भास्कर न्यूज | मुंबई

देश के आईपीओ बाजार में नया ट्रेंड देखा जा रहा है। ज्यादातर बड़ी कंपनियों ने आईपीओ टाल दिया है, लेकिन छोटी कंपनियां (एसएमई) आगे बढ़ रही हैं। मार्च और अप्रैल में क्रमशः 9 और 4 एसएमई लिस्टिंग के बाद मई में यह संख्या 13 तक पहुंचने की उम्मीद है। दो आईपीओ अभी सब्सक्रिप्शन के लिए खुले हैं और करीब आधा दर्जन पब्लिक इश्यू अभी पाइपलाइन में हैं। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, मेनबोर्ड पर बड़ी कंपनियों की गैरमौजूदगी ने छोटी कंपनियों को लिस्टिंग योजनाएं आगे बढ़ाने का मौका दिया। बड़ी कंपनियों को संस्थागत भागीदारी और बाजार की स्थिरता चाहिए, जो अभी दुर्लभ है। एसएमई आईपीओ का आकार छोटा होता है, इनका निवेशक आधार मुख्यतः रिटेल है और अधिकांश इश्यू पूरी तरह ताजा पूंजी जुटाने के लिए हैं, न कि मौजूदा निवेशकों की एग्जिट के लिए। यह किसी भी आईपीओ के अच्छा होने का संकेत होता है।

बिजनेस एंकर 15-30 वर्ष उम्र वाली नई पीढ़ी बीमारी से पहले ही उसका समाधान तलाशने के प्रयास में

बीमारी नहीं, लाइफस्टाइल का इलाज, दवा बाजार को नई शक्ल दे रही जेन जी, देश की पूरी आबादी में इनकी हिस्सेदारी 26 फीसदी

संकेत कौल | नई दिल्ली

पहले दवा बाजार में मांग अक्सर बीमारी तय करती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। देश की जेन जी (करीब 15-30 वर्ष) फिटनेस, लुक्स, वेलनेस और सुविधा को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य संबंधी फैसले कर रही है। यही वजह है कि फार्मा इंडस्ट्री में ऐसी थेरेपी तेजी से बढ़ रही हैं, जिनका संबंध मोटापा, त्वचा, आंखें, ओरल हेल्थ और लाइफस्टाइल से है।

भारत की आबादी में करीब 26% हिस्सेदारी वाली जेन जी इलाज का इंतजार करने के बजाय पहले से समाधान खोजने की कोशिश कर रही है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन हेल्थ प्लेटफॉर्म्स ने इस बदलाव की रफ्तार तेज कर दी है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बढ़ता स्क्रीन टाइम आंखों से जुड़ी दवाओं की मांग बढ़ा रहा है। वहीं, सोशल मीडिया पर दिखने वाले ब्यूटी ट्रेंड्स और फौरन नतीजे की चाह एंटी-ओबेसिटी और डर्मेटोलॉजी से जुड़ी दवाओं की खपत बढ़ा रही है। फार्मरैक की कमर्शियल वाइस प्रेसिडेंट शीतल सपाले का कहना है कि प्रदूषण और इंस्टाग्राम से प्रभावित ब्यूटी कल्चर के कारण डर्मेटोलॉजी और रेस्पिरेटरी दवाओं की खपत में जेन जी की हिस्सेदारी 25% से ज्यादा हो गई है। खान-पान की आदतें बदलने का भी असर दिखा रहा है। फूड डिलीवरी पर बढ़ती निर्भरता से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण और जंक फूड से जुड़ी फैटी लिवर जैसी बीमारियों ने एंटी-इन्फेक्टिव और लीवर प्रोटेक्शन थेरेपी की मांग बढ़ाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पीढ़ी फार्मा बाजार को केवल डॉक्टर-आधारित नहीं रहने दे रही। इसे मांग-आधारित बना रही है। क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन फार्मेसी के बढ़ने से युवा जल्द समाधान चाहते हैं और इलाज के फैसलों में पहले से ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली स्थित सीके बिड़ला हॉस्पिटल की इंटरनल मेडिसिन डायरेक्टर मनीषा अरोड़ा कहती हैं, 'जेन जी इंटरनेट पर सहज है। इसी वजह से सेल्फ-मेडिकेशन का ट्रेंड नजर आ रहा है। नियमित जांच के बजाय वर्चुअल कंसल्टेशन और ई-प्रिस्क्रिप्शन को प्राथमिकता दी जा रही है।'

हालांकि विशेषज्ञ चेताते हैं कि सुविधा आधारित यह हेल्थ मॉडल लंबे समय में जोखिम बढ़ा सकता है। अभी कार्डियक (दिल से जुड़ी बीमारियां) और एंटी-डायबिटीज (मोटापे) जैसी थेरेपी में इस समूह की हिस्सेदारी कम है, पर उम्र बढ़ने के साथ इसमें तेजी आने की संभावना है।

स्वास्थ्य को लेकर जागरूक, पर जांच से दूरी

जेन जी मानसिक स्वास्थ्य और वेलनेस को लेकर पहले की पीढ़ियों से ज्यादा सक्रिय नजर आती है, लेकिन नियमित हेल्थ जांच में पीछे है। मैकिंजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ 47% जेन जी सालाना वेलनेस विजिट कराते हैं, जबकि कुल औसत करीब 72% है। डॉक्टरों के अनुसार, कई युवा नियमित सामान्य डॉक्टर भी नहीं रखते। ये मैमोग्राम, गायनाकोलॉजिकल जांच, वैक्सीनेशन और फिजिकल टेस्ट जैसे प्रिवेंटिव चेकअप अमूमन टाल देते हैं।

ग्रोथ • जनवरी-मार्च में बकाया गोल्ड लोन 50% बढ़कर 18 लाख करोड़

सोने के सहारे बढ़ा रिटेल क्रेडिट, ग्रोथ में पर्सनल लोन को पीछे छोड़ गया गोल्ड लोन

सुब्रत पांडा | मुंबई

रिटेल लोन के घरेलू बाजार में बीते वित्त वर्ष बड़ा बदलाव आया। बैंकों और फाइनेंस कंपनियों का झुकाव असुरक्षित लोन की बजाय सुरक्षित (सिक्योर्ड) कर्ज की तरफ बढ़ा और गोल्ड लोन सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट बनकर उभरा। क्रिफ हाई मार्क की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 तक कुल रिटेल बकाया कर्ज 16.6% बढ़कर 170.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें कंजम्पशन लोन 15.3% बढ़कर 118.6 लाख करोड़ रुपए रहा। गोल्ड लोन ने सबसे मजबूत प्रदर्शन किया। इसका बकाया 50.4% बढ़कर 18.6 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसने पर्सनल लोन को पीछे छोड़ते हुए होम लोन के बाद दूसरा सबसे बड़ा रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट का दर्जा हासिल कर लिया। सोने की बढ़ती कीमतों से गिरवी मूल्य बढ़ा और औसत टिकट साइज 52% बढ़कर जनवरी-मार्च तिमाही में 2.19 लाख रुपए हो गया।

ऑटो लोन 14%, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन 21% बढ़े

बीती तिमाही ऑटो लोन 13.9% और टू-व्हीलर लोन सालाना 15.1% बढ़े, हालांकि त्योहारों के बाद वितरण की गति थोड़ी धीमी पड़ी। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन 20.8% बढ़कर करीब 1 लाख करोड़ हो गया। प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड और जीएसटी तर्कसंगत होने से इस सेगमेंट को सहारा मिला।

होम लोन: यह ₹44.4 लाख करोड़ के साथ सबसे बड़ा सेगमेंट बना रहा। इसमें 9.4% वृद्धि हुई। वहीं पर्सनल लोन 12.9% बढ़कर ₹16.5 लाख करोड़ तक पहुंचा, लेकिन इसमें तनाव के संकेत हैं। दूसरी ओर क्रेडिट कार्ड बिजनेस लगभग स्थिर रहा। नए कार्ड जारी होने में लगातार दूसरे साल गिरावट देखी गई।

Get Exclusive Access to My Private Channel

✅One-Time Entry Fee Only. No Monthly Fees. Lifetime Validity.

♦ **Indian Newspaper**

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ **International Newspapers channel** [Europian, American, Gulf & Asia]

♦ **Magazine Channel**

National & International [Genaral & Exam related]

♦ **English & Hindi Editorials**

[National + International Editorials]

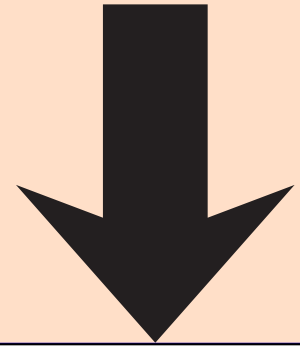

Click here to join

अब सिंहासन की बारी

देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तस्वीर साफ होने के साथ ही वहां मुख्यमंत्री के चयन की कवायद तेज हो गई है। तमिलनाडु में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के विधायक दल ने मंगलवार को पार्टी के मुखिया जोसेफ सी विजय को अपना नेता चुन लिया, तो यह स्वाभाविक ही था। वहां किसी ऊहापोह की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। हालांकि, टीवीके पार्टी स्पष्ट बहुमत से दस सीट पीछे रह गई है, मगर उसे सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का अंकगणित बहुत कमजोर है और छोटे दलों के पास पर्याप्त संख्या में विधायक हैं, जो विजय के साथ खड़े हो सकते हैं। विजय के लिए असली चुनौती मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू होने वाली है, क्योंकि वह पहली बार विधायक बने हैं और उनके पास संसदीय राजनीति का बहुत अनुभव नहीं है। दूसरी तरफ, राज्य के लोगों की उनसे अपेक्षाएं ज्यादा हैं। रुपहले परदे पर तंत्र की खामियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले विजय के नायकत्व की असली परीक्षा उनमें जननायक तलाशते लोग अब लेंगे। अपने चुनावी वायदे को वह कितनी ईमानदारी से लागू कर पाते हैं, इस पर तमिलनाडु ही नहीं पूरे देश की नजर होगी। यहां अरविंद केजरीवाल की नजीर उनके सामने है, जो दिल्ली में अपने ही बनाए मानदंड पर कैसे कसे गए और खारिज किए गए।

पांचों राज्यों में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है, तो यह उचित भी है, क्योंकि देरी से प्रशासनिक ऊहापोह बनी रहती है, जिससे असामाजिक तत्वों को मौका मिलता है।

इसी तरह, पश्चिम बंगाल और असम में शानदार विजय हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने दोनों प्रदेशों में विधायक दल के नेता के चयन के लिए जिस तत्परता से केंद्रीय पर्यवेक्षकों की घोषणा की है, वह भी सराहनीय है। पिछले कई चुनावों से यह एक परिपाटी सी बनती जा रही थी कि भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री के चुनाव में काफी समय लग जाता था और संबंधित राज्य को लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए काफी इंतजार करना पड़ता था। ऐसे में, बंगाल में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह व असम में स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा की नियुक्ति आश्वस्तकारी है कि वहां विधायक दल के नेता के चुनाव में अड़चनें नहीं आएंगी और जल्द ही कोलकाता और गुवाहाटी में राज्य सरकारें नियमित कामकाज में जुट सकेंगी। इन दोनों प्रदेशों में गहरे सामाजिक ध्रुवीकरण और चुनाव बाद ही हिंसा के इतिहास को देखते हुए जल्द से जल्द लोकप्रिय सरकार का गठन उचित है। खासकर पश्चिम बंगाल में आगजनी और हिंसा की कई घटनाओं को देखते हुए इस बात की अनिवार्यता और स्पष्ट हो जाती है। तमाम पार्टियों को इस समय परिपक्वता का प्रदर्शन करते हुए उद्दंड समर्थकों को नियंत्रित करना चाहिए।

केरलम और तमिलनाडु में भी सरकारें बदली हैं, मगर वहां जिस शालीनता से पराजित दलों ने जनादेश को स्वीकार किया है, उनकी सराहना की जानी चाहिए। खासकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नाटकीय रुख को देखते हुए। उनकी कई शिकायतों को राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा मानते हुए भी इस बात की प्रशंसा नहीं की जा सकती कि वह स्थापित मूल्यों के खिलाफ आचरण करें। राजनीति में शिकवे-शिकायतें अपनी जगह हैं, मगर राजनेताओं का यह पहला दायित्व है कि वे परिणाम आने के बाद अपने समर्थकों-कार्यकर्ताओं के हितों को पहली प्राथमिकता दें। उन्हें किसी टकराव और भड़काऊ परिस्थिति के हवाले करना खुदगर्जी की राजनीति है। एक सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनादेश अंतिम होता है और उसे शिरोधार्य करने में ही सबकी भलाई है।

क्या एसआईआर से सचमुच असर पड़ा

रोशन किशोर | राजनीतिक आर्थिक संपादक, एचटी

सांविधानिक व राजनीतिक नैतिकता को एक किनारे रख दें और ठोस चुनावी आंकड़ों पर गौर करें, तो भाजपा की इस जीत का मूल कारक एसआईआर नहीं दिखता है।

भाजपा को जीत क्या एसआईआर की वजह से मिली है? पश्चिम बंगाल के संदर्भ में यह एक विवादास्पद सवाल बनता जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल से निर्वाचन आयोग ने जिन 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया है, उनमें से छह राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, पर बंगाल इस मामले में सबसे विवादास्पद साबित हुआ, क्योंकि यहां 27 लाख मतदाता 'विचाराधीन' (अंडर एडजुडिकेशन) होने के कारण अयोग्य साबित कर दिए गए, यहां तक कि चुनाव के दिन भी वे अपने मताधिकार की बाट जोहते रह गए, जबकि करीब 62 लाख मतदाताओं के नाम एसआईआर में कटे हैं।

एसआईआर से जुड़ी सांविधानिक व राजनीतिक नैतिकता को एक किनारे रख दें और ठोस चुनावी आंकड़ों पर गौर करें, तो भाजपा की इस जीत का मूल कारक एसआईआर नहीं दिखता। इसे समझने के लिए तीन सवालों के जवाब तलाशते हैं। पहला सवाल है- पार्टियों के पारंपरिक गढ़ से बाहर एसआईआर का क्या असर रहा? दूसरा, मुस्लिम मतदाता इस प्रक्रिया से कितने प्रभावित हुए? और तीसरा, पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत की असली वजह क्या रही?

शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। साल 2011, 2016 और 2021 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल और उसके सहयोगियों को क्रमशः 226, 211 और 215 सीटें मिली थीं। उन्होंने इन तीनों चुनावों में 124 सीटों पर हर बार जीत दर्ज की। मैं यहां 2011 से पहले के चुनावों को शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि 2008 के परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं बदल गईं थीं।

बहरहाल, तृणमूल और उसके सहयोगियों को इस बार अपने गढ़ वाले 124 विधानसभा क्षेत्रों में से 78 में हार का सामना करना पड़ा है (इनमें से एक में चुनाव स्थगित है) और इन सभी क्षेत्रों से बाहर केवल 34 सीटें जीतने में उनको सफलता मिली है।

इसके बरअक्स, भारतीय जनता पार्टी ने साल 2019, 2021 और 2024 के चुनावों में क्रमशः 121, 77 व 90 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की (यहां 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों को विधानसभावार बांटा गया है)। उसे इन सभी चुनावों में कुल 54 विधानसभा क्षेत्रों में हर बार जीत मिली। इस बार भाजपा ने इन 54 विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ गुजरे तीनों चुनावों में कभी-न-कभी जीती गई सभी 142 सीटों पर भी विजय का परचम लहराया है। इसके अलावा, उसके खाते में 65 ऐसी सीटें भी आई हैं, जिन पर वह पहले कभी नहीं जीत सकी थी।

अगर किसी को बंगाल के इस नए घटनाक्रम को समझना है, तो उसे राज्य के चुनावी नतीजों पर एसआईआर के असर की जांच करनी चाहिए, पर उन 100 मजबूत विधानसभा सीटों को छोड़कर, जो 2026 में भी तृणमूल और कांग्रेस के पास ही रहीं। सवाल है कि इनमें से कितने क्षेत्रों में 2024 और 2026 के बीच मतदान में गिरावट देखी गई? जवाब है- 20, जिनमें से 2019, 2021, 2024 व 2026 में भाजपा 13 सीटों पर हर बार आगे रही, जबकि तृणमूल 2011, 2016, 2021 और 2026 में सात सीटें जीतीं (यह मंगलवार रात 10 बजे तक का आंकड़ा है)। बेशक, इन निर्वाचन क्षेत्रों में एसआईआर के कारण 2.1 प्रतिशत से लेकर 38.6 प्रतिशत मतदाताओं के नाम कटे हैं। किंतु, जब तृणमूल या भाजपा के वोट प्रतिशत में बदलाव और एसआईआर के कारण मतदाता-संख्या में आई कमी के बीच तुलना की जाती है, तो दोनों में दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं दिखता।

दूसरा सवाल। एसआईआर के तहत धर्म-विशेष के मतदाताओं के नाम को 'पक्षपातपूर्ण तरीके' से हटाने का आखिर क्या असर पड़ा? एसआईआर को लेकर यह आरोप जोर-शोर से उछला है कि इसके तहत उन जिलों में मतदाताओं के नाम ज्यादा हटाए गए, जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। पश्चिम बंगाल में 39 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे, जहां से 2011, 2016 और 2021 के चुनावों में मुस्लिम विधायक चुने गए थे। इन 39 सीटों में से 18 सीटें उन जिलों में थीं, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी का अनुपात 50 फीसदी या उससे अधिक था। इस बार भी इनमें से 34 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम विधायक चुने गए हैं, जिनमें से महज पांच वास्तव में गैर-तृणमूल उम्मीदवार हैं। शेष पांच सीटें भाजपा के खाते में गई हैं।

पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की कुल संख्या 40 है। साल 2021 में भी उनकी संख्या कमोबेश इतनी ही थी। अलबत्ता तृणमूल विधायकों में मुस्लिम विधायकों की हिस्सेदारी बढ़कर 42.5 प्रतिशत हो गई है। साफ है, यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का उदाहरण है, न कि मतदाता-सूची में कथित हेर-फेर का नतीजा। असम में कांग्रेस भी इसी गफलत का शिकार हुई है।

ऐसे में, तीसरा सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का असली कारण क्या था? इसका जवाब है, सत्ता विरोधी लहर। लोगों पर इसका भारी असर दिखा है, शेष कसर ध्रुवीकरण ने पूरी कर दी। 2021 से 2026 के बीच तृणमूल ने 293 विधानसभा क्षेत्रों में से 268 में अपना मत-प्रतिशत गंवाया है। इनमें से 69 सीटों पर उसे 10 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके उल्ट, भाजपा ने 293 विधानसभा सीटों में से 270 में अपना मत-प्रतिशत बढ़ाया है और 95 सीटों पर उसे 10 प्रतिशत से अधिक का लाभ मिला है।

जन-समर्थन में आए इस बदलाव के गहरे निहितार्थ हैं। ऐतिहासिक तथ्यों से इसे समझना आसान होगा। दरअसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले वाममोर्चा ने 2006 की अपनी शानदार जीत और 2011 की करारी हार के बीच 11 प्रतिशत मत गंवाए थे। परिसीमन के कारण किए गए बदलावों के कारण इस परिवर्तन का क्षेत्रवार सटीक विश्लेषण संभव नहीं है, पर 2026 में तृणमूल के मत-प्रतिशत में लगभग 4.7 प्रतिशत की गिरावट हुई है, जो वाममोर्चा की तुलना में कम है। यही कारण है कि ममता बनर्जी 2011 के वाममोर्चे की तुलना में अपनी सीटों की संख्या को कहीं अधिक बचाए रखने में सफल रही हैं।

हालांकि, तृणमूल कांग्रेस के सामने अब भी एक बड़ी चुनौती शेष है। अगर बचे हुए हिंदू मतदाता भाजपा या राज्य की अन्य विपक्षी पार्टियों का रुख कर लें, तब क्या होगा? ये मतदाता अब तृणमूल के खिलाफ मुखर हो सकते हैं, क्योंकि वह भाजपा से हार चुकी है। जाहिर है, पश्चिम बंगाल की राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है।

(साथ में अभिषेक झा)

वैश्विक पहचान मिलने से और संवरेगी शेखा झील

संगीता सिंह | आयुक्त, अलीगढ़ मंडल

सुबह की हल्की धुंध में जब पक्षियों का मधुर कलरव रात्रि की नीरवता को तोड़ता है, तब शेखा झील का विस्तार एक जीता-जागता संसार बनकर उभरता है। यह संसार कोमल है, पक्षियों के मखमली पंखों-सा। प्रवासी पक्षी इस आर्द्रभूमि में आते हैं, अघोषित मेहमानों की तरह, कुछ दिन ठहरते हैं और उड़ चलते हैं किसी दूसरी दुनिया की ओर। पीछे रह जाती है, उनकी मीठी यादें और फिर से उनको देखने की कसक। अब जब शेखा झील को रामसर कन्वेंशन (अभिसमय) के तहत 'रामसर आर्द्रभूमि स्थल' का दर्जा प्राप्त हुआ है, तब इस शांत स्थल को वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय द्वारा साल 2018-19 के दौरान कराई गई गणना और 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, देश में 22,361 झीलें हैं, हालांकि इनमें से बहुत सी झीलों की स्थिति अच्छी नहीं है। गाद जमने या सूख जाने के कारण इनमें से ज्यादातर उपयोग लायक नहीं रह गई हैं। इस समय देश में कुल 24,24,540 जल निकाय हैं, जिनमें तालाब, टैंक, झील, जलाशय आदि शामिल हैं। इनके संरक्षण की बहुत जरूरत है, क्योंकि इनमें से कई न सिर्फ हमारे शहरों की जीवनधारा हैं, बल्कि भविष्य की जरूरतों के लिहाज से एक अनमोल संसाधन हैं।

शेखा झील को रामसर कन्वेंशन के तहत 'रामसर आर्द्रभूमि' का दर्जा मिला है। इससे इस शांत स्थल को एक वैश्विक पहचान मिली है।

इस पृष्ठभूमि में शेखा रामसर झील की अहमियत स्पष्ट हो जाती है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए 2 फरवरी, 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुई अंतरराष्ट्रीय संधि है, जो 1975 में प्रभावी हुई। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र को बचाना है। भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ और वर्तमान में यहां 99 रामसर स्थल हैं। बिहार में बक्सर की गोकुल झील, पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील और कटिहार में गोगाबिल झील के 'रामसर स्थल' बनने के बाद वहां रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर छह हो गई है।

जो लोग शेखा झील को जानते हैं, वे इससे अभिभूत रहे हैं। उनके लिए यह शुरुआत नहीं, बल्कि इस स्थल की विशिष्टता की पुष्टि है। शेखा झील पर कभी शांत बैठे बगुले के रूप में, कभी अबाबील जैसे शिकारी के रूप में और कभी दूर देश से आए प्रवासी पक्षियों की विभिन्न सुर लहरियों में जीवन के विविध आयाम सहज ही परिलक्षित होते हैं। यह इस बात का संकेत है कि पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय महत्व हमेशा जोर-शोर से अपने को प्रकट नहीं करते, बल्कि निश्छल जल की तरह धीरे से अपनी चमक बिखेर देते हैं। अभी पिछले वर्ष ही प्रशासन व नागरिक समाज के लोग झील पर जमी सूखी जलकुंभी साफ करने आए थे। बारिश आते-आते वह प्रयास झील में दिख रहे स्वच्छ जल और पक्षियों की बढ़ी हुई संख्या के रूप में सामने आया।

रामसर कन्वेंशन अपने साथ मात्र वैश्विक पहचान नहीं लाया है, वरन पर्यावरणीय संरक्षण व इसके सतत उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता लेकर आया है। करीब 40 हेक्टेयर में फैली यह आर्द्रभूमि अलीगढ़ से 17 किलोमीटर दूर है। प्रतिवर्ष 'बार हेडेड गूज, ग्रे लैग गूज' व 'नॉर्दर्न पिनटेल' जैसे प्रवासी पक्षी इसके शांत जल में जीवन की किलकारियां भरते हैं। यहां अब तक पक्षियों की 166 प्रजातियों की आमद दर्ज की गई है। मंडल के दूसरे जिले- एटा की जलेसर तहसील में 'पटना पक्षी विहार' को हाल में ही रामसर स्थल घोषित किया गया है। इससे यहां भी इको-टूरिज्म की संभावना बनी है।

इन स्थलों के विकास का उद्देश्य यह है कि सैलानी इन आर्द्रभूमियों का भ्रमण करें और प्राकृतिक परिवेश में विश्राम केंद्रों का सहज आनंद प्राप्त करें। अगर सावधानी से कार्य किया जाए, तो इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि इस क्षेत्र की सूक्ष्म प्राकृतिक संरचना भी बची रहेगी। हालांकि, इन सबके बीच मुख्य चुनौती इस बात की है कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या कहीं पक्षियों के सहज जीवन में व्यवधान न उत्पन्न करे। इसी तरह, समय-समय पर इन जल क्षेत्रों की सफाई और इनमें जलकुंभी के विस्तार को रोकना सतत चुनौती होगी। यहां निर्बाध जलापूर्ति भी संरक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग होगा। शेखा झील आज एक सितारा बनकर उभरा है। अब इसकी चमक को और निखारने व आकर्षक बनाने की आवश्यकता है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं।)

मनसा वाचा कर्मणा

ओंकार का महत्व

एक साधक ने प्रश्न किया- 'बाबा, सत्य का सबसे बड़ा माध्यम क्या है?'

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति- यह वैदिक उद्घोष भारतीय दर्शन की उस गहराई को स्पर्श करता है, जहां शब्द अपनी सीमा स्वीकार करते हैं और अनुभव ही सत्य का एकमात्र माध्यम बन जाता है। वेद, उपनिषद और समस्त आध्यात्मिक परंपराएं जिस परम तत्व की ओर संकेत करती हैं, उसे पाने के लिए तपस्वी तप करते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और साधक जीवन भर साधना में निमग्न रहते हैं। उसी परम सत्य को संक्षेप में ॐ या ओंकार के रूप में अभिव्यक्त किया गया है।

ओंकार सृष्टि का मूल स्पंदन है। यह वह आद्य कंपन है, जिससे सृजन, पालन और संहार की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती हैं। अ+उ+ म, इन तीन ध्वनियों का सम्मिलित रूप ओंकार है, जो ब्रह्म के त्रिविध आयामों का प्रतीक है। अ सृष्टि का आरंभ, उ उसका विस्तार और म उसका लय दर्शाता है। इस तरह ओंकार में संपूर्ण ब्रह्मांड की गति और प्रक्रिया समाहित है। यह 'सगुण ब्रह्म' की अभिव्यक्ति है, जबकि निर्गुण ब्रह्म उस परम अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जो सभी गुणों, रूपों और शब्दों से परे है। यही कारण है कि ओंकार को निर्गुण और सगुण के बीच एक अद्भुत सेतु माना गया है।

वास्तव में ब्रह्म का अनुभव बौद्धिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। इसे तर्क या भाषा से पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम केवल प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से उसके निकट पहुंचने का प्रयास करते हैं। ओंकार ऐसा ही एक दिव्य प्रतीक है, जो उस अनंत सत्ता की झलक प्रदान करता है। यह केवल उच्चारण का विषय नहीं, बल्कि श्रवण का विषय है। उस सूक्ष्म नाद को सुनना, जो हमारे भीतर और ब्रह्मांड के विस्तार में निरंतर गूंजता रहता है। जब साधक बाहरी कोलाहल से हटकर अपने अंतर्मन में उतरता है, तब इस अनाहत नाद को अनुभव करता है। यही उसे मूल स्रोत से जोड़ देता है।

आध्यात्मिक साधना का सार इसी अनुभव में निहित है। साधक जब इस ध्वनि के प्रति संवेदनशील होता है, तब उसका मन स्थिर होने लगता है और चेतना विस्तार होने लगता है। यह प्रक्रिया आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। इस गूढ़ सत्य को सरल भाषा में समझाने के लिए रामायण का एक प्रसंग है। जब भगवान राम के चरणों के स्पर्श से नाव सोने की बन गई, तो नाविक की पत्नी हर वस्तु को सोना बनाने लगी। तब नाविक ने उसे समझाया कि वस्तुओं की अपेक्षा उन चरणों की शरण में जाना अधिक बुद्धिमानी है।

यह कथा सिखाती है कि बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागने के बजाय मूल स्रोत से जुड़ना ही सच्चा ज्ञान है।

श्रीश्री आनंदमूर्ति

आध्यात्मिक साधना का सार इसी अनुभव में निहित है। साधक जब इस ध्वनि के प्रति संवेदनशील होता है, तब उसका मन स्थिर होने लगता है और चेतना का विस्तार होने लगता है।

पोप लिओ XIV | ईसाई धर्मगुरु

शिक्षण का अर्थ है, आंतरिक आजादी हासिल करने और आलोचनात्मक सोच के लिए खुद को तैयार करना। इस प्रक्रिया में, आस्था और तर्क न एक-दूसरे की उपेक्षा करते हैं और न विरोध। सत्य की खोज में दोनों को हमसफर होना चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 06 मई, 1951

लोकतंत्री मोर्चे का भंग होना

अहमदाबाद में कांग्रेस महासमिति ने एकता का जो प्रस्ताव पास किया था, वह रंग लाने लगा है। नेहरूजी व मौलाना आजाद के प्रयत्नों से आचार्य कृपलानी तथा उनके साथियों ने लोकतंत्री मोर्चे को भंग करना स्वीकार कर लिया है।

हम इस बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय का स्वागत किये बिना नहीं रह सकते। इसके लिए न केवल नेहरूजी व मौलाना आजाद, वरन् आचार्य कृपलानी भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने सूझ से काम लेकर एकता की ओर ठोस कदम उठाया।

इस बात को तो सब स्वीकार करेंगे ही कि देश की वर्तमान डांवाडोल आर्थिक परिस्थितियों के समय हमें संगठित होकर उनका सामना करना है। यह समय राजनीतिक अखाड़ेबाजी का नहीं, समवेत प्रयत्नों से अपनी कमियों को दूर करने, वर्तमान का सामना करने और भविष्य को सुरक्षित बनाने का है। हमें आशा है कि कांग्रेस तथा लोकतंत्री मोर्चे ने एकता की ओर जो कदम उठाया है, उससे न केवल राजनीतिक विश्रृंखलता ही रुकेगी वरन् देश की आर्थिक भित्ति भी सुदृढ़ होगी।

काश्मीर की समस्या : भारत के विरोध के बावजूद अमरीका और उसके साथी काश्मीर में अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं। गत सोमवार को सुरक्षा परिषद ने रूस की आपत्ति की पर्वाह न करते हुए एक अमरीकी नागरिक श्री फ्रांक ग्राहम को काश्मीर में नया संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया।

दूसरी ओर काश्मीर की जनता भी अपने अधिकारों के लिए उतनी ही दृढ़ है। जिस दिन सुरक्षा परिषद ने नये प्रतिनिधि की नियुक्ति की, उसी दिन काश्मीर में युवराज कर्णसिंह ने एक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। जनता के मतों से निर्वाचित यह संविधान सभा ही काश्मीर के भविष्य का निर्णय करेगी। काश्मीर सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि वह संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि को भारतीय काश्मीर में न घुसने दे और इस प्रकार आंग्ल-अमरीकी गुट की चाल विफल कर दे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इन दिनों ब्रिटेन व अमरीका में पाकिस्तान के प्रति अगाध स्नेह उमड़ पड़ा है। हाल में ही ब्रिटिश पत्रों ने नेहरूजी को उनकी काश्मीर-नीति के लिए जीभरकर कोसा है और उनकी तुलना चेम्बरलेन से की है, यही नहीं, उन्हें चेम्बरलेन से भी अधिक खतरनाक बताया है।

अनुलोम-विलोम

जनादेश 2026

भाजपा नब्ज पकड़ने में सफल रही

हालिया विधानसभा चुनावों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, रणनीतियों, नेतृत्व और सामाजिक समीकरणों का जटिल मिश्रण है। इस बार के नतीजों ने कई स्थापित धारणाओं को तोड़ा और नई राजनीतिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वजहों से सत्ता-परिवर्तन हुआ है, लेकिन अगर गहराई से देखें, तो कुछ साझा कारक ऐसे रहे, जिन्होंने इन नतीजों को आकार दिया।

इनमें भाजपा द्वारा जनता की नब्ज पकड़ना उल्लेखनीय है। चुनाव अब केवल विकास या स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पहचान संस्कृति और भावनात्मक अपील तक व्यापक हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से सत्ता में रही सरकार के खिलाफ माहौल बना, लेकिन यह केवल सत्ता-विरोधी रुझान नहीं था। यहां एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया गया। माछ-भात, झालमुड़ी और मां काली जैसे प्रतीकों के जरिये यह संदेश दिया गया कि स्थानीय परंपराओं का सम्मान केवल एक खास राजनीतिक विचारधारा ही कर सकती है। इसी तरह, ध्रुवीकरण भी इन चुनावों में बड़ा कारक रहा। यह केवल धार्मिक आधार पर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के स्तर पर भी हुआ। असम में इसका एक अलग रूप देखने को मिला और इसे कहीं अधिक व्यवस्थित तरीके से लागू किया गया।

इन चुनावी नतीजों का एक बड़ा कारक प्रशासनिक और संरचनात्मक बदलाव भी है। मतदाता सूचियों में संशोधन और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं का असर नतीजों पर पड़ा है। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटने का मुद्दा चर्चा में रहा, वहीं असम में परिसीमन के बाद सीटों का स्वरूप बदल गया, जिससे कई क्षेत्रों का राजनीतिक संतुलन प्रभावित हुआ। ये बदलाव तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन इनका असर जमीन पर बहुत गहरा होता है। हालांकि, तमिलनाडु में जो हुआ, वह भारतीय राजनीति के लिए एक दिलचस्प मोड़ है।

यहां एक फिल्मी सितारे ने अपनी लोकप्रियता को राजनीतिक ताकत में बदल दिया। यह बदलाव जिस तेजी और पैमाने पर हुआ, उसने सबको चौंका दिया। इसका मतलब यही है कि आज का मतदाता पारंपरिक दलों से हटकर नए विकल्पों को मौका देने के लिए तैयार है। खासकर युवा ऐसे चेहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो उन्हें अलग लगता है। यह बदलाव आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

जनता के मुद्दे पर मुखर हो विपक्ष

राजनीतिक विचारधारा की लोकप्रियता और अलोकप्रियता उनकी ग्राह्यता और उदारता से सर्वाधिक प्रभावित होती है। हठधर्मिता और आत्ममुग्धता अलोकप्रिय होने के बड़े कारण हैं। खासकर, जब नेतृत्व हठधर्मिता की जद में आ जाए, तो संभालना मुश्किल होता है। वह न तो अपनी गलतियां सुधारता है, न प्रतिद्वंद्वी की कुशलता को स्वीकार करता है। नतीजतन, न आगे की तैयारी हो पाती है, न पीछे का विश्लेषण।

पिछले कुछ वर्षों से भारत के तमाम राजनीतिक दलों, विशेषकर विपक्ष की स्थिति लगभग ऐसी ही रही है। कांग्रेस, वाम दल, सपा, राजद, टीएमसी- सबके लगभग एक जैसे राग हैं। चुनाव जीतने या हारने के बाद ये पार्टियां किसी भी मुद्दे पर बहुत अधिक दिनों तक मुखर नहीं दिखतीं और न ही किसी मुद्दे को निर्णायक बनाकर जनता से जुड़ पा रही हैं। बार-बार हारने के बाद भी उनको जनता से दूरी का एहसास नहीं हो रहा। इसका कारण यह है कि वे पराजय को स्वीकार नहीं कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि संघ और आनुषंगिक संगठन के साथ लंबे समय से सत्ता में बने रहने की विशेष सुविधा है, इसलिए वह इससे उबर जाती है। यही कारण है कि आज राजनीतिक परिदृश्य कुछ ऐसा बन गया है कि कोई भी चुनाव हो, परिणाम आने के बाद जिम्मेदारियों से भागना राजनीतिक कौशल गिना जाने लगा है। यह दलों और नेताओं को महंगा पड़ रहा है।

वे चुनाव से पहले शॉर्टकट रास्ता खोजते हैं और फिर परिणाम विपरीत आने पर फिर से नए शॉर्टकट से निकल भागना चाहते हैं। किसी भी चुनाव के बाद एक ही आलाप! जीते तो खुद की पीठ थपथपाई और हारे तो धांधली का आरोप लगाकर जिम्मेदारी मुक्त हो गए।

देश में कोई संस्था नहीं बची है, जिस पर आरोप नहीं लगा है। किंतु इसका फायदा कब और क्या मिला? क्या जनांदोलन हो गया? दरअसल, ईवीएम, वोट चोरी जैसे मुद्दे जनता से नहीं जुड़ रहे। कार्यकर्ता भी नेता की 'हां' में 'हां' तो मिलाते हैं, लेकिन अंदर से टूट रहे हैं। आशाहीन और ऊर्जाहीन कार्यकर्ता सिर्फ भीड़ बन रहे हैं। उन्हें नेतृत्व से उम्मीद है, पर उनमें विश्वास नहीं। जबकि, पर्याप्त अवसर और बहुतेरे विकल्प बचे हैं। जहां कहीं थोड़ी मेहनत हुई, मुद्दे की राजनीति हुई, वहां दलों, क्षत्रपों ने पूर्णरूपेण अथवा आंशिक वापसी की है। यही कारण है कि आज राजनीतिक हितों के आरोप मुखर हैं और जनता के मुद्दे गौण। इसलिए फिलहाल देश में किसी बड़े राजनीतिक परिवर्तन की गुंजाइश नहीं दिख रही। जनता इसी अनुरूप जनादेश सुना रही है।

ओंकार कश्यप, टिप्पणीकार

विदेश से अपने परिवार को रकम भेजने में भारतीय सबसे आगे

उपलब्धि

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने वर्ष 2024 में 137 अरब डॉलर से अधिक राशि विदेशों से धनप्रेषण के रूप में हासिल कर दुनिया में शीर्ष स्थान बरकरार रखा और वह 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने वाला एकमात्र देश रहा।

संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसकी रिपोर्ट के अनुसार, भारत विदेशों से लगातार सबसे अधिक प्रेषण पाने वाला देश बना हुआ है। भारत के बाद मेक्सिको का स्थान है। वर्ष 2024 में भारत, मेक्सिको, फिलीपीन और फ्रांस वैश्विक स्तर पर धनप्रेषण पाने के मामले में शीर्ष चार देशों में शामिल रहे।

भारत का बज रहा डंका

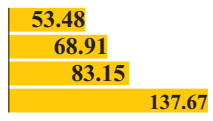

■ आंकड़ा अरब डॉलर में

शीर्ष प्रेषण भेजने वाले देश

क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिण एशिया में 2024 के दौरान प्रेषण में 11.8 प्रतिशत की सबसे तेज वृद्धि का अनुमान है। उच्च आय वाले देश इसके प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। अमेरिका से 2024 में सर्वाधिक 100 अरब डॉलर से अधिक राशि दूसरे देशों को भेजी गई। उसके बाद सऊदी अरब (46 अरब डॉलर से अधिक), स्विट्जरलैंड (करीब 40 अरब डॉलर) और जर्मनी (लगभग 24 अरब डॉलर) का स्थान रहा।

100
अरब डॉलर से अधिक प्राप्त करने वाला पहला देश

6.2
लाख से अधिक छात्र अन्य देशों में कर रहे पढ़ाई

प्रवासी निभा रहे महत्वपूर्ण भूमिका

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने देश के तकनीकी क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवासियो के विकास में योगदान को सुरक्षित रखने के लिए ब्रेन ड्रेन की चुनौती को ब्रेन गेन में बदलना जरूरी है। जब कुशल कामगार विदेश जाते हैं, तो मूल देश को मानव संसाधन का नुकसान हो सकता है, लेकिन सही नीतियों से ज्ञान का आदान-प्रदान संभव है जिससे दोनों देशों को लाभ होता है।

अंतरराष्ट्रीय छात्रों में एशिया का दबदबा

रिपोर्ट के अनुसार, एशियाई देशों का अंतरराष्ट्रीय छात्रों में सबसे बड़ा हिस्सा है। 2022 में चीन से 10 लाख से अधिक छात्र विदेश गए, जिससे वह दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत देश बना। भारत दूसरे स्थान पर रहा, जहां से 6.2 लाख से अधिक छात्र विदेश में पढ़ रहे थे। चीन और भारत के बाद संख्या में काफी गिरावट देखी गई—उज्बेकिस्तान (1.5 लाख), वियतनाम (1.34 लाख) और जर्मनी (1.26 लाख) इसके बाद आते हैं। वहीं अमेरिका, फ्रांस, नाइजीरिया, सीरिया और नेपाल से प्रत्येक के 95,000 से 1,15,000 छात्र विदेश में पढ़ रहे थे। दुनिया के आधे से अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्र यूरोप और उत्तरी अमेरिका में रहते हैं।

प्रतिभाओं को वापस बुलाने की कोशिश

भारतीय प्रवासी समुदाय को देश के प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बताया गया है। रिपोर्ट ने 'ब्रेन ड्रेन' की चुनौती को 'ब्रेन गेन' में बदलने के लिए नीतिगत उपायों की जरूरत पर भी बल दिया। भारत ब्रेन गेन के लिए प्रवासी सम्मेलनों और नवाचार केंद्रों का आयोजन करता है, ताकि भारतीय वैज्ञानिकों और उद्यमियों को वापस आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स		निफ्टी	
77,017	-251.61	24,032	-86.50

टॉप गेनर

कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
एमएंडएम	3211.65	3.41
अल्ट्राटेक	11964.45	1.79

टॉप लूजर

आईसीआई बैंक	1251.45	-1.53
एटरनल	248.50	-1.37

टॉप गेनर

कंपनी	बंद भाव	बदलाव%
एमएंडएम	3,220.80	3.68
अल्ट्राटेक	11,939.00	1.54

टॉप लूजर

आईसीआई बैंक	1,250.90	-1.57
जिओ फाई.	249.00	-1.48

कमोडिटी

	भाव	बदलाव
सोना	1,52,500	-300
चांदी	2,51,000	+1500

करेंसी
डॉलर/रुपया
95.18 +0.05

साइबर सुरक्षा के लिए समझौता किया

नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल ढांचे को और अधिक मजबूत किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखकर यूआईडीएआई और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता किया है, जिसके तहत छह मुख्य क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। यूआईडीएआई सीईओ विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह समझौता डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत तकनीकी शोध के क्षेत्र में पांच वर्षों तक सहयोग उद्देश्य से किया गया है।

रुपया पांच पैसे बढ़कर 95.18 प्रति डॉलर पर

मुंबई। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार को रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले पांच पैसे की तेजी के साथ 95.18 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह अबतक के सबसे निचले स्तर पर चला गया था लेकिन बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के संभावित हस्तक्षेप से इसमें सुधार आया। ब्रेंट क्रूड 110 डॉलर प्रति बैरल के आस-पास बना हुआ है, जिससे रुपया दबाव में है।

कुमार मंगलम वोडाफोन के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष

नई दिल्ली। कर्ज में डूबी कंपनी वोडाफोन आइडिया ने मंगलवार को घोषणा की कि आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला को कंपनी का नया गैर-कार्यकारी अध्यक्ष किया गया है। कंपनी ने कहा कि वह रविंदर टक्कर का स्थान लेंगे। टक्कर ने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब वे गैर-कार्यकारी वाइस चेयरमैन के रूप में कुमार मंगलम बिड़ला को सहयोग देते रहेंगे। कंपनी पर भारी कर्ज और समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाया को लेकर लंबे समय से वित्तीय दबाव बना हुआ है।

कर्ज वृद्धि में अल्पकालिक सुस्ती के आसार

मुंबई। बैंक क्षेत्र के दिग्गज दीपक पारेख ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं से बैंकिंग, वित्तीय सेवा एवं बीमा क्षेत्र के सामने कोई बड़ा जोखिम नहीं है लेकिन कर्ज वृद्धि में अल्पकालिक सुस्ती आ सकती है। व्यापक वित्तीय प्रणाली मजबूत एवं पर्याप्त पूंजी वाली बनी हुई है लेकिन वैश्विक परिस्थितियां नए ऋण की मांग तथा समग्र कारोबारी गति को प्रभावित कर सकती हैं।

भारतीय निवेश से रोजगार में वृद्धि

वॉशिंगटन। भारत से अमेरिका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 16.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा जिससे रोजगार के करीब 70,800 अवसर उत्पन्न हुए। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत से अमेरिका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीए) करीब 16.4 अरब डॉलर रहा जिससे करीब 70,800 नौकरियों को समर्थन मिला।

उच्चस्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जल्द लागू हो सकता है फैसला

तैयारी: कृत्रिम पनीर की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा

विशेष

■ प्रियंका शर्मा

नई दिल्ली। सरकार बाजार में बिकने वाले कृत्रिम पनीर पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने फैसला लिया है कि कम पोषण वाले और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले दिखावटी पनीर को बाजार से पूरी तरह बाहर किया जाएगा। मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इस मामले में बनी एक उच्चस्तरीय समिति ने अक्टूबर 2025 में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया था, जिसे मार्च 2026 की बैठक में आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। समिति का कहना था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक देश है, लेकिन इसके बावजूद बाजार में बड़ी मात्रा में सस्ता कृत्रिम पनीर बेचा जा रहा है। यह असली पनीर जैसा दिखता और स्वाद में मिलता-जुलता होता है, जिससे आम ग्राहक के लिए पहचान करना मुश्किल हो जाता है और वह भ्रमित होता है। इसी वजह से इसे बाजार से चरणबद्ध तरीके से हटाने की योजना बनाई जा रही है। वर्तमान में कृत्रिम पनीर की बिक्री पर पूरी तरह रोक नहीं है। देश में करीब 1,000 ऐसी कंपनियां या कारोबारी हैं, जिनके पास इसे बनाने का लाइसेंस है। नई नीति के तहत अब नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे और मौजूदा कंपनियों को अपना स्टॉक खत्म करने और उत्पादन बंद करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

कीमत में भारी अंतर

अधिकारियों के अनुसार, असली ब्रांडेड पनीर की कीमत करीब 450 रुपये प्रति किलो तक होती है, जबकि खुले में बिकने वाला कृत्रिम या बिना ब्रांड वाला पनीर 250 से 300 रुपये प्रति किलो तक बिकता है।

11
अरब डॉलर के करीब पहुंच सकता है पनीर का बाजार

इसलिए पड़ी जरूरत

बीते कुछ समय से बाजार में 'कृत्रिम पनीर' का चलन तेजी से बढ़ा है। यह एक सस्ता विकल्प है, जिसे ताजे दूध की बजाय मुख्यत: पाम ऑयल, मिल्क पाउडर, स्टार्च और इमल्सीफायर्स से बनाया जाता है। यह दिखने और बनावट में असली पनीर जैसा होता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता और पोषण मूल्य दूध से बने पनीर की तुलना में काफी कम होता है। यह कृत्रिम पनीर सस्ता होने के कारण कई रेस्तरां में उपयोग किया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को भ्रम होता है।

लगातार बढ़ रहा बाजार

उत्तर भारत में खासतौर पर पनीर प्रोटीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यही कारण है कि भारत का पनीर बाजार 10.8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। मार्केट रिसर्च कंपनी आईएमएआरसी के अनुसार, वर्ष 2033 तक भारतीय पनीर बाजार के 22.1 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 8.7% रहने की संभावना है।

स्वास्थ्य पर भी खतरा बढ़ा

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, कृत्रिम पनीर में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम और फैट बहुत ज्यादा होता है। इसके नियमित सेवन से स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। इससे शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध पैदा हो सकता है, जो टाइप-2 डायबिटीज का कारण बन सकता है।

विदेशी निवेश मंजूरी के लिए 40 खास क्षेत्रों की पहचान

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने चीन समेत भारत के साथ जमीन सीमा साझा करने वाले देशों से आने वाले निवेश को तेज करने के लिए 40 अहम क्षेत्रों की पहचान की है, जहां प्रस्तावों को 60 दिनों के भीतर मंजूरी देने का लक्ष्य रखा गया है।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने इसके लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया तय की है, जो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान से आने वाले निवेश प्रस्तावों पर लागू होगी। सरकार का कहना है कि इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना जरूरी है, क्योंकि ये ज्यादातर उच्च तकनीक और विनिर्माण से जुड़े हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उन्नत बैटरी, दुर्लभ खनिज, मशीन टूल्स और औद्योगिक पुर्जे जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा डिस्प्ले से जुड़े उपकरण, कैमरा मॉड्यूल, स्पीकर, माइक्रोफोन और पहनने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी इस सूची में शामिल किए गए हैं।

नियंत्रण भारतीय कंपनियों के पास रहेगा : सरकार ने यह भी साफ किया है कि ऐसे निवेश में भारतीय कंपनियों पर नियंत्रण भारतीयों के पास ही रहेगा। यानी कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी और नियंत्रण भारतीय नागरिकों या भारतीय स्वामित्व वाली इकाइयों के पास होना जरूरी होगा। त किए जा सकेंगे।

मानक प्रक्रिया जारी

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों के निपटान के लिए जारी अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के तहत अब सरकार सभी आवेदनों पर 12 सप्ताह के भीतर फैसला करेगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार, इसमें आवेदकों के प्रस्तावों में कमियों को दूर करने या सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने में लगा समय शामिल नहीं होगा।

सख्त नियम : निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त रिपोर्टिंग नियम भी तय किए गए हैं। निवेश करने वाले को अपनी हिस्सेदारी की पूरी जानकारी, असली मालिक का विवरण, कंपनी का ढांचा, निदेशक मंडल और प्रमुख अधिकारियों की जानकारी देनी होगी। साथ ही, जिस भारतीय कंपनी में निवेश किया जा रहा है, उसे भी अपने पंजीकरण और हिस्सेदारी से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी।

चांदी 1,500 रुपये मजबूत, सोना टूटा

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी की कीमत 1,500 रुपये बढ़कर 2.51 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गयी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के साथ घरेलू बाजार में चांदी में तेजी आई।

पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 2,49,500 रुपये प्रति किलोग्राम रही थी। हालांकि, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 300 रुपये घटकर 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रहा। सोने की कीमत सोमवार को 1,52,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रही थी। विश्लेषकों ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलेत निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।

वाहनों की बिक्री के लिहाज से शानदार रहा अप्रैल माह

रिपोर्ट

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। ऑटोमोबाइल बाजार के लिहाज से अप्रैल महीना खासा उत्साहजनक रहा है। बीते महीने वाहनों की खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर 12.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

हालांकि कुल बिक्री में मार्च के मुकाबले थोड़ी गिरावट देखी गई है लेकिन बिक्री की आंकड़ों को ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लोग बेहतर मानते हैं। मंगलवार को फाडा की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते महीने देशभर में 26,11,317 वाहनों की बिक्री हुई है। जबकि बीते वर्ष की समान अवधि में 23,12,221 वाहन बिके थे। वहीं, मार्च 2026 में कुल 26,92,449 वाहनों की बिक्री हुई थी। छह में से पांच श्रेणी की वाहनों की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि बीते महीने ग्रामीण क्षेत्र में वाहनों की अच्छी बिक्री हुई है। पैसेंजर वाहनों की ग्रामीण क्षेत्र में बिक्री 20.40 फीदी और शहरी क्षेत्र में 7.11 फीसदी तक बढ़ी है। कमर्शियल वाहनों की बिक्री के मामले में भी ग्रामीण बाजार आगे रहा है जबकि दोपहिया वाहनों की बिक्री में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में तेजी देखी गई है।

ब्रिटेन में निर्मित रेंज रोवर के दाम घटाए

नई दिल्ली, एजेंसी। लक्जरी वाहन विनिर्माता जगुआर लैंडरोवर (जेएलआर) की भारतीय इकाई ने मंगलवार को भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता लागू होने की संभावना को देखते हुए ब्रिटेन में निर्मित रेंज रोवर मॉडलों की कीमतों में 75 लाख रुपये तक की कटौती की घोषणा की।

जेएलआर इंडिया ने कहा कि पूरी तरह निर्मित इकाई के रूप में भारत आने वाले वाहनों की कीमतों में कटौती का प्रमुख लाभ रेंज रोवर एसवी और रेंज रोवर स्पोर्ट एसवी मॉडलों को मिलेगा। इस कटौती के बाद रेंज रोवर एसवी मॉडल की शुरुआती शोरूम कीमत 4.25 करोड़ रुपये से घटाकर 3.5 करोड़ रुपये हो गई है।

महंगे तेल से कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा: फिच

नई दिल्ली, एजेंसी। कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बने रहने और घरेलू ईंधन कीमतों में समय पर वृद्धि नहीं होने की स्थिति में भारत की तेल विपणन कंपनियों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इससे उनकी कमाई और नकदी प्रवाह भी प्रभावित होगा। फिच रेटिंग्स ने मंगलवार को यह अनुमान जताया।

रेटिंग एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि कच्चे तेल की ऊंची लागत के अनुरूप पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं होने पर तेल कंपनियों की कर-पूर्व आय तेजी से घट सकती है। इसके अलावा बड़े स्तर पर भंडारण और अधिक रिफाइनिंग मात्रा के कारण कार्यशील पूंजी की जरूरत भी बढ़ेगी, जिससे मुक्त नकदी प्रवाह पर दबाव आएगा। फिच रेटिंग्स ने कहा कि यदि 2026 में ब्रेंट क्रूड औसतन 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहता है, तो केवल रिफाइनिंग पर आधारित कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, जबकि खुदरा ईंधन कीमत नियंत्रण से प्रभावित कंपनियां दबाव में रहेंगी।

रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कंपनियों की रेटिंग अब भी सरकार या सरकारी स्वामित्व से जुड़ी हुई है, जिससे कमजोर स्वतंत्र क्रेडिट प्रोफाइल का असर सीमित रहता है। सरकार की नीतियां और मूल्य स्थिरीकरण तंत्र इस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाते रहेंगे।

भारत झटकों से निपटने में बेहतर स्थिति में: मूडीज

नई दिल्ली। भारत उभरते बाजारों में 2020 के बाद से सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बना हुआ है और इसके बड़े विदेशी मुद्रा भंडार ने वैश्विक झटकों के दौरान मुद्रा की अस्थिरता को नियंत्रित करने तथा विश्वास को मजबूत करने में मदद की है। साख तय करने वाली एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने मंगलवार को यह बात कही। एजेंसी ने कहा कि स्पष्ट एवं भरोसेमंद मौद्रिक नीति रूपरेखा, मुद्रास्फीति अपेक्षाओं का स्थिर रहना और जरूरत पड़ने पर विनिमय दरों का समायोजित हो पाना, इन सभी कारणों से भारत भविष्य के झटकों से निपटने के लिए अच्छी स्थिति में है।

भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट संभव

समरकंद (उजबेकिस्तान), एजेंसी। पश्चिम एशिया में तनाव के दुष्प्रभावों की वजह से चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 0.6 प्रतिशत घटकर 6.3 प्रतिशत रह सकती है और महंगाई में भी खासी बढ़ोतरी हो सकती है।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के मुख्य अर्थशास्त्री अल्बर्ट पार्क ने मंगलवार को कहा कि यह आकलन एडीबी के मॉडल-आधारित परिदृश्य पर आधारित है और अगले वित्त वर्ष में वृद्धि पर इसका नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था अगले वर्ष फिर संभल सकती है।

किरण मजूमदार ने भतीजी को उत्तराधिकारी बनाया

चर्चा में चेहरा

किरण मजूमदार

क्लेयर मजूमदार

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है और कंपनी की कमान युवा पीढ़ी को हाथ सौंपने की तैयारी कर ली है। उन्होंने अपनी भतीजी क्लेयर मजूमदार को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है।

चार दशक से अधिक पहले बायोकॉन की स्थापना करने वाली किरण मजूमदार-शॉ निःसंतान हैं। एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मैं बायोकॉन की एकमात्र मालकिन हूं और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी सही हाथों में जाए। इसलिए मैंने अपनी भतीजी क्लेयर को अपना उत्तराधिकारी चुना है, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है कि वह एक कंपनी बहुच अच्छी तरह से चला सकती हैं। किरण मजूमदार के अनुसार, उनकी कोशिश है कि बायोकॉन को विकास के नए चरण तक ले जाया जाए। कंपनी का ध्यान एडवांस बायोटेक और एआई की मदद से विकास करने पर है।

उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में क्लेयर के भाई एरिक मजुमदार और क्लेयर के पति थॉमस रॉबर्ट्स बायोकॉन की पारिवारिक पृष्ठभूमि को मजबूत करेंगे। बॉयोकान की स्थापना बैंगलुरु में साल 1978 में हुई थी। यह फार्मा सेक्टर की अग्रणी कंपनी है, जिसका मौजूदा बाजार पूंजीकरण करीब 60 हजार करोड़ रुपये के आसपास है। यह कंपनी सिर्फ भारत ही नहीं, कई और देशों में अपना कारोबार करती है।

कौन हैं क्लेयर

क्लेयर बिकारा थेरप्टिक्स नाम की एक अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी की कमान संभालती हैं, जिसे बायोकॉन ने ही वित्तीय मदद देकर तैयार किया है। 2024 में नैस्डैक पर सूचीबद्ध हुई बिकारा का कुल बाजार पूंजीकरण 1.6 अरब डॉलर से अधिक है। क्लेयर ने अमेरिका के एमआईटी से बायोलॉजिक इंजीनियरिंग में स्नातक किया है। साथ ही एमबीए की डिग्री हासिल की। इतना ही नहीं स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन से कैंसर बायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि भी ली।

कॉरपोरेट कॉर्नर

पंजाब नेशनल बैंक ने 220 स्थानों पर मेगा एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया। एमडी एवं सीईओ अशोक चंद्र के नेतृत्व में हुए इस अभियान में कार्यकारी निदेशकों व वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लेकर उद्यमियों को वित्तीय समाधान से जोड़ने का प्रयास किया।

उत्तर रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी कुलतार सिंह 35 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। बड़ौदा हाउस स्थित मुख्यालय में आयोजित समारोह में उन्हें विदाई दी गई। इस अवसर पर अपर महाप्रबंधक हर्ष खरे ने उनके योगदान की सराहना की और सम्मानित किया। समारोह में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

आरईसी ने ₹16,282 करोड़ का सर्वाधिक मुनाफा दर्ज किया

नई दिल्ली। आरईसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2025-26 में ₹16,282 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक शुद्ध लाभ अर्जित किया। कंपनी ने ₹18.55 प्रति शेयर का कुल लाभांश भी घोषित किया। ऋण पोर्टफोलियो ₹5.84 लाख करोड़ के उच्च स्तर पर पहुंचा, जबकि एनपीए लगभग शून्य (0.12%) रहा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऋण बढ़कर ₹75,347 करोड़ हो गया। मजबूत वित्तीय स्थिति और सतत विकास रणनीति ने इसे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में अग्रणी बनाए रखा।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने बढ़ती एलपीजी मांग के बीच आपूर्ति बनाए रखी

मुंबई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने देशभर में बढ़ती एलपीजी मांग के बीच मजबूत प्रबंधन से आपूर्ति सुचारु रखी। 1 से 28 अप्रैल के बीच 349 लाख सिलेंडर वितरित किए गए, जबकि 28 अप्रैल को 13.8 लाख सिलेंडर की आपूर्ति हुई। कंपनी ने 2,06,985 टैंकरों की तैनाती कर वितरण तंत्र को मजबूत किया। डिजिटल बुकिंग प्रणाली के माध्यम से 99.3 प्रतिशत ऑर्डर ऑनलाइन प्राप्त हुए। निगरानी बढ़ाते हुए 6,150 निरीक्षण और कई कार्रवाई की गईं।

दिलीप कुमार बने सेल के मुख्य सतर्कता अधिकारी

नई दिल्ली। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के वरिष्ठ अधिकारी दिलीप कुमार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद संभाल लिया है। उन्हें रेलवे में ट्रेन संचालन, रोलिंग स्टॉक रखरखाव और मानव संसाधन प्रबंधन का 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में राजेश अग्रवाल बने निदेशक

नई दिल्ली। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने राजेश कुमार अग्रवाल को 23 अप्रैल 2026 से निदेशक (वित्त) नियुक्त किया है। इससे पहले वे पीएफसी में कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यरत थे। उन्हें ऊर्जा और वित्त क्षेत्र में 31 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इससे पूर्व एनटीपीसी, एनपीसीआईएल और डीटीएल में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।

पीएसई में कोचिंग पर स्कोप-आईसीएफ का बड़ा अध्ययन शुरू

नई दिल्ली। सार्वजनिक उपक्रमों के शीर्ष संगठन स्कोप और इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन (आईसीएफ), अमेरिका ने भारतीय पीएसई में कोचिंग की स्थिति पर एक व्यापक अध्ययन शुरू किया है। इसका उद्देश्य वर्तमान कोचिंग प्रणाली और संगठनात्मक संस्कृति को समझना है। अध्ययन के आधार पर एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे पीएसई में आंतरिक कोचिंग क्षमता विकसित की जा सके। इसके लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़े जुटाए जाएंगे।

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राज्य मंत्री तोखन साहू एवं सचिव श्रीनिवास कातिकीथला सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर शहरी चुनौती निधि और शहरी निवेश खिड़की पहल पर संगोष्ठी आयोजित हुई।

बीआईएस ने सहायक उत्पादों के लिए छह नए मानक जारी किए

नई दिल्ली। भारतीय मानक ब्यूरो ने सहायक उत्पादों के लिए छह नए मानक जारी किए हैं। बैसाखी, चलने की छड़ी, बहु-पैर वाली छड़ी, व्हीलचेयर के लिए पोर्टेबल रैंप तथा ब्रेल संकेत और स्पर्शनीय मार्गदर्शिका मानचित्र शामिल हैं। ये मानक सुरक्षा, प्रदर्शन और गुणवत्ता से जुड़े दिशा-निर्देश तय करते हैं। यह पहल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एनएलईएपी योजना के तहत तकनीकों के विकास और दिव्यांगजनों तथा बुजुर्गों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

दैनिक जागरण

शिक्षा में किया निवेश जीवनपर्यंत प्रतिफल प्रदान करता है

आदत से लाचार राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश की समस्याओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को जिस तरह गद्दार करार दिया, उससे एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें रह-रह कर कुछ बेतुके, आपत्तिजनक और अमर्यादित बयान देने की आदत पड़ गई है और वे इस आदत से लाचार भी हो गए हैं। विशेष बात यह है कि वे कई बार अपने भोंडे और ओछे बयान दोहराते भी रहते हैं और यह प्रतीति भी कराते हैं मानो उन्होंने कोई बहादुरी का काम कर दिखाया हो। उन्होंने गद्दार वाले अपने बयान को दोहराते हुए कहा, 'आरएसएस वालों सुन लो, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। मैं फिर कहता हूं कि मोदी और शाह गद्दार हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान पर हमला किया है।' संविधान खतरे में है, उनका पुराना जुमला है। इसे वे जाने कितनी बार दोहरा चुके हैं। इसी तरह वे एक समय चौकीदार चोर है... का जुमला दोहराते थे। वे प्रधानमंत्री को सैनिकों के खून की दलाली करने वाला और न जाने क्या-क्या कह चुके हैं। हालांकि राहुल गांधी के ऐसे अशोभनीय बयान उन पर ही भारी पड़े हैं, लेकिन वे कुछ समझने के लिए तैयार नहीं।

ऐसा लगता है कि अपनी राजनीतिक विफलताओं से हताश और कुंठित होकर राहुल गांधी इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री को गाली देने से उनकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी और वे राजनीतिक रूप से उनका मुकाबला करने में सक्षम हो जाएंगे। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि ओछी और अपमानजनक बयानबाजी विरोध अथवा आलोचना का पर्याय नहीं हो सकती। समस्या यह है कि राहुल यह साधारण सी बात समझने को तैयार नहीं कि राजनीति की अपनी एक भाषा होती है और आलोचना-निंदा का यह मतलब नहीं होता कि किसी के प्रति अशोभनीय टिप्पणियां की जाने लगें। चूंकि वे अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, इसलिए इसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि वे किसी से कुछ सीखेंगे, लेकिन कम से कम उन्हें अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से तो यह सीखना ही चाहिए कि शब्दों की मर्यादा लांघे बिना प्रधानमंत्री अथवा उनके सहयोगियों की कड़ी आलोचना कैसे की जा सकती है? इसमें कोई संदेह नहीं कि राहुल की तुलना में प्रियंका कहीं अधिक प्रभावी वक्ता हैं। राहुल अपने बेतुके बयानों से चर्चा में अवश्य आ जाते हैं, लेकिन इससे उन्हें राजनीतिक रूप से कुछ हासिल नहीं होता। उनकी छवि अक्खड़, अशिष्ट और अगंभीर नेता के रूप में ही अधिक उभरती है। उनकी एक समस्या यह भी है कि वे ऐसे नेताओं से घिरे हैं, जो उनके हर बेतुके बयान की केवल वाह-वाही ही नहीं करते, बल्कि उनमें इसके लिए होड़ भी मचती है कि कौन कितनी अधिक अशिष्ट बयानबाजी कर सकता है।

जीवन होगा आसान

बिहार में सम्राट चौधरी सरकार ने सात निश्चय (तीन) के अंतर्गत सबका सम्मान, जीवन आसान के लक्ष्य पर काम शुरू कर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि विकास का वास्तविक अर्थ जनता की खुशहाली और सम्मान से जुड़ा है। पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर इसका सकारात्मक उदाहरण है। राशन कार्ड, पेंशन, प्रमाण पत्र, जमीन विवाद और अन्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं अक्सर लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती रही हैं। ऐसे में पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर प्रशासन को जनता के दरवाजे तक पहुंचाने की पहल सराहनीय है। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा और लोकतंत्र की भावना मजबूत होगी। हालांकि इसके पहले भी जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी जाती थीं, लेकिन उनका समुचित निदान कम ही हो पाता था। मंत्री से लेकर जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों तक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह तय किया गया है कि शिविर में आने वाली शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों में करना होगा। व्यवस्था प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने वाली है। क्रियान्वयन के जरिये जनता में यह भरोसा पैदा करना होगा कि सरकार उनका जीवन बेहतर बनाने के प्रति गंभीर है। सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित होने से काम में भी तेजी आएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था के फिर से लागू होने से लोगों की अनेक प्रकार की शिकायतों का समाधान संभव होगा।

> लोकतंत्र की सफलता केवल योजनाएं बनाने में नहीं, बल्कि उनको जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में है

विकृत सोच से उपजा सनातन विरोध

निरंजन कुमार

यह विडंबना ही हैं कि जो सनातन परंपरा अपने मूल में सर्वाधिक सहिष्णु, उदार और समावेशी हैं, उसी पर सर्वाधिक प्रहार किया जाता हैं

अवधेश राजपूत

वैश्विक विचार श्रृंखला को भारत की एक अनुपम भेंट है- सनातन धर्म, जो मूल रूप से समावेशी, सहिष्णु, शांतिप्रिय और सर्वकल्याणकारी है। दुर्भाग्य से विदेशी विचारधाराओं ने सनातन धर्म के विरुद्ध एक मुहिम छेड़ रखी है। इन विदेशी षड्यंत्रों के प्रभाव और राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत भारत में भी कुछ राजनीतिक दलों और तथाकथित बुद्धिजीवियों ने सनातन धर्म के विरुद्ध मोर्चा खोला हुआ है। इसका ताजा उदाहरण है पिछले दिनों तमिलनाडु विधानसभा में द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन का विषवमन कि सनातन को मिटा देना चाहिए। उनके अनुसार सनातन समाज को बांटता है। पहले भी उदयनिधि या ऐसे लोग सनातन विरोधी बयान देते रहे हैं। ऐसे खतरनाक वक्तव्यों के पीछे दुर्भावना और राजनीतिक स्वार्थ के साथ ही सनातन धर्म को लेकर एक विकृत समझ भी है।

'सनातन' शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा की 'सद' धातु से हुआ है। पाणिनि सूत्र के अनुसार 'सद' धातु पर 'नुम्' प्रत्यय लगकर 'सना' शब्द बनता है, जिसका अर्थ है 'शाश्वत' या 'सदा रहने वाला' जबकि 'तन' का अर्थ है विस्तारित। इस प्रकार सनातन का अर्थ है-जो शाश्वत रूप से विस्तारित और प्रवाहित है। कहा भी गया है, 'सनातनस्य धर्मः इति सनातन धर्मः' अर्थात् जो सदा से है और सदा रहेगा, वही सनातन है। इसका न कोई आदि (शुरुआत) है और न अंत। सनातन विरोधियों को समझ लेना चाहिए कि जिस सनातन धर्म का कोई आदि और अंत नहीं, जो शाश्वत और चिरंतन है, उसे मिटाने या नष्ट करने की कल्पना एक दिवास्वप्न ही है। अतीत में भी सिकंदर, मिहिरकुल, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, खिलजी, चंगेज खां, तैमूर लंग, बाबर, औरंगजेब आदि ने भी सनातन धर्म-संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन आज भी सनातन धर्म अपराजेय खड़ा है।

सनातन की चिरंतनता का आधार है कुछ ब्रह्माण्डीय नियम, जो सार्वदेशिक, सर्वकालिक और सार्वभौमिक हैं। ये नियम हैं-सत्य, कर्म, कर्तव्य, नैतिकता, सदाचार, सर्वकल्याण, सहिष्णुता, प्रकृति-पूजा और भक्ति इत्यादि। अर्थात सनातन केवल एक धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की समग्र पद्धति भी है। सनातन धर्म से इस्लाम या ईसाइयत आदि रिलीजन या मजहब काफी अलग हैं, जो एक पैगंबर, एक किताब या एक विशिष्ट पूजा-उपासना पद्धति पर आधारित हैं और अन्य को स्वीकार नहीं करते। जबकि सर्वसमावेशी सनातन धर्म में सभी के कल्याण की कामना के साथ समूची पृथ्वी को ही अपना परिवार मानने की परंपरा रही है। फिर भी, दुर्भावनावश सनातन धर्म को विभाजनकारी या भेदभावपूर्ण कहा जाता है? इस सनातन धर्म को बाद में हिंदू धर्म भी कहा जाने लगा। समय के साथ इसमें जाति प्रथा जैसी कुछ बुराइयां भी प्रविष्ट कर गईं, जिनका आंतरिक स्तर पर विरोध भी हुआ। ऐसे में कुछ बुराइयों के कारण संपूर्ण सनातन धर्म को ही मिटा देने की बात करना घोर निंदनीय है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मार्क्सवाद एवं अन्य विदेशी विचारधाराओं के साथ-साथ तुष्टीकरण की राजनीति के कारण द्रमुक ही नहीं, कुछ अन्य दल भी सनातन या हिंदू धर्म की अवमानना करते रहते हैं। इससे पहले 2023 में भी उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, 'जिस प्रकार मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को समाप्त किया जाता है, उसी प्रकार सनातन धर्म का केवल विरोध करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए।' मद्रास उच्च न्यायालय ने उनके इस बयान को 'हेट स्पीच' के समान बताया था। अफसोस की बात है कि इस बयान पर कांग्रेस और अन्य दलों की मौन सहमति सी रही। उदयनिधि के हालिया बयान की निंदा करने के बजाय कांग्रेस ने इसे उनका 'निजी विचार' या 'क्षेत्रीय राजनीति' करार देकर किनारा कर लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे प्रियांक खरगे ने तो उदयनिधि के बयान का परोक्ष रूप से समर्थन ही किया था। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी उदयनिधि के बयान की निंदा करने के बजाय धर्म को एक व्यक्तिगत विषय बताकर कन्नी काट ली। उलटे अखिलेश यादव ने तो स्वयं सनातन पर परोक्ष प्रहार किए थे। अयोध्या में राम मंदिर के प्रश्न पर मई 2022 में उन्होंने कहा, 'हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा लगा दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाता है।' यह टिप्पणी हिंदू आस्था का उपहास ही थी। इसी तरह 2025 में अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें सुगंध पसंद है, इसलिए उनकी सरकार ने कन्नौज में इत्र पार्क बनाया, जबकि भाजपा 'दुर्गंध' पसंद करती है तो गौशालाएं बनवा रही है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से प्रेरित राजनीति में यह प्रवृत्ति नई नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोली चलवाने के बचाव में कहा था कि अगर गोली नहीं चलती तो मुसलमानों का देश से विश्वास उठ जाता।

सनातन पर प्रहार को लेकर कांग्रेस का इतिहास भी ऐसा ही रहा है। इस क्रम में इंदिरा गांधी द्वारा नवंबर 1966 में गौ-भक्तों पर गोली चलवाना, 2007 में रामसेतु प्रकरण में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार द्वारा न्यायालय में श्रीराम से संबंधित घटनाक्रम को ऐतिहासिक प्रमाण मानने से शुरू में इनकार करना या फिर अप्रैल 2025 में अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा प्रभु श्रीराम को एक मिथकीय पात्र बताने जैसे कई उदाहरण हैं।

जो सनातन परंपरा अपने मूल में सर्वाधिक सहिष्णु, उदार और समावेशी है, उसी पर सर्वाधिक प्रहार किया जाता है। जबकि ये राजनीतिक दल कट्टरपंथी विचारधाराओं के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलते। वहां विरोध करने पर हिंसक प्रतिक्रियाओं का भय रहता है। 'गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा' जैसे कट्टर नारों पर तथाकथित पंथनिरपेक्ष और प्रगतिशील राजनीति प्रायः मौन रहती है। आज जबकि विश्व आतंकवाद, हिंसा, युद्ध, सांस्कृतिक असहिष्णुता और सामाजिक विघटन जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है तब ऐसी स्थिति में मानव सभ्यता के लिए एक संतुलित और टिकाऊ समाधान सनातन के मार्ग से ही निकलेगा। सनातन धर्म को मिटाने या अवमानना करने वालों को यह ठीक से समझ लेना चाहिए।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

आसान होती अच्छी शिक्षा तक पहुंच

विदेशी शिक्षण संस्थानों का आगमन भारतीय संस्थानों की जगह नहीं लेता, बल्कि छात्रों को नए विकल्प देता हैं

प्रमथ राज सिन्हा

एक समय था जब भारतीय युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा की डगर बहुत कठिन हुआ करती थी। फीस, रहने का खर्च और वीजा की लागत तो ज्यादा थी ही, साथ ही उन्हें भाषा की दिक्कतों और परिवार से दूर रहने जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। विदेश जाकर पढ़ाई करना हर किसी के लिए संभव नहीं था। हालांकि यह अब भी आसान नहीं, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं के लिए नए अवसर आ गए हैं। दुनिया की प्रमुख शिक्षा संस्थाएं अब भारत की ओर रुख कर रही हैं और अपने कैंपस यहां खोल रही हैं। भारत ने भी उन्हें यहां लाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। किसी संस्थान को यहां आने के लिए दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में होना चाहिए या उस संस्थान की किसी खास विषय में असाधारण विशेषज्ञता होनी चाहिए। कई संस्थाओं ने भारत में अपने कैंपस खोल दिए हैं या खोलने की घोषणा कर दी है। उदाहरण के लिए, यूनिवर्सिटी आफ एबरडीन की पांच सौ साल की शैक्षणिक विरासत है। यूनिवर्सिटी आफ साउथैंपटन के दुनिया भर में 2.85 लाख से अधिक पूर्व छात्र हैं।

यूनिवर्सिटी आफ वोलोंगोंग का मानना है कि अच्छी विश्वस्तरीय शिक्षा और वैश्विक करियर हर छात्र की पहुंच में होने चाहिए, चाहे वह कहीं भी हो। ये विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान अपने साथ गहरा अनुभव और शैक्षणिक व्यवस्था ला रहे हैं। वे भारत में ऐसे आधुनिक विषय पढ़ा रहे हैं, जो भारत के युवाओं के लिए उत्साहपूर्ण और उपयोगी हैं, जैसे टेक्नोलाजी, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस और फाइनेंस। एक समय था जब इन संस्थानों में पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ता था। अधिकांश भारतीय परिवारों के लिए यह न तो किफायती था और न सुलभ। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के भारतीय कैंपस में पढ़ने वाला छात्र वही डिग्री पाता है, जो उसे विश्वविद्यालय के मूल कैंपस में पढ़ने पर मिलती। इससे छात्रों के लिए न सिर्फ खर्च कम हुआ है, बल्कि कई संस्थान तो अपने शुरुआती वर्षों में छात्रवृत्तियां भी दे रहे हैं। कुछ को मिलने वाले अवसर अब सबके लिए उपलब्ध हैं।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना आवश्यक। फाइल

भारत एक युवा देश है और अच्छी उच्च शिक्षा देश की राष्ट्रीय आवश्यकता है। यहां लाखों ऐसे सक्षम और मेहनती छात्र हैं, जिन्हें सीटों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण उत्कृष्ट संस्थानों में जगह नहीं मिल पाती। भारत में अपनी क्षमता बढ़ा रहे अंतरराष्ट्रीय संस्थान भारत की इस वास्तविक और तात्कालिक आवश्यकता को भी पूरा कर रहे हैं। उनका आगमन भारतीय संस्थानों की जगह नहीं लेता, बल्कि भारतीय छात्रों को नए विकल्प देता है। इस दृष्टि से इनका आना शिक्षा क्षेत्र में एक आवश्यक कदम है। क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ विविधता भी महत्वपूर्ण है।

जहां एक तरफ भारतीय उच्च शिक्षा कुछ क्षेत्रों में उत्कृष्ट है, वहीं दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें विकास की आवश्यकता है। विदेशी संस्थान अपने साथ भिन्न-भिन्न बौद्धिक माहौल में विकसित अध्ययन शैली, शोध की परंपरा और नई पाठ्यक्रम संरचनाएं लाते हैं। इससे छात्र प्रश्न करने और अपने विचार रखने के नए तरीके सीखते हैं, जिससे पूरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलती है। जब ऊंची रैंक वाले संस्थान भारत में आते हैं, तो वे अपने साथ अपेक्षाओं के ऊंचे मानक भी लाते हैं और शिक्षा क्षेत्र के लिए उदाहरण बनते हैं। पहले भी कारपोरेट जगत में ऐसा हुआ है। वैश्विक कंपनियों के भारत आने पर भारतीय उद्योग खत्म नहीं हुए, बल्कि और बेहतर बने। सबमें सुधार का दबाव बना और जो कंपनियां बदलाव ला पाईं, वे और भी मजबूत हुईं। संभव है ऐसा शिक्षा के क्षेत्र में भी हो।

अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का भारतीय कैंपसों में निवेश करना इसका प्रमाण है कि वे भारत के भविष्य में भागीदारी चाहते हैं। अभी तक सबसे ज्यादा रुचि ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया से आई है, लेकिन दूसरे देश भी आगे आ रहे हैं। सिंगापुर, यूएई और चीन जैसे देशों ने वर्षों पहले समझ लिया था कि विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से देश शिक्षा का केंद्र बनता है। भारत भी इस दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। अब दूसरे देशों विशेषकर करीबी देशों के छात्र भारत को केवल भारतीय संस्थानों के लिए नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में भी देख सकेंगे। इससे उद्योग में सहयोग, शोध साझेदारी, बेहतर रोजगार जैसी नई संभावनाएं खुलेंगी।

विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से देश में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि वैश्विक शैक्षिक जीवन और भारतीय बौद्धिक शक्ति साथ-साथ आगे बढ़ेंगी। इस नए अवसर में स्पष्ट नियम व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय रुचि, युवा आबादी की मांग और नीतिगत समर्थन, सब एक साथ एक बिंदु पर मिल रहे हैं और यह कोई मामूली बात नहीं। यह भारत के भविष्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए सक्रिय निर्णयों का परिणाम है। प्रश्न यह है कि इस अवसर का कार्यान्वयन कैसा होगा? क्या आने वाले शिक्षण संस्थान अपने ऊंचे मानक बनाए रखेंगे? क्या हर क्षेत्र और हर आय वर्ग के छात्रों को इन अवसरों का लाभ मिलेगा? और क्या पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था अपने आप को नए स्तर के अनुरूप तेजी से ढाल पाएगी?

(लेखक अशोका यूनिवर्सिटी, दिल्ली-एनसीआर के संस्थापक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन जीने की कला

एक ऐसे समय जब बाहर का तापमान अंगारों को छू रहा है, तब अगर भीतर का तापमान भी आग उगलने लग जाए तो हमारा झुलसना तय है। इस तपिश का असर हमारे तन-मन के साथ ही करीबियों को भी होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मानव मन सांसारिक विषयों के सुख को भोगने की इच्छा करता हैं और इस इच्छा में बाधा आती है या वे पूर्ण नहीं होतीं तो स्वभाव में नरमी-गर्मी होना भी स्वाभाविक है। हमारी भोग की प्यास की यही तीव्रता हमें इतना स्वार्थी बना देती है कि हमें किसी और की प्यास महसूस ही नहीं होती है। इस 'मैं और मेरे' की चिंता और तनाव से तपते इस मरू में थोड़ी सी शीतल चांदनी का समावेश ही सार्थक होगा। इसके लिए सबसे पहले अपने मन के ताप को नियंत्रित करें। अगर मन को शांत रखा जाए तो हर स्थिति में आनंद ही आनंद है।

हमारा चेहरा हमारे अंदर के सच का आईना होता है। मन के विचारों की छाया को चेहरे पर उतरने से रोकना संभव नहीं। इसलिए अच्छा सोचते ही हमारा व्यक्तित्व भी खिलखिला उठता है। हमारा व्यवहार और व्यक्तित्व सौम्य बन जाता है। उदासी के माहौल में हास्य की लहर से बिखरती मुस्कान नकारात्मकता की तपन को सकारात्मकता की ठंडक में बदल देती है। किंतु कई बार भरसक प्रयास करने पर भी कतिपय अज्ञानता और परिस्थितिवश हमारी छवि नकारात्मक दिखने लगती है। तनिक भी ऐसा आभास हो तो अपने सोच-विचार में अपेक्षित परिवर्तन लाएं। कामना पूर्ति के पीछे हम क्रोध, नफरत, लालच और विषाक्त विचारों के बीच फंसकर जीने का सही तरीका ही भूल गए हैं। हर परिस्थिति में जीवन के पक्षों में संतुलन साधने की समझ के साथ जीवन के उतार-चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करना और वर्तमान में जीना ही जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है।

डा. निर्मल जैन

आतंकवाद के विरुद्ध स्पष्ट नीति

डा. आशीष त्रिपाठी

आतंकवाद-रोधी दिवस

आतंकवाद के विरुद्ध सभी देशों को साथ मिलकर कार्रवाई करनी होगी ताकि इसका समूल नाश किया जा सके

आतंकवाद समकालीन विश्व की सबसे ज्वलंत एवं जटिल समस्याओं में से एक है यह एक ऐसी समस्या है जिसने समूचे विश्व को अपने प्रकोप से प्रभावित किया हुआ है। हमारा देश भारत भी आतंकवाद जैसी समस्या से ग्रसित है और हम दशकों से इस समस्या से लड़ते आ रहे हैं। भारत में अस्थिरता लाने और देश में अशांति फैलाने के उद्देश्य से भीषण आतंकवादी हमले किए गए। यहां तक हमने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी इसी घटना में खो दिया। यह घटना भारत के इतिहास में सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक थी थी। लिहाजा 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी दिवस के रूप में घोषित किया।

वैसे भारत में होने वाली इन सभी आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की षड्यंत्रकारी भूमिका रही है। इसी कारण से इतने वर्षों के संघर्ष के बाद भी आतंकवाद देश के लिए एक नासूर बना हुआ है। पिछले वर्ष कश्मीर के पहलगाम में आम पर्यटकों पर हुआ हमला भी बहुत दर्दनाक था जिसने मानव जाति की सभी संवेदनाओं को नष्ट कर दिया था। इस हमले में निर्दोष लोगों से उनका धर्म पूछ कर उनके परिवार के सामने उन पर गोलियां बरसाई गई थीं। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना में 26 पर्यटकों को मार दिया गया था। इस घटना के माध्यम से दंगे को भड़काकर समाज का सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र भी रचा गया था, परंतु देश ने बड़े ही संयम से काम लिया और इस घटना को अंजाम देने वाली पाकिस्तान में बैठी ताकतों को उनकी ही भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया।

भारत की वायु सेना ने अदम्य साहस और पुरुषार्थ का परिचय देते हुए पाकिस्तान में घुसकर बहावलपुर और मुरीदके जैसे बड़े आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया और सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। भारत की सरकार के इस मजबूत इरादे और सेना की बहादुरी को पूरी दुनिया ने देखा और सराहा। यह अपने आप में एक बदलते हुए नए भारत की तस्वीर है। यही नहीं, भारत ने कूटनीतिक कदम उठाते हुए एक संसदीय दल को विश्व के अनेक देशों में भेजा और पाकिस्तान के सरकार समर्थित आतंकवाद का पर्दाफाश किया। इस दल में अनेक राजनीतिक दलों के सदस्यों ने भाग लिया और भारत की बात को अंतरराष्ट्रीय पटल पर रखा।

भारत के प्रधानमंत्री अनेक मंचों से आतंकवाद के विरुद्ध स्पष्ट मत प्रकट करते रहते हैं। वह आतंकवाद के विरुद्ध 'जीरो टालरेंस' की नीति की वकालत करते हैं। समूचे विश्व को मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता का परिचय देते हुए ठोस कदम उठाने चाहिए और इसका समूल नाश करना चाहिए।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

भारत को साधना होगा संतुलन

श्रीराम चौलिया का आलेख 'अमेरिका-चीन संबंधों के नए समीकरण' केवल दो महाशक्तियों के संबंधों का विश्लेषण नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था की धड़कनों को समझने का एक गंभीर प्रयास भी है। आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति उस मोड़ पर खड़ी है, जहां वैचारिक नारों से अधिक महत्व आर्थिक हितों, तकनीकी प्रभुत्व और सामरिक संतुलन का हो गया है। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा अब केवल व्यापार युद्ध तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री नियंत्रण, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और भू-राजनीतिक प्रभाव के वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। विडंबना यह है कि दोनों एक-दूसरे को रणनीतिक खतरा बताते हैं, फिर भी दोनों की अर्थव्यवस्थाएं इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि पूर्ण टकराव स्वयं उनके लिए अहितकारी सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि बयानबाजी में आक्रामकता और व्यवहार में व्यावहारिकता दिखाई देती है। भारत के लिए यह समय अत्यंत संवेदनशील और निर्णायक है। एक ओर चीन की विस्तारवादी नीति, सीमा विवाद और हिंद महासागर में उसकी बढ़ती सक्रियता चिंता का विषय है, तो दूसरी ओर अमेरिका भी अपने सामरिक हितों के अनुरूप ही मित्रता निभाता है। इतिहास गवाह है कि महाशक्तियां नैतिकता नहीं, बल्कि अपने व्यापक हितों के अनुसार ही संबंध तय करती हैं। इसलिए भारत को किसी भी शक्ति-गुट का 'उपकरण' बनने के बजाय स्वयं को एक स्वतंत्र, निर्णायक और संतुलित वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना होगा। आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता भावनात्मक विदेश नीति नहीं, बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता है। क्वाड, ब्रिक्स, जी-20 या इंडो-पैसिफिक-प्रत्येक मंच पर भारत को अपने हितों की स्पष्ट रेखा खींचनी होगी। यदि भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता, आर्थिक मजबूती और सामरिक क्षमता को समानांतर रूप से विकसित करता है, तभी वह अमेरिका-चीन संघर्ष के बीच अवसरों को अपने पक्ष में परिवर्तित कर सकेगा। वर्तमान विश्व व्यवस्था में वही राष्ट्र सम्मान पाता है जो दबाव में झुकता नहीं, बल्कि संतुलन के साथ अपनी दिशा स्वयं तय करता है। भारत को अब प्रतिक्रियावादी नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन का निर्णायक निर्माता बनने की आवश्यकता है।

बिमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

मेलबाक्स

न्यायालय के निर्णय का स्वागत

आवारा आतंक पर सख्ती- शीर्षक से प्रकाशित अग्रलेख पढ़ा। यह विषय आज देश के करोड़ों नागरिकों की सुरक्षा और चिंता से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेबीज से पीड़ित, हिंसक एवं खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति दिया जाना वास्तव में एक अत्यंत आवश्यक और सराहनीय फैसला है। आज देश के अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में आवारा कुत्तों का आतंक गंभीर रूप धारण कर चुका है। आजकल कहीं भी किसी समय कुत्ते लोगों पर हमला कर देते हैं, जो कई बार घायल भी कर देता है। स्कूल जाते छोटे बच्चे, वृद्धजन, महिलाएं और राहगीर आए दिन इनके हमलों का शिकार हो रहे हैं। कई मामलों में रेबीज जैसी लाइलाज बीमारी के कारण लोगों की दर्दनाक मृत्यु तक हो चुकी है। इसके बावजूद कुछ तथाकथित ''डाग लवर'' केवल भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर मानव जीवन की सुरक्षा को नजरअंदाज करते दिखाई देते हैं। यदि किसी को वास्तव में इन कुत्तों से इतनी हमदर्दी है तो उन्हें सड़कों पर खुला छोड़ने के बजाय स्वयं उनकी देखभाल और पालन-पोषण की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, रेलवे एवं बस स्टेशनों पर आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय मानव जीवन की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय इस आदेश को कठोरता एवं गंभीरता से लागू करें, ताकि आमजन भयमुक्त वातावरण में जीवन यापन कर सकें।

सुरेश गोयल धूप वाला, हिसार, हरियाणा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एजीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

22 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे इस माह आयोजित नीट की परीक्षा में, जिसे पेपर ली की आशंका के कारण रद कर दिया गया और अब 21 जून को दोबारा इसकी परीक्षा कराए जाने का कार्यक्रम है।

आजकल

प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पारदर्शी व्यवस्था

प्रो. श्रीप्रकाश सिंह
कुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड

भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं केवल चयन की प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि युवाओं के भविष्य और देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ी हुई हैं। विशेष रूप से नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षा, जिसके माध्यम से लाखों विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा में प्रवेश पाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जब पेपर लीक जैसी गंभीर शिकायतें सामने आती हैं, तो परीक्षा व्यवस्था के प्रति भरोसा डगमगाता है। परंतु केंद्र सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से यह भी पता चलता है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था की निष्पक्षता को लेकर गंभीर है

नीट यूजी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका के कारण इसे रद करते हुए दोबारा से आयोजित की जाएगी परीक्षा। फाइल

पिछले लंबे समय से केंद्र सरकार लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि जैसे ही परीक्षा में अनियमितताओं की जानकारी सामने आई, सरकार ने मामले को केवल एक प्रशासनिक त्रुटि मानकर छोड़ने के बजाय कठोर कदम उठाए। परीक्षा रद करना और तुरंत सीबीआइ जांच के आदेश देना यह स्पष्ट करता है कि सरकार व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए राजनीतिक जोखिम उठाने से भी पीछे नहीं हटना चाहती। यह निर्णय आसान नहीं था। परीक्षा रद होने से लाखों विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी है, मानसिक दबाव बढ़ा है और कई परिवारों को अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पड़ेगा। लेकिन सरकार ने यह समझा कि यदि थोड़े समय की असुविधा सहकर पूरी व्यवस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बचाया जा सकता है, तो वही लोकतांत्रिक रूप से उचित कदम होगा। यदि सरकार केवल सीमित कार्रवाई करती या शिकायतों को नजरअंदाज करती, तो छात्रों और अभिभावकों के बीच यह संदेश जाता कि व्यवस्था भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन है।

प्रतियोगी परीक्षाएं केवल विद्यार्थी ही नहीं देते, बल्कि उनके साथ पूरा परिवार इस प्रक्रिया से गुजरता है। माता-पिता अपनी आर्थिक सीमाओं के बावजूद बच्चों की कोचिंग, पढ़ाई और रहने की व्यवस्था में वर्षों तक मेहनत करते हैं। परिवार अपनी उम्मीदों, सपनों और त्याग को इन परीक्षाओं से जोड़ कर देखता है। ऐसे में जब परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न उठते हैं, तो केवल एक विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित होता है। केंद्र सरकार ने इसी सामाजिक और भावनात्मक पक्ष का सम्मान करते हुए परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को सर्वोपरि मानकर परीक्षा रद करने तथा उच्चस्तरीय जांच कराने का निर्णय लिया। यह कदम इस भावना को स्वीकार करने वाला था कि युवाओं की मेहनत के साथ किसी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यदि नकल माफिया और भ्रष्ट तंत्र सफल हो जाता तो परिश्रम और लगन से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता। उल्लेखनीय है कि सरकार लंबे समय से पारदर्शी शासन और जवाबदेह प्रशासन के आधार पर लोगों के विश्वास को कायम रखने की बात करती रही है। नीट प्रकरण में सरकार की कार्रवाई इसी सोच का विस्तार दिखाई देती है। आज भारत में शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं का दायरा बहुत व्यापक हो चुका है। छोटे कस्बों, ग्रामीण इलाकों और गरीब परिवारों के बच्चे भी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में भाग लेते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता सामाजिक न्याय का भी प्रश्न बन जाती है। वर्तमान सरकार ने यह समझा कि यदि परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है, तो इसका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि युवाओं का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास भी प्रभावित होगा। इसलिए सरकार ने इसे प्राथमिकता के रूप में लिया।

नीट पर उठे सवालों के बीच भी सरकार ने सुधारात्मक कदमों की बात की और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने का आश्वासन दिया। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने भी अपना दायित्व समझा है। अब पुनः परीक्षा आयोजित हो रही है। इस अवसर का लाभ छात्रों को लेना चाहिए, इसी में उनका भविष्य है। सरकार ने दो स्तरों पर सार्थक प्रयास किया, एक ओर सघन जांच और कड़ी कार्रवाई, दूसरी ओर शांति और संस्थागत अनुशासन बनाए रखने का रचनात्मक प्रयास। यही कारण है कि सरकार ने इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बहस से दूर रखा। अनेक विपक्षी दलों ने इसे लेकर सरकार पर हमला किया, लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रशासनिक और कानूनी कदमों को प्राथमिकता दी।

डिजिटल इंडिया, आधार आधारित पहचान, आनलाइन प्रक्रियाओं और तकनीकी निगरानी के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करने की कोशिशें की गई हैं। इसलिए यह अपेक्षा भी स्वाभाविक है कि भविष्य में सरकार परीक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी, तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाएगी, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह कहना गलत नहीं होगा कि नीट विवाद सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण क्षण था। लेकिन संकट के समय किसी भी सरकार की वास्तविक परीक्षा होती है कि वह कितनी तेजी, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ प्रतिक्रिया देती है। केंद्र सरकार ने परीक्षा रद करने, सीबीआइ जांच शुरू करने और सुधारात्मक कदमों की घोषणा करके यह दिखाने का प्रयास किया कि वह युवाओं के प्रति गंभीर है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि नीट परीक्षा प्रकरण में सरकार का दृष्टिकोण, व्यवस्था की विश्वसनीयता बचाने और छात्रों का विश्वास बनाए रखने पर केंद्रित रहा है। लोकतंत्र में संस्थाओं की साख सबसे महत्वपूर्ण होती है और जब कोई संकट उस साख को चुनौती देता है, तब निर्णायक कार्रवाई आवश्यक हो जाती है। परीक्षा रद करना और उच्चस्तरीय जांच कराना इसी जिम्मेदारी का हिस्सा है। यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि करोड़ों विद्यार्थियों के सपनों, परिवारों के त्याग और देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता की रक्षा करने का प्रयास है।

प्रबंधन शिक्षा में केंद्रीकृत प्रवेश प्रणाली की पहल

डा. अतुल अग्रवाल
भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हालिया आयोजित आइआइएम समन्वय मंच की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य आइआइएम के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए केंद्रीकृत प्रवेश एवं काउंसलिंग प्रणाली लागू करने की संभावनाओं पर विचार करना था। यह चर्चा केवल प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था के भविष्य को अधिक सरल, पारदर्शी और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में एक संभावित ऐतिहासिक कदम हो सकता है।

यह विदित है कि भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने केवल उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक व्यापक और समावेशी बनाने की दिशा में भी गंभीर प्रयास किए हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान अर्थात आइआइएम इस परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में शामिल हैं। एक समय था जब आइआइएम केवल स्नातकोत्तर प्रबंधन शिक्षा तक सीमित माने जाते थे, लेकिन अब वे स्नातक और एकीकृत प्रबंधन कार्यक्रमों की दिशा में भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं। कई आइआइएम स्नातक तथा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार आइआइएम बेंगलुरु, कोझिकोड, लखनऊ, मुंबई, संभलपुर और सिरमौर जैसे संस्थान या तो स्नातक कार्यक्रम प्रारंभ कर चुके हैं या उनकी तैयारी कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अलग अलग संस्थान अलग अलग परीक्षाओं को स्वीकार करते हैं।

यह विविधता संस्थागत स्वतंत्रता और नवाचार का प्रतीक प्रतीत होती है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर यह छात्रों के लिए अत्यधिक जटिल और बोझिल व्यवस्था बन चुकी है। आज एक छात्र को केवल प्रबंधन शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनेक परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है। प्रत्येक परीक्षा का पाठ्यक्रम, आवेदन प्रक्रिया, शुल्क, परीक्षा तिथि और चयन प्रक्रिया अलग होती है। इसके बाद अलग अलग संस्थानों के लिए पृथक आवेदन, साक्षात्कार और काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इससे छात्र मानसिक, आर्थिक दबाव का सामना करते हैं। एक और गंभीर समस्या सीट आवंटन से जुड़ी हुई है। वर्तमान व्यवस्था में छात्र अनेक संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों को अंतिम समय तक सुरक्षित रखते हैं, ताकि उन्हें अपनी पसंद का सर्वश्रेष्ठ विकल्प मिल सके। इससे कई सीटें लंबे समय तक अवरुद्ध रहती हैं। प्रतीक्षा सूची वाले छात्रों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है और संस्थानों को अंतिम समय तक प्रवेश प्रक्रिया को स्थिर करने में कठिनाई होती है।

यही कारण है कि अब एक समन्वित और केंद्रीकृत प्रवेश प्रणाली की आवश्यकता महसूस की जा रही है। भारत के पास इसका सफल अनुभव पहले से मौजूद है। इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा में केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रणाली ने पारदर्शिता और दक्षता को मजबूत किया है। प्रबंधन शिक्षा में भी ऐसा माडल अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कैट पहले से ही आइआइएम के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए एक साझा राष्ट्रीय परीक्षा के रूप में कार्य कर रहा है। इसी प्रकार आइपीएमएटी और जेआइपीएमएटी जैसी परीक्षाएं स्नातक प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा पहचानने का माध्यम बन सकती हैं। यदि इन परीक्षाओं के आधार पर एक साझा आवेदन और केंद्रीकृत काउंसलिंग प्रणाली विकसित की जाए, तो छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया अत्यंत सरल हो सकती है।

खरी-खरी

फूफा का रायता

मनीष कुमार चौधरी

वैसे तो रायता विभिन्न अवसर और क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न तरीके से फैलाया जाता है, पर शादी-ब्याह में रायता फैलाने का आनंद ही कुछ और होता है। अधिकतर मौकों पर यह प्रतिभा प्रदर्शन रूठे फूफा के जिम्मे रहता है। अपनी पत्नी के रिलेशन में कोई विवाह आयोजन हो तो मुंह फुलाने में फूफा को विशेष महारत हासिल है। वह इस बात पर भी रूठ सकता है कि शादी में बुलाने की मनुहार उससे आधी-अधूरी ही की गई है। वह अपनी पत्नी के सामने इसका पुरजोर विरोध भी दर्ज करा देता है।

लेकिन वह फूफा है तो क्या, उसकी पत्नी भी कम नहीं होती। अपने रिश्तेदारों के सामने ऐसे शुभ अवसर पर कोई फजीहत न हो, इसके लिए वह पति से साफ-साफ कह देती है, 'देखिए जी, इस तरह की बातें कर शादी में रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बनने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपकी साइड के सारे रिश्तेदारों को जानती हूं कि कौन-कितनी मनुहार करता है! आप तो मेरे परिवार की हर शादी में इस तरह का नाटक करते हो।' यह सुनते ही फूफा रायता फैलाने की सारी प्लानिंग ताक पर रख देता है।

शादी ही वह एकमात्र आयोजन है, जहां फूफा को उसकी औकात पता चलती है। अपने निजी जीवन में फूफा भले ही कितना तोपची क्यों न हो, शादी में उसकी हैसियत परिवार के उस वयोवृद्ध के समान हो जाती है, जहां उसकी खैर-खबर लेने वाला कोई नहीं होता। यहां तक कि उसकी पत्नी भी उसे नहीं गांठती और सार्वजनिक रूप से कई महिला रिश्तेदारों के सामने उस पर रौब झाड़ते हुए कहती है कि हमारे ये तो बड़े सीधे-सादे, सरल मन के हैं।

आहत फूफा रायता फैलाने के कुत्सित इरादों की मन ही मन प्लानिंग करता रहता है। लेकिन अधिकांश अवसरों पर प्रैक्टिकली वह ऐसा नहीं कर पाता। फैलाने की बात तो दूर, वह रायता खाने से आगे नहीं बढ़ पाता। पर फूफा तो फूफा ठहरा। यह पदनाम रायता फैलाने वालों की लिस्ट में चूंकि पहले नंबर पर रहता है, तो उसे यह परंपरा बनाए रखने में भरपूर सहयोग करना पड़ता है। इसके लिए वह भांति-भांति के प्रपंच करता रहता है। कुछ अपवादों को छोड़कर फूफा के हाथ निल बटे सन्नाटा आता है।

पोस्ट

दिल्ली की मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को मेट्रो से यात्रा करते देखना सुखद है। उम्मीद है कि वे ये सिर्फ कैमरे के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आगे भी संकट निपट जाने के बाद मेट्रो से चलते रहेंगे ताकि नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन से जाने की प्रेरणा मिलती रहे और डीजल-पेट्रोल की बचत हो।
आशुतोष@ashutosh83B

बंगाल में इमामों और पुजारियों को मिलने वाला धार्मिक भत्ता समाप्त कर दिया गया है। सरकारी खजाने के इस पैसे का उपयोग अब 'स्वामी विवेकानंद मेरिट स्कालरशिप' के माध्यम से राज्य के मेधावी और जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार का यह निर्णय बहुत स्वागतयोग्य है।
प्रभाकर कुमार मिश्रा@PMishra_Journo

प्रेस फ्रीडम रैंकिंग की विश्वसनीयता और गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों की रैंकिंग भी भारत से बेहतर है। इस तरह की रैंकिंग कूड़ा है, जिसमें न कोई पारदर्शिता है और न ही जवाबदेही।
कुमार श्याम@thekumarshyam

समाज में आई विद्रूपता का नया प्रतीक

धनंजय प्रताप सिंह
डिप्टी पालिटिकल एडिटर (स्टेट), मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

भोपाल में माडल-अभिनेत्री और कारपोरेट प्रोफेशनल रही त्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत आत्महत्या हो या हत्या, लेकिन यह हमारी सामाजिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। त्विशा अब दुनिया में नहीं हैं, इसलिए पूरा सच शायद ही कभी सामने आ पाए। प्रथमदृष्टया यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि त्विशा के साथ हुआ व्यवहार एक संस्कारित परिवार में शायद ही कभी होता। उनकी शादी मात्र छह महीने भी नहीं चल पाई और अब वह इस दुनिया में नहीं हैं। इसके कारणों पर सारे समाज को चिंतन करना चाहिए। दोषी कौन है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह विचार करना कि आधुनिक समाज में कैसे भी शादी बचाने के विचार ने त्विशा की जान ले ली। त्विशा पर शादी टूटने की रूढ़िवादी सोच या कहें कि पारिवारिक-सामाजिक दबाव नहीं होता तो शायद आज वह जीवित होती।

त्विशा की मौत ने उजागर कर दिया कि आधुनिक और आत्मनिर्भर होने के बावजूद भारत जैसे सनातनी देश में आज भी महिलाएं वैवाहिक प्रताड़ना और सामाजिक खोखलेपन का शिकार हो रही हैं। घटना ने परिवार नामक व्यवस्था, समाज और कानून तीनों को कठघरे में खड़ा किया है। यदि त्विशा के पिता का यह कहना सही है कि हनीमून के दौरान ही उसके साथ दुर्व्यवहार होने लगा था, लेकिन वह इसलिए सब सहती रही कि शादी एक झटके में टूट न जाए, तो फिर यह सोच बेटियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। परिवार और समाज, दोनों का यही दबाव रहता है कि सारे रिश्ते निभाने की जिम्मेदारी बेटी की ही है। तमाम तरह की प्रताड़ना झेलकर भी वह उफ न बोले। क्या आज के समय में यह संभव है?

त्विशा शर्मा। फाइल

त्विशा की ही बात की जाए तो वह योग्य और सफल बेटी थी। जो बातें सामने आ रही हैं, वह तो संकेत दे रही हैं कि उसके चरित्र हनन का प्रयास मौत के बाद ही नहीं, पहले से वह इन आरोपों को झेल रही थी। गर्भावस्था, गर्भपात और उस पर भी सवाल... कुछ इस तरह की बातें त्विशा के चैट में भी सामने आई हैं। जब मायके वालों को मालूम था कि त्विशा गर्भपात के बाद टूट गई है तो उसे मां-बाप को सहारा देना चाहिए था। लेकिन परिवार ने भी बेटी के नए घर पर ही सब निर्णय छोड़ दिए।

पुलिस की जांच तो संदिग्ध दिखाई दे ही रही है। वह पहले दिन से ही सास के पूर्व न्यायिक अधिकारी होने के भय से ग्रसित है। उसकी नजर में वही सच है, जो वह बता रही हैं। त्विशा की मौत के बाद उसके पति समर्थ सिंह का फरार होना और सास द्वारा मीडिया के सामने आकर बहू को ड्रग एडिक्ट बताना, चरित्र हनन की कोशिश करना यही बताता ही है कि ससुराल पक्ष दूध का धुला तो नहीं है।

मध्य प्रदेश सरकार को भी यह सोचना चाहिए कि त्विशा की मौत पर उठ रहे सवालों के कारण भोपाल की बदनामी हो रही है। ऐसे में त्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करवाने या बाहरी एजेंसी से जांच करवाने में क्या दिक्कत है। त्विशा के माता-पिता और भाई को इसी बात से संतुष्टि मिलती है तो सरकार को क्या परेशानी है। वे इस भीषण गर्मी में न्याय के लिए लड़ रहे हैं। न्याय जहां से मिल सकता है, उन सभी दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, पर शायद सुनने वाला कोई नहीं है। त्विशा शर्मा किसी की बेटी है, बहन है, वह भोपाल की बहू थी।

ऐसी मृत्यु किसी अन्य बेटी की न हो, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है। जब आरोप ऐसे परिवार पर हैं, जहां न्यायिक सेवा का प्रभुत्व है तो जांच एजेंसी का दबाव में होना स्वाभाविक है। ऐसे हालात में जांच को तुरंत राज्य से बाहर या सीबीआइ की निगरानी में ट्रांसफर करने पर विचार करना चाहिए, ताकि सिस्टम का दुरुपयोग न हो सके। डिजिटल साक्ष्यों को कानूनी मान्यता मिल चुकी है तो पुलिस को भी वाट्सएप या इंस्टाग्राम पर भेजे गए मैसेज को एफआइआर में दर्ज करना चाहिए। इस पूरी कवायद को केवल किसी निर्दोष को फंसाने की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे दोषी की पहचान और सजा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए कानून को बिना किसी पक्षपात के अपना काम करना चाहिए।

समाज को अपनी बेटियों को केवल यह नहीं सिखाना चाहिए कि शादी के बाद ससुराल ही उनका एकमात्र ठिकाना है, बल्कि अपनी बेटियों को सिखाना होगा, आश्वस्त करना होगा कि जिंदगी शादी टूटने से अधिक महत्वपूर्ण है। त्विशा की मौत की लड़ाई केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि देश की हर उस बेटी की है, जो रसूख और रूढ़िवादिता के भंवर में फंसी हुई हैं। यह केवल एक कानूनी मसला नहीं, बल्कि हमारे समाज के चेहरे पर काला धब्बा है। यह घटना कह रही है कि हमारे सामाजिक सोच और परवरिश में सब कुछ सही नहीं है।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या रिषभ पंत को वनडे टीम से बाहर करना और टेस्ट की उपकप्तानी से हटाने का फैसला सही है?

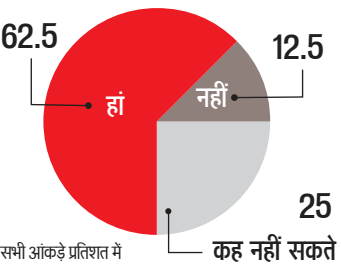

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टी-20 टीम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

डर कर 'पुष्पा' ने दिये अपने घुटने टेक,
किसके दम पर अब भला कूदेंगे अभिषेक।
कूदेंगे अभिषेक बुआ जी भी हैं हारी,
सारे किये कुकर्म पड़ रहे हैं अब भारी!
साफ किया बंगाल आपने जी भर चर कर,
अब शुभेंदु के राज रहोगे तुम डर डर कर!!
-ओम प्रकाश तिवारी

योगी माडल

कानून एवं व्यवस्था की मिसाल

विक्रम सिंह
पूर्व महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं चांसलर नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी

यूपी में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है। योगी सरकार ने 'जीरो टालरेंस' व 'माफिया को मिट्टी में मिला देंगे' जैसी बातों को कार्रवाई के जरिये धरातल पर उतारने का माडल पेश किया है

आज अपराधी और माफिया तत्वों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कठोर रवैये की चर्चा सारे देश में होती है, लेकिन प्रदेश की राजनीति का एक लंबा दौर ऐसा भी रहा है, जब अपराध केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं था, बल्कि सत्ता, जातीय समीकरण और राजनीतिक अस्तित्व का हिस्सा बन चुका था। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर राजनीतिक दलों में तनाव पैदा होता था, अधिकारियों के तबादले होते थे और गठबंधन टूटने की नौबत तक आ जाती थी।

वर्ष 1994 में कुख्यात गैंगस्टर महेंद्र फौजी का एनकाउंटर उस दौर का इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह केवल एक दुर्दांत अपराधी के मारे जाने की घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक विस्फोट था, जिसने तत्कालीन सत्ताधारी गठबंधन (सपा और बसपा) में ऐसी दरार डाल दी, जो आगे चलकर 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड तक पहुंची और फिर वह कभी भर नहीं सकी।

आज के दौर में जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 'जीरो टालरेंस' नीति की चर्चा होती है, तब पिछली सदी के अंतिम दशक का वह दौर और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। यह फर्क केवल सरकारों का नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण का भी है। तब और अब का अंतर समझने के लिए जेन जी को महेंद्र फौजी के बारे में जानना आवश्यक है। पिछली सदी के अंतिम दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र फौजी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक फैले नेटवर्क वाला कुख्यात गैंगस्टर था। अप्रैल, 1994 में बुलंदशहर पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी सफलता थी, लेकिन जल्द ही इस सफलता का स्वाद फीका पड़ गया। पुलिस का मनोबल तोड़ने के लिए सत्ताधारी पार्टियां आपस में भिड़ गईं। एक अपराधी के एनकाउंटर के लिए एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया- वह भी एक बार नहीं दो बार!

बुलंदशहर के तत्कालीन एसएसपी ओपी सिंह (बाद में डीजीपी बने) को हटाकर लखनऊ भेजा गया और फिर कुंभ मेले का एसएसपी बनाया गया। पुलिस पर इतने भारी दबाव के पीछे जातीय समीकरण काम कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों पर तो जातीय समीकरण साधने का दबाव हमेशा होता है। यह राज्य के मुखिया की जिम्मेदारी थी कि एक कुख्यात अपराधी के एनकाउंटर के बाद पुलिस का मनोबल न टूटने दिया जाए। स्वयं ओपी सिंह ने स्वीकार किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने उनसे साफ कहा था कि अगर उन्हें नहीं हटाया गया तो सरकार गिर सकती है। यह बयान उस दौर की राजनीति को समझने के लिए पर्याप्त है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराध और सत्ता के गठजोड़ की चर्चा महेंद्र फौजी तक सीमित नहीं रही। आगे चलकर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कई नाम इस राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक बन गए। सदन से लेकर सड़क तक अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे नाम कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे। इससे यह धारणा मजबूत होती गई कि अपराध और राजनीति के बीच का गठजोड़ अटूट हो गया है।

वर्ष 2017 के बाद जब योगी सरकार ने माफिया पर सीधी कार्रवाई शुरू की, तो उसे केवल प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि दबावों से मुक्त एक नए राजनीतिक बदलाव के रूप में भी देखा गया। माफिया को मिट्टी में मिला देने का योगी माडल प्रदेश भर में अपराध के खिलाफ 'जीरो टालरेंस माडल' के रूप में लागू हुआ। कौन भूल सकता है 2023 में प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल के करीबी उमेश पाल की सरेआम हत्या को, जिसे अतीक अहमद के लड़के समेत कई अपराधियों ने अंजाम दिया था। इस घटना के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ललकारते हुए कहा था, 'माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।' यह बयान आगे चलकर उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में बड़े बदलाव का प्रतीक बना।

आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 के बाद से प्रदेश में 10 हजार से अधिक पुलिस मुठभेड़ें हुईं। इनमें सैकड़ों अपराधी मारे गए, हजारों घायल और गिरफ्तार हुए। 75 से अधिक माफिया की 2500 करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त या ध्वस्त की गई। गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत भी व्यापक कार्रवाई हुई। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और विकास दुबे जैसे अपराधियों पर हुई कार्रवाई ने यह संदेश दिया कि अब कानून का शिकंजा जाति, धर्म या राजनीतिक संरक्षण देखकर नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे उत्तर प्रदेश में 'कानून का राज' स्थापित करने और तुष्टीकरण आधारित कार्रवाई की पुरानी राजनीतिक संस्कृति से अलग एक नए प्रशासनिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया।

सरकार बदलने के साथ धारणा भी बदली। महेंद्र फौजी का मामला उस दौर का प्रतीक था, जब अपराध, जातीय समीकरण और सत्ता की राजनीति एक-दूसरे में उलझी हुई थीं। अपराधियों का मनोबल तोड़ने के बजाय पहले के समय में ये समीकरण पुलिस का मनोबल तोड़ते थे। जबकि इसके विपरीत आज का उत्तर प्रदेश उस दौर से अलग दिखता है, क्योंकि अब राजनीतिक विमर्श 'किस अपराधी की जाति क्या है' से आगे बढ़कर 'कानून का शासन कितना मजबूत है' पर केंद्रित हो चुका है।

विधानसभा में बोलते योगी आदित्यनाथ। फाइल

बिजनेस

संयुक्त राष्ट्र ने भारत का वृद्धि अनुमान घटाया

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक झटकों का हवाला देते हुए 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.6 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (यूएन डीईएसए) द्वारा मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। (प्रेट्र)

मजबूत जनसांख्यिकी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और सरकार के सहायक उपायों के दम पर वैश्विक स्तर पर अस्थिर माहौल के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है।
– एन चंद्रशेखरन, चेयरमैन, टाटा संस

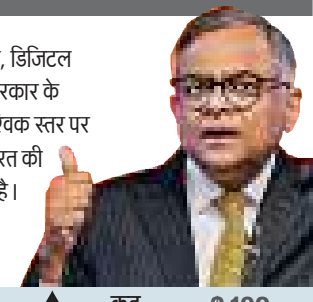

सेंसेक्स	75,318.39 ▲ 117.54	निफ्टी	23,659 ▲ 41	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,64,900 ▲ ₹ 1,300	चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,66,000 ▼ ₹ 5,000	$ डालर	₹ 96.86 ▲ ₹ 0.16	क्रूड प्रति बैरल	$ 109

एक नजर में

बीपीसीएल ने रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई

नई दिल्ली: भारत पेट्रोलियम (बीपीएसील) ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के चलते आपूर्ति में आ रही रुकावटों के बीच रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाकर लगभग 41 प्रतिशत कर दी है। कंपनी के डायरेक्टर (फाइनेंस) वेट्सा रामकृष्ण गुप्ता ने बताया कि रूसी कच्चा तेल अब कुल आयात का 40-41 प्रतिशत है, जो वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में 31 प्रतिशत और तीसरी तिमाही में 25 प्रतिशत था। जुलाई तक तेल की सप्लाई सुनिश्चित हो गई है, जिसका बड़ा हिस्सा रूस से आएगा। (आइएएनएस)

अप्रैल में बुनियादी उद्योग का उत्पादन 1.7% बढ़ा

नई दिल्ली: देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में अप्रैल में 1.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसे इस्पात, सीमेंट और बिजली के उच्च उत्पादन से समर्थन मिला। बुधवार को जारी आंकड़ों से जानकारी मिली। अप्रैल, 2025 में इन आठ उद्योगों का उत्पादन एक प्रतिशत बढ़ा था। मार्च में यह वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत थी। समीक्षाधीन महीने में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। (प्रेट्र)

एमएफ में कर्मियों की ओर से भुगतान कर सकेंगे नियोक्ता

नई दिल्ली: सेबी ने बुधवार को कुछ निश्चित परिस्थितियों में म्यूचुअल फंड (एमएफ) में तीसरे पक्ष से भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा। इनमें पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ नियोक्ता का अपने कर्मचारियों की ओर से निवेश करना और म्यूचुअल फंड यूनिट के रूप में संपत्ति प्रबंधन कंपनियों का कमीशन का भुगतान करना शामिल है। सेबी ने इन प्रस्तावों पर 10 जून तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। अभी एमएफ में निवेश के लिए सभी भुगतान सीधे निवेशक के अपने बैंक खाते से होने चाहिए और केवल आरबीआइ से अधिकृत भुगतान एग्रीगेटर से होने चाहिए। (प्रेट्र)

साबुन, शैंपू से लेकर टूथपेस्ट भी होंगे महंगे

विभिन्न देशों की ओर से पाम-सोयाबीन तेल का इस्तेमाल बायोफ्यूल में करने से बढ़ रहे उत्पादों के दाम

- पाम आयल के बड़े उत्पादक इंडोनेशिया ने बंद किया निर्यात
- सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल भी बायोफ्यूल में हो रहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पश्चिम एशिया संकट के कारण दुनिया के 40 से अधिक देश वाहनों के ईंधन के लिए बायोफ्यूल पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पाम आयल से लेकर सोयाबीन तेल के वैश्विक दाम लगातार मजबूत हो रहे हैं। पाम आयल का इस्तेमाल साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट जैसे आइटम के उत्पादन में किया जाता है। इसके महंगा होने से इनकी कीमत भी कंपनियां बढ़ा चुकी है या बढ़ाने वाली है।

अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, चीन जैसे सभी प्रमुख देश वैकल्पिक ईंधन के रूप में बायोफ्यूल को तेजी से अपना रहे हैं या इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया ने पाम आयल का निर्यात बंद कर दिया है, ताकि वहां पाम आयल का इस्तेमाल बायोफ्यूल के लिए किया जा सके। ब्राजील सोयाबीन से बायोफ्यूल बना रहा है। वैश्विक स्तर पर सोयाबीन के उत्पादन में ब्राजील की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल भी बायोफ्यूल के रूप में किया जा रहा है। यूरोप से मुख्य रूप से सूरजमुखी तेल का आयात भारत करता है। तेल के अलावा दूसरी अन्य चीजों के दाम में वृद्धि होने लगी है।

भारत खाद्य तेल की जरूरत का 60% हिस्सा करता है आयात

भारत अपनी खाद्य तेल की जरूरत का 60 प्रतिशत से अधिक आयात करता है। मुख्य रूप से पाम आयल विदेश से मंगाया जाता है। पाम और सोयाबीन की कमी होने से इन दोनों खाद्य तेल की कीमत घरेलू स्तर पर पिछले ढाई महीनों में 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुकी है। इसका असर सरसों तेल पर भी देखा जा रहा है। बाजार में सरसों तेल की कीमत 170-200 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। सूरजमुखी तेल की कीमत 160-190 रुपये प्रति लीटर, सोयाबीन तेल की कीमत 130-150 रुपये प्रति लीटर, मूंगफली तेल की कीमत 180-200 रुपये लीटर तो पाम तेल की कीमत 145-165 रुपये लीटर की वृद्धि हुई है।

वैश्विक स्तर पर काटन की कमी का भी संकट

अमेरिका में काटन का उत्पादन कम होने से वैश्विक स्तर पर काटन की कमी बताई जा रही है, जिससे काटन के दाम में भी तेजी दिख रही है। पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक स्तर पर गेहूं की किल्लत भी बताई जा रही है। हालांकि, घरेलू स्तर पर गेहूं की कोई कमी नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि अल नीनो से भी विभिन्न जिन्सों के उत्पादन पर असर दिख सकता है। यही वजह है कि भारत ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

मेलोडी के चक्कर में धोखे से बढ़ गए पारले इंडस्ट्रीज के शेयर

नई दिल्ली, जेएनएन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा के दौरान एक छोटा सा वीडियो भारतीय शेयर बाजार में बड़ी हलचल का कारण बन गया। इटली की प्रधानमंत्री जार्जिया मेलोनी ने इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मोदी उन्हें भारत की मशहूर मेलोडी टाफी गिफ्ट करते नजर आए। वीडियो वायरल होते ही कई निवेशकों ने जल्दबाजी में पारले नाम देखकर शेयर खरीदना शुरू कर दिया। इसका फायदा पारले इंडस्ट्रीज को मिला, जिसके शेयरों में जबरदस्त खरीदारी शुरू हो गई। बुधवार के कारोबार में कंपनी का शेयर पांच प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 5.25 रुपये पर पहुंच गया।

असल में मेलोडी टाफी बनाने वाली कंपनी पारले प्रोडक्ट्स है, जो पार्ले-जी, मोनाको, हाइड एंड सीक और मैंगो बाइट जैसे लोकप्रिय ब्रांड बनाती है, लेकिन पारले प्रोडक्ट्स शेयर बाजार में सूचीबद्ध ही नहीं है। दूसरी तरफ, जिस पारले इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी आई, उसका टाफी या बिस्कुट कारोबार से कोई लेना-देना नहीं है। पारले इंडस्ट्रीज इन्फ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और पेपर वेस्ट रीसाइक्लिंग जैसे बिजनेस में लगी हुई है। उधर, पारले प्रोडक्ट्स के वाइस प्रेसिडेंट मयंक शाह ने कहा कि यह कदम भारतीय प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने और उन्हें एक ग्लोबल प्लेटफार्म देने का एक अच्छा तरीका था। यह वीडियो वायरल होने के बाद बिक्री में उछाल आएगा।

12 सालों में 166 प्रतिशत बढ़ा टाफी का निर्यात

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि पिछले 12 सालों के दौरान देश का टाफी निर्यात 166 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में 132 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 2013-14 में टाफी निर्यात 49.68 करोड़ रुपये था।

प्रतिभूति बाजार से होने वाली घरेलू बचत बढ़कर 6.91 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय परिवारों के बीच वित्तीय संपत्तियों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सेबी अधिकारियों द्वारा लिखे गए एक पेपर के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के 3.58 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 2024-25 में प्रतिभूति बाजार के जरिये की गई बचत बढ़कर 6.91 लाख करोड़ रुपये हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, 2024-25 के लिए भारत का सकल बचत-जीडीपी 47 आधार अंकों की वृद्धि के साथ 34.47 प्रतिशत से बढ़कर 34.94 प्रतिशत हो गया है।

प्रभात कुमार रथ, शाइनी सुनील और कल्याणी एच द्वारा लिखे गए पेपर में कहा गया है कि प्रतिभूति बाजार से की गई घरेलू बचत, वित्तीय बचत का एक अहम हिस्सा है और यह सोना और रियल एस्टेट जैसी संपत्तियों के एक आकर्षक विकल्प के रूप में उभर रही है।

- सेबी के मुताबिक भारतीय परिवारों के बीच वित्तीय संपत्तियों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही
- वित्तीय संपत्तियां ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता और तरलता के चलते लोगों के बीच हो रही हैं लोकप्रिय

निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड्स का रहा

2024-25 में प्राथमिक बाजार में किए गए निवेश की कुल रकम 6.32 लाख करोड़ रुपये थी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा 5.13 लाख करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड्स का था। 95,139 करोड़ रुपये के साथ इक्विटी दूसरे नंबर पर रही। इस साल सेकेंडरी मार्केट में किए गए निवेश का कुल योगदान 59,452 करोड़ रुपये रहा। 2024-25 में प्रतिभूति बाजार के जरिये परिवारों की बचत जीडीपी का 2.17 प्रतिशत रही। इसी तरह, परिवारों की बचत और जीडीपी का अनुपात 21.23 प्रतिशत से बढ़कर 21.7 प्रतिशत हो गया, जबकि परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत जीडीपी के 6.63 प्रतिशत से बढ़कर 7.10 प्रतिशत तक पहुंच गई।

बैंकिंग सिस्टम में पांच अरब डालर की नकदी डालेगा आरबीआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र: आरबीआइ बैंकिंग सिस्टम में पांच अरब डालर की नकदी डालेगा। इसके लिए 26 मई को डालर-रुपये की खरीद-बिक्री स्वैप नीलामी आयोजित की जाएगी। आरबीआइ द्वारा यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है, जब वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच डालर के मुकाबले रुपया काफी कमजोर हुआ है।

इस व्यवस्था के तहत बैंक आरबीआइ को डालर बेचेंगे और बदले में उन्हें रुपये मिलेंगे। स्वैप की अवधि यानी तीन साल खत्म होने के बाद बैंक केंद्रीय बैंक को समान राशि के रुपये वापस देकर अपने डालर दोबारा खरीद लेंगे।

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, इस स्वैप आक्शन में न्यूनतम बोली एक करोड़ डालर की होगी और इसके बाद एक करोड़ डालर के गुणांक में ही अगली बोली लगाई जा सकेगी।

96.86 के नए निचले स्तर पर रुपया

मुंबई, प्रेट्र: लगातार नौवें सत्र में गिरावट दर्ज करते हुए डालर के मुकाबले रुपया बुधवार को 16 पैसे टूटकर 96.86 के नए निचले स्तर पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी ने महंगाई की चिंताओं को और बढ़ा दिया। विदेशी मुद्रा बाजार में, डालर के मुकाबले रुपया 96.89 पर खुला, फिर और कमजोर होकर 96.95 के रिकार्ड निचले स्तर और 96.65 के उच्चतम स्तर को छुआ, और अंत में 96.86 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 16 पैसे की गिरावट है।

मिराए एसेट शेयरखान में शोध विश्लेषक (कमोडिटीज) अनुज चौधरी ने कहा, मजबूत डालर और अमेरिकी बांड रिटर्न में उछाल के कारण भारतीय रुपया नए निचले स्तर पर पहुंच गया। 30-वर्षीय बांड रिटर्न दो दशक के उच्चतम स्तर पर पहुच गया, जबकि 10-वर्षीय बांड रिटर्न 16 माह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इससे महंगाई की चिंताएं बढ़ीं और वैश्विक बाजारों में बिकवाली हुई।' उम्मीद है कि महंगाई की चिंताओं के बीच रुपया नकारात्मक रुख के साथ कारोबार करेगा।

- डालर के मुकाबले भारतीय मुद्रा बुधवार को 16 पैसे टूटी
- मजबूत डालर और बांड रिटर्न में उछाल से भारतीय मुद्रा दबाव में

अंतिम घंटे में खरीदारी से सेंसेक्स 117 अंक चढ़ा

कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच अंतिम घंटे की खरीदारी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में उछाल से बुधवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट से उबरकर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक उतार-चढ़ाव भरे 117.54 अंक यानी 0.16 प्रतिशत चढ़कर 75,318.39 अंक पर बंद हुआ। एक समय यह 671.44 अंक टूटकर 74,529.41 अंक तक आ गया था। एनएसई निफ्टी 41 बढ़कर 23,659 अंक पर बंद हुआ।

सोना 1,300 रुपये बढ़ा, चांदी 5,000 रुपये सस्ती हुई

नई दिल्ली, प्रेट्र: बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 1,300 रुपये बढ़कर 1,64,900 रुपये प्रति 10 ग्राम गई। व्यापारियों ने बताया कि कीमती धातुओं में नई खरीदारी से घरेलू सोने की कीमतों को सहारा मिला। हालांकि, चांदी 5,000 रुपये गिरकर 2,66,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। विश्लेषकों ने कहा कि कम औद्योगिक मांग और मुनाफा-वसूली से चांदी अस्थिर बनी रहीं।

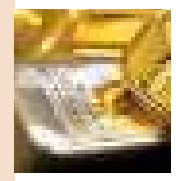

राष्ट्रीय फलक

पीएसपीसीएल के पूर्व सीएमडी समेत तीन भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लुधियाना

- विजिलेंस की कार्रवाई में पूर्व सीनियर एक्सईएन व कालोनाइजर भी शामिल
- कालोनाइजर ने कालोनी में स्थापित करवाया 66 केवी सब-स्टेशन

पीएसपीसीएल के पूर्व सीएमडी केडी चौधरी कोर्ट परिसर बाहर आते हुए। फोटो अजय शर्मा

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के आर्थिक अपराध शाखा लुधियाना ने 12 साल पुराने भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के पूर्व चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) 75 वर्षीय केडी चौधरी, पूर्व सीनियर एक्सईएन संजीव प्रभाकर और कालोनाइजर अमित गर्ग को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने यह कार्रवाई 10 मई 2021 को दर्ज केस की जांच पूरी होने के बाद की है। विजिलेंस ने बुधवार को आरोपितों को अदालत में पेश कर एक दिन का रिमांड हासिल किया है। हालांकि, पेशी के बाद बाहर लाए जाने पर केडी चौधरी ने खुद पर लगाए आरोपों को बेबुनियाद बताया।

विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि 66 केवी बसंत एवेन्यू सब-स्टेशन की स्थापना (2014-15) के मामले में कालोनाइजर ने पीएसपीसीएल के संबंधित अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर कालोनी में 1015 वर्ग गज क्षेत्र में सब-स्टेशन स्थापित करवाया। आरोप है कि अगर उच्च अधिकारियों द्वारा कालोनाइजर की सभी कालोनियों के एनओसी की जांच करवाई जाती और कालोनियों का बिजली लोड एक साथ जोड़ा जाता तो पूरे 66 केवी सब-स्टेशन का खर्च कालोनाइजर को उठाना पड़ता।

'भारत को वैश्विक ताकत के तौर पर देख रहे युवा'

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- ओआरएफ सर्वेक्षण में सामने आई नई पीढ़ी की विदेश नीति पर सोच
- पाकिस्तान पर सख्त रुख और यूएई पर सबसे ज्यादा भरोसा

भारत के पास है खेल बदलने वाली ताकत

वहीं, पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर युवाओं का रुख बेहद सख्त दिखाई दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चलाए गए आपरेशन सिंदूर का युवाओं ने खुलकर समर्थन किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई और सिंधु जल संधि को रोकने के फैसले को भी सही बताया गया। रिपोर्ट में चीन के साथ सीमा तनाव और पाक से होने वाले आतंकवाद को देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में गिना गया। इस सर्वेक्षण ने साफ कर दिया कि भारत का युवा अब दुनिया को नए नजरिये से देख रहा है। उसे लगता है कि बदलती वैश्विक राजनीति में भारत किनारे खड़ा देश नहीं, बल्कि खेल बदलने वाली ताकत बन चुका है।

भारत के ज्यादातर युवा देश को दुनिया की एक बड़ी ताकत के तौर पर देख रहे हैं और उनका मानना है कि मौजूदा विदेश नीति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। हाल ही में विदेश नीति पर किए गए एक सर्वेक्षण में युवाओं ने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं पर भरोसा जताया है और भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया।

युवा ब्रिक्स को भी पश्चिमी देशों के प्रभाव वाले वैश्विक ढांचे के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। यानी अब देश के युवा सिर्फ नौकरी, पढ़ाई और इंटरनेट मीडिया तक सीमित नहीं है। वह दुनिया की राजनीति, देशों के रिश्तों और भारत की बढ़ती ताकत को भी बारीकी से समझ रहे हैं। यही तस्वीर सामने आई है द आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की नई रिपोर्ट 'फारेन पालिसी सर्वे : यंग इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट' में। सर्वेक्षण में देश के 19 शहरों के 18 से 35 वर्ष के पांच हजार से ज्यादा युवाओं से हुई बातचीत को शामिल किया गया है।

पश्चिम एशिया बनेगा तरक्की का आधार : सर्वेक्षण में सबसे दिलचस्प बात यह सामने आई है कि भारत के युवा पश्चिम एशिया को अब सिर्फ तेल और व्यापार का इलाका नहीं मानते। उनके लिए यह क्षेत्र भारत की तरक्की, तकनीक और वैश्विक साझेदारी का नया दरवाजा बन चुका है। युवाओं का मानना है कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा और चार देशों के रणनीतिक गठबंधन आइ2यू2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट आने वाले समय में भारत को पश्चिम एशिया से और मजबूती से जोड़ेंगे। रिपोर्ट में यूएई ज्यादा चर्चा में रहा। युवाओं ने माना कि यूएई के साथ भारत की दोस्ती अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे सकती है। भारत-यूएई आर्थिक समझौते को युवाओं ने फायदे का सौदा बताया।

डिफाल्टर के मोबाइल फोन को डिसेबल नहीं कर सकेंगे बैंक

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ ने बुधवार को कहा कि बैंक पर्सनल, कार या होम लोन की रिकवरी के लिए डिफाल्टर के मोबाइल फोन को डिसेबल या प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। हालांकि, बैंकों को उस मोबाइल डिवाइस को प्रतिबंधित या डिसेबल करने की अनुमति होगी, जिसे बैंक ने स्वयं फाइनेंस किया है। केंद्रीय बैंक इन नियमों को 1 अक्टूबर, 2026 से लागू करने का प्रस्ताव कर रहा है।

केंद्रीय बैंक ने लोन की बकाया राशि की रिकवरी और रिकवरी एजेंसियों को काम पर रखने के मामलों से जुड़े सख्त नियम प्रस्तावित किए है। ये नियम उधारकर्ताओं के उत्पीड़न की शिकायतों के बीच लाए गए हैं, जिसमें इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के जरिये उत्पीड़ने और गाली-गलौज का इस्तेमाल शामिल है। आरबीआइ ने प्रस्ताव दिया है, "कोई भी बैंक ऐसा कोई तकनीक आधारित तरीका नहीं अपनाएगा, जो किसी उधारकर्ता के मोबाइल डिवाइस की कार्यक्षमता को प्रभावित करे। बैंक ऐसा तभी कर सकेंगे जब उसे डिवाइस के फाइनेंस से जुड़े लोन की बकाया राशि की रिकवरी करनी हो।' बैंक तब तक डिवाइस को ब्लाक नहीं कर सकेंगे जब तक कि संबंधित लोन 90 दिनों से ज्यादा समय से बकाया नहीं हो गया हो। आरबीआइ ने कहा कि गलत तरीके से प्रतिबंध लगाने या हटाने में देरी होने पर बैंक को उधारकर्ता को उस समय तक 250 रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजा देना होगा, जब तक कि उस गलत कार्रवाई को ठीक नहीं कर दिया जाता है। बैंक ने लोन की रिकवरी व रिकवरी एजेंटों को काम पर रखने मामलों में भी संशोधित मसौदा निर्देश जारी किए हैं।

- आरबीआइ ने लोन की रिकवरी से जुड़े सख्त नियम प्रस्तावित किए
- केंद्रीय बैंक का इन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू करने का प्रस्ताव

बिजली की अधिकतम मांग 265.44 गीगावाट के रिकार्ड स्तर पर रही

नई दिल्ली, प्रेट्र: बढ़ती गर्मी के चलते देश में बिजली की अधिकतम मांग बुधवार को 265.44 गीगावाट के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई। इसने मंगलवार को बने पिछले रिकार्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को बिजली की अधिकतम मांग 257.37 गीगावाट तक पहुंच थी और मंगलवार को बिजली की मांग बढ़कर 260.45 गीगावाट हो गई थी।

बुधवार को 15:45 बजे, बिजली की अधिकतम मांग 265.44 गीगावाट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर बताया कि यह लगातार तीसरा दिन है जब बिजली की अधिकतम मांग एक नए उच्चस्तर पर पहुंच गई है। बिजली मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि इस गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग 270 गीगावाट तक पहुंच जाएगी।

केजी बेसिन मामले को लेकर सुनवाई रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल) और दो विदेशी कंपनियों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि वे कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन गैस स्थानांतरण विवाद में मध्यस्थता के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगी, तब तक सुनवाई रोक दें। इस पर कोर्ट ने सुनवाई रोकने से इन्कार कर दिया।

यह मामला प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची तथा जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष रखा गया। कंपनियों की ओर से पेश वकील ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि सभी याचिकाकर्ता आज केंद्र सरकार को मध्यस्थता के लिए पत्र लिखेंगे। हम निवेदन कर रहे हैं कि पहले मध्यस्थता का प्रयास किया जाए। वकील ने पीठ से अनुरोध किया कि मध्यस्थता का परिणाम आने तक मामले की सुनवाई रोक दी जाए। हालांकि, केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने मामले में सुनवाई जारी रखने का अनुरोध किया। अटार्नी जनरल ने कहा कि यदि इस बीच कुछ होता है, तो हम अदालत को सूचित करेंगे। पीठ ने सुनवाई रोकने से इन्कार करते हुए कहा कि पक्षकार मध्यस्थता के परिणाम से उसे अवगत करा सकते हैं। पीठ ने कहा कि अगर आप मध्यस्थता में सफल होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तब हम मामले का निपटारा कर देंगे।

- आरआइएल व दो अन्य कंपनियों ने कहा मध्यस्थता के लिए केंद्र को पत्र लिखेंगे

प्रतीकात्मक

निर्मला ने अमेरिकी राजदूत से की मुलाकात, आर्थिक संबंधों की मजबूती पर चर्चा

नई दिल्ली, प्रेट्र: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। दोनों ने भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की।

वित्त मंत्रालय ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर लिखा, 'दोनों ने भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी को मजबूत करने, भारत-अमेरिका वित्तीय प्रौद्योगिकी सहयोग, निवेश के अवसरों और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।' इसमें यह भी कहा गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने गोर को आगामी 250वें अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।

अमेरिकी प्रशासन भारतीय कंपनियों को अमेरिका में निवेश करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि दोनों देशों को इसका लाभ मिल सके। इससे दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम मिलेगा।

'वर्क फ्राम होम' पर भेज दिग्गज कंपनी मेटा ने की आठ हजार कर्मचारियों की छुट्टी

नई दिल्ली, आइएएनएस : तकनीकी दुनिया की दिग्गज कंपनी 'मेटा प्लेटफार्म्स' से एक बेहद भावुक और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा ने बुधवार से अपने वैश्विक कार्यबल के लगभग 10 प्रतिशत यानी लगभग आठ हजार कर्मचारियों की छंटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह फैसला कंपनी के उस व्यापक पुनर्गठन का हिस्सा है, जिसके तहत मेटा अब खुद को पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के सांचे में ढालने जा रही है। अचानक आए इस फैसले से हजारों घरों के चूल्हे प्रभावित हुए हैं। छंटनी के दिन उत्तर अमेरिकी कर्मचारियों को घर से काम करने (वर्क फ्राम होम) के लिए कहा गया था, ताकि दफ्तरों में असहज स्थितियों से बचा जा सके।

एआइ-आधारित बदलाव और कर्मचारियों का भविष्य : मेटा की एचआर प्रमुख जेनेल गेल ने कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक ई-मेल में इस दर्दनाक फैसले के पीछे की वजह स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि कई टीमों को 'एआइ-नेगेटिव सिद्धांतों' के आधार पर फिर से तैयार किया जा रहा है, ताकि कंपनी की संरचना को छोटा, तेज और अधिक जवाबदेह बनाया जा सके। इस छंटनी के बीच एक राहत भरी खबर यह भी है कि मेटा के आंतरिक दस्तावेजों के अनुसार, लगभग सात हजार कर्मचारियों की नौकरी पूरी तरह खत्म नहीं की जा रही है, बल्कि उन्हें कंपनी के भीतर ही नए एआइ-केंद्रित भूमिकाओं में स्थानांतरित किया जा रहा है।

भविष्य की तैयारी: एआइ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश : मेटा का यह कदम उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह एआइ के क्षेत्र में अपनी बादशाहत कायम करना चाहती है। कंपनी ने साल 2026 के लिए अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 125 अरब डालर से 145 अरब डालर के बीच रहने का अनुमान लगाया है। यह भारी-भरकम बजट मुख्य रूप से एआइ डाटा केंद्रों, कस्टम चिप्स और माडल ट्रेनिंग पर खर्च किया जाएगा। इस बीच, सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कर्मचारियों को आश्वस्त करते हुए कहाकि इस प्रक्रिया में एकत्र किया गया डाटा केवल एआइ प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए है, न कि किसी की निगरानी के लिए।

- फैसला कंपनी के व्यापक पुनर्गठन का हिस्सा, अब खुद को पूरी तरह एआइ के सांचे में ढालने जा रही है मेटा

प्रतीकात्मक

उस सुख का क्या महत्त्व, जो थोड़ी या बहुत
वेदना के मूल्य पर नहीं खरीदा गया।

– मार्गरेट ओलीफे

परेशानी का पारा

उत्तर और पश्चिमी भारत में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। हाल में कुछ राज्यों में आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन अब आसमान से फिर आग बरसने लगी है। दिन में लू चल रही है और रात में भी लोग गर्मी से बेहाल हैं। कृत्रिम उपकरणों के जरिए राहत पाने के लिए बिजली की मांग में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने जून तक के मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसके अनुसार पूर्वी मध्य, उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीप में इस बार अधिक गर्मी पड़ेगी। जाहिर है कि आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा बढ़ने से आम लोगों की परेशानी भी बढ़गी। मगर सवाल है कि हर साल गर्मी, सर्दी और आंधी-बारिश के क्रम में इतना ज्यादा उतार-चढ़ाव क्यों आ रहा है? मौसम चक्र में इस बदलाव की वजह क्या है? क्या इसके पीछे प्राकृतिक कारण हैं या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली मानव गतिविधियां इसके लिए जिम्मेदार हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते मंगलवार को पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक था। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर-पश्चिमी हवाएं राजस्थान के थार रेगिस्तान और मध्य पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से दिल्ली की ओर बह रही हैं। विशाल शुष्क क्षेत्रों से गुजरते हुए ये हवाएं दिल्ली पहुंचते-पहुंचते बेहद शुष्क हो जाती हैं, जिससे गर्मी सतह के करीब बनी रहती है। इस बीच दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 7,776 मेगावाट से ज्यादा हो गई है, जो हाल के वर्षों की तुलना में मई में तेज वृद्धि को दर्शाती है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पंखे, कूलर और एसी यानी एअर कंडीनशर का इस्तेमाल करते हैं। मगर इस बात पर गौर नहीं किया जाता कि एसी से निकलने वाली हानिकारक गैसों से जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, वहीं इनकी वजह से स्थानीय तापमान में भी बढ़ोतरी होती है। यानी जिन उपकरणों से घर को ठंडा रखने की कोशिश की जाती है, वही तापमान बढ़ने का कारण भी बनते हैं।

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, गर्मी, सर्दी, बारिश और बाढ़ की चरम स्थितियां जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ताप की वजह से पैदा हो रही हैं। इससे मौसम का प्राकृतिक चक्र प्रभावित हो रहा है। वनों की कटाई, शहरों में कंक्रीट के जंगलों का बढ़ता दायरा, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से पर्यावरण में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप तापमान सामान्य से अधिक हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली मानव गतिविधियों को सीमित करने और चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए ठोस उपाय किए जाएं। हाल में उत्तर प्रदेश में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जैसे हालात पैदा हुए, उसने एक बार फिर यही दर्शाया कि मौसम की मार से बचाव के लिए एहतियात बरतने और सटीक पूर्वानुमान को लेकर अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। राज्य में इस दौरान चौबीस घंटों के भीतर सौ से अधिक लोगों की जान चली गई। बहरहाल, अभी गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में 24 मई तक लू की स्थिति बनी रहेगी।

सुरक्षा की फिक्र

उत्तराखंड अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऊंची-ऊंची चोटियों और धार्मिक स्थलों की वजह से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पर्यटन का कारोबार राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। खासकर चार धाम यात्रा के लिए यहां साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उस लिहाज से व्यवस्थागत ढांचे का विस्तार नहीं हो पाया है। पहाड़ी प्रदेश होने की वजह से यहां के मौसम में अचानक बदलाव आने से भारी बारिश और भूस्खलन की घटनाएं आम बात है। ऐसे में पर्यटकों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, पर्यटकों को ले जाने और वापस लाने वाले हेलिकाप्टर के हादसाग्रस्त हो जाने की घटनाएं भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही हैं। ऐसी ही एक घटना बुधवार सुबह हुई, जब बदरीनाथ से तीर्थ यात्रियों को लेकर लौट रहे एक हेलिकाप्टर को तकनीकी कारणों से टिहरी के चंबा-आराकोट क्षेत्र में आपात स्थिति में उतरना पड़ा। इस दौरान बिजली की तारों के संपर्क में आने से हेलिकाप्टर के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा, हालांकि उसमें सवार यात्री सुरक्षित हैं।

उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। मगर सवाल है कि सरकार की ये कदम क्या सिर्फ राजस्व अर्जित करने तक सीमित हैं, या पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था को भी केंद्र में रखा जाता है? यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि पहाड़ी प्रदेश होने के नाते क्षेत्रीय मौसम में बदलाव का स्टीक पूर्वानुमान लगाने की व्यवस्था हो, ताकि पर्यटकों और परिवहन एजंसियों को पहले ही संभावित खतरे से सतर्क किया जा सके। इससे पहले भी चार धाम यात्रा मार्ग पर हेलिकाप्टरों के हादसे का शिकार होने की घटनाएं हो चुकी हैं। मगर ऐसा लगता है कि इन हादसों से शासन-प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। हालांकि, सरकार की ओर से धार्मिक यात्रा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू की गई है, लेकिन जब तक इसे कड़ाई से लागू नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक व्यवस्था में आमूल-चूल सुधार नहीं हो पाएगा।

रणनीतिक साझेदारी का संकल्प

ऐसे समय में जब पूरी दुनिया की व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, इटली और भारत की साझेदारी उच्च राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर लगातार संवाद से आगे बढ़ रही है। द्विपक्षीय संबंध अब एक नए और अधिक व्यापक स्तर पर पहुंच रहे हैं।

नरेंद्र मोदी

जार्जिया मेलोनी

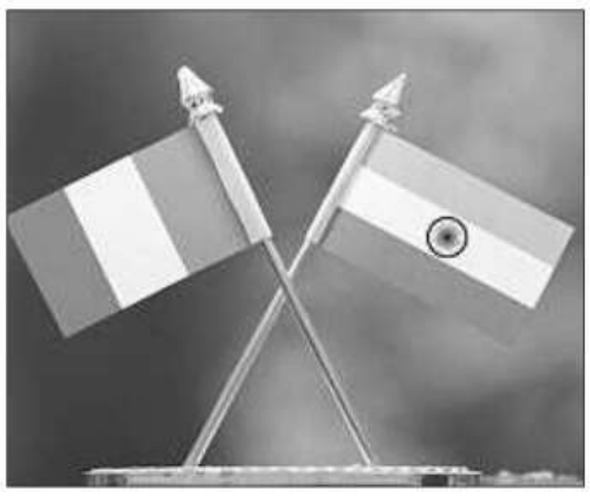

भारत और इटली के संबंध अब एक निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में अभूतपूर्व तेजी से विस्तार हुआ है। ये संबंध अब केवल सौहार्दपूर्ण मित्रता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों तथा भविष्य के साझा दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। ऐसे समय में, जब पूरी दुनिया की व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, इटली और भारत की साझेदारी उच्च राजनीतिक एवं संस्थागत स्तर पर लगातार संवाद से आगे बढ़ रही है। ये संबंध अब एक नए और अधिक व्यापक स्तर पर पहुंच रहे हैं, जिसमें दोनों देशों की आर्थिक ताकत, सामाजिक रचनात्मकता और हजारों वर्षों पुरानी सभ्यतागत विरासत शामिल है।

हमारा सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि इक्कीसवीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि देश कितनी क्षमता से नवाचार करें, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करें और अपनी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करें। इसी उद्देश्य से हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा तथा विविध बनाने का संकल्प लिया है, ताकि नए लक्ष्यों को हासिल किया जा सके और दोनों देशों की पूरक शक्तियों का बेहतर उपयोग हो सके। हम इटली की डिजाइन क्षमता, बेहतरीन विनिर्माण कौशल और विश्वस्तरीय सुपर कंप्यूटर तकनीक को भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, इंजीनियरिंग प्रतिभा, नवाचार, एक सौ से अधिक 'यूनिकार्न' तथा दो लाख नवउद्यम वाली प्रणाली के साथ जोड़ कर एक शक्तिशाली तालमेल बनाना चाहते हैं। यह केवल दो व्यवस्थाओं का साधारण मेल नहीं है, बल्कि ऐसा साझा मूल्य निर्माण है, जिसमें दोनों देशों की औद्योगिक ताकतें एक-दूसरे को और अधिक मजबूत बनाती हैं।

यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश बढ़ाने का रास्ता खोलता है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2029 तक भारत और इटली के बीच व्यापार को 20 अरब यूरो से आगे ले जाना है। इसमें रक्षा एवं एअरोस्पेस, मशीनरी, आटोमोबाइल पुर्जे, रसायन, दवाइयां, वस्त्र, कृषि एवं खाद्य और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा। 'मेड इन इटली' हमेशा से दुनिया भर में उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है और आज इसका स्वाभाविक तालमेल 'मेक इन इंडिया' पहल के उच्च गुणवत्ता वाले लक्ष्यों के साथ दिखाई देता है। इसी संदर्भ में भारत के लिए उत्पादन में इतालवी कंपनियों की बढ़ती रुचि और इटली में भारतीय उद्योगों की बढ़ती मौजूदगी जो अब दोनों पक्षों से मिला कर एक हजार से अधिक हो चुकी है, एक सकारात्मक संकेत है। तकनीकी नवाचार हमारी साझेदारी का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार है। आने वाले दशकों में दुनिया एक बड़े तकनीकी बदलाव के दौर से गुजरेगी, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), क्वांटम कंप्यूटिंग, उन्नत विनिर्माण, महत्त्वपूर्ण खनिज और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में तेजी से प्रगति होगी। भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता, इन क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक बनाती है। दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के बीच बढ़ती साझेदारी भी इसे मजबूती देगी। भारत का डिजिटल सार्वजनिक ढांचा पहले से ही दुनिया के कई देशों, खासकर वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज हमारे समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रही है।

> **इटली और भारत का सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि इक्कीसवीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि देश कितनी क्षमता से नवाचार करें, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करें और अपनी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करें। इसी उद्देश्य से हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा बनाने का संकल्प लिया है। हम इटली की डिजाइन क्षमता, बेहतरीन विनिर्माण कौशल और सुपर कंप्यूटर तकनीक को भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, इंजीनियरिंग, नवाचार और नव उद्यम प्रणाली के साथ जोड़ कर एक शक्तिशाली तालमेल बनाना चाहते हैं।**

भारत और इटली कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समावेशी विकास का एक शक्तिशाली माध्यम मानते हैं, खासकर वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए। डिजिटल सार्वजनिक ढांचा और आसान एवं बहुभाषी तकनीकों के जरिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामाजिक और डिजिटल खाइयों को कम कर सकती है। तकनीक के केंद्र में मानव को रखने की भारत की सोच और इटली की मानव-केंद्रित 'एल्गोर-एथिक्स' की अवधारणा, जो उसकी मानवतावादी परंपरा पर आधारित है, उस पर आगे बढ़ते हुए हमारी साझेदारी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामाजिक सशक्तीकरण का माध्यम बने। सुरक्षित डिजिटल सहयोग, क्षमता निर्माण और मजबूत साइबर ढांचे से जुड़ी श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को साझा करके हम एक ऐसा खुला, भरोसेमंद और समान डिजिटल वातावरण बनाना चाहते हैं, जिसमें हर देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सके और उससे लाभ उठा सके। यही सोच इटली की जी-7 अध्यक्षता और वर्ष 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 'एआइ इम्पेक्ट समिट' के निष्कर्षों का मुख्य आधार है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता को इंसानों की ओर से इंसानों के लिए बनाई गई तकनीक मानने का अर्थ है- यह स्पष्ट करना कि तकनीक न तो मनुष्य की जगह ले सकती है और न ही उसके मूल अधिकारों को कमजोर कर सकती है। इसका उपयोग जनमत को प्रभावित करने या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए भी नहीं होना चाहिए। इटली और भारत रक्षा, सुरक्षा एवं रणनीतिक तकनीकों जैसे क्षेत्रों में अपने सहयोग को और मजबूत करना चाहते हैं। हमारा सहयोग महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आतंकवाद, अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी चुनौतियों के खिलाफ मजबूती बढ़ाने में मदद करेगा।

ऊर्जा हमारी साझेदारी का एक और महत्त्वपूर्ण आधार है। भारत और इटली नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर हाइड्रोजन तकनीक तथा स्मार्ट ग्रिड से लेकर मजबूत बुनियादी ढांचे तक कई क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात का वैश्विक केंद्र बनने की भारत की पहल अपार संभावनाएं रखती है। यह इटली की नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना में उन्नत तकनीक और यूरोप के लिए ऊर्जा प्रवेश द्वार के रूप में उसकी रणनीतिक भूमिका के साथ पूरी तरह मेल खाती है। इस संदर्भ में भारत की अगुआई वाली प्रमुख पहलों- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन और 'ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस' में अन्य देशों के साथ हमारा सहयोग बेहद महत्त्वपूर्ण है। भारत और इटली दोनों वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों- हिंद-प्रशांत और भूमध्यसागर के केंद्र में स्थित हैं। अब इन क्षेत्रों को अलग-अलग नहीं, बल्कि आपस में जुड़े हुए क्षेत्रों के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, हम एक नए 'भारत-भूमध्यसागरीय' क्षेत्र को उभरते हुए देख रहे हैं, जो व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, डेटा और विचारों का एक महत्त्वपूर्ण गलियारा बन रहा है।

इस क्षेत्र में हमारा संबंध एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित होता है- ऐसी साझेदारी, जो दो महाद्वीपों को जोड़ती है और नई वैश्विक परिस्थितियों को आकार देती है। हम अपनी साझा चुनौतियों का समाधान दोनों देशों के गहरे संबंधों और लंबे सांस्कृतिक जुड़ाव के आधार पर कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में 'धर्म' का विचार उस जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है, जिसे हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। वहीं 'वसुधैव कुटुंबकम' अर्थात 'पूरी दुनिया एक परिवार है' का सिद्धांत आज के आपस में जुड़े डिजिटल युग में और भी अधिक प्रासंगिक लगता है। ये मूल्य इटली की मानवतावादी परंपरा से भी मेल खाते हैं, जिसकी जड़ें पुनर्जागरण काल में हैं। यह परंपरा हर व्यक्ति की गरिमा और संस्कृति की उस शक्ति पर जोर देती है, जो समाजों और लोगों को एकजुट कर सकती है। इसलिए हमारी साझा दृष्टि का उद्देश्य लोगों को केंद्र में रखते हुए भारत-इटली साझेदारी को मजबूत, आधुनिक और भविष्य उन्मुख आधार प्रदान करना है।

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री तथा इटली गणराज्य मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष हैं।)

श्रम की गरिमा

रितुप्रिया शर्मा

श्रम का भले ही कोई भी रूप हो, यह वाकई सम्मानजनक है। टालस्टाय ने भी अपनी प्रसिद्ध रचना 'वाट डैन मस्ट वी डू' में समाज के ढांचे में मौजूद आर्थिक असमानता और शोषण की तीखी आलोचना की है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति बिना श्रम के दूसरों के श्रम पर निर्भर रहता है, वह नैतिक रूप से कमजोर होता है। टालस्टाय के विचार श्रम की महिमा को और बढ़ाते हैं। मगर इस आधुनिक युग में लोग श्रम को अधिक महत्त्व न देते हुए व्यक्ति के भौतिक रूप से सफल होने को ज्यादा महत्त्व देते हैं। जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करके पैसा कमा रहा है, उसके प्रति समाज की मानसिकता यही होती है कि वह एक साधारण आदमी है। आमतौर पर उसके श्रम को सम्मानजनक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। जबकि ऐसे लगभग सभी काम या काम की श्रेणी ऐसी है, जिसके बिना समाज का काम न चले। सवाल है कि जिस काम के बिना हमारा जीवन सहज न रह पाए या कई मुश्किलें सामने खड़ी हो जाएं, उन कार्यों का सम्मान न करना क्या हमारी संवेदनशीलता को कठघरे में खड़ा नहीं करता।

समाज के लिए सभी कार्य आवश्यक रूप से जरूरी हैं, चाहे वह सफाईकर्मी का कार्य हो या फिर खेत में अनाज उगाना, विद्यालय में पढ़ाना हो या समाज सेवा करना। प्रत्येक कार्य का अपना एक समान महत्त्व है और उसे उच्च और निम्न दृष्टि से देखना उचित नहीं है। आज तकनीक ने जीवन को बहुत ही सहज बना दिया है और इसी वजह से मनुष्य का श्रम से दूर होना स्वाभाविक है। अब लोग अधिक मेहनत करने से बचने लगे हैं। श्रम और श्रमिक के प्रति जो आदर भाव था, वह समाज में कहीं खो गया है।

लोग सब कुछ पा लेने की होड़ में लगे हैं और सब कुछ पाने के लिए ही श्रम करना चाहते हैं। समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करना अब उन्हें बेकार लगने लगा है। मानव सभ्यता के विकास में श्रम का इतिहास छिपा है और जिस मानव सभ्यता को आज इस विकसित रूप में हम देख रहे हैं, वह इसी श्रम की महिमा है। श्रम में ही समाज की आर्थिक प्रगति छिपी है। अगर एक शिक्षक परिश्रम करके बच्चों को न पढ़ाए, तो क्या विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है? एक चिकित्सक अगर रोगियों की सेवा न करे, तो क्या रोगी अपनी बीमारी से निजात पा सकता है?

सभी कार्यों के पीछे श्रम ही निहित है, जो हमें न केवल आत्मनिर्भरता प्रदान करता है, बल्कि जीवन के गतिमान होने का द्योतक भी है। श्रम को सिर्फ जीविका अर्जित करने का माध्यम समझना श्रम की गरिमा को कम करना है। समाज में किसी भी व्यक्ति का श्रम ज्यादा या कम नहीं होता, बल्कि छोटे से छोटा कार्य करने वाले व्यक्ति का भी श्रम उसी व्यक्ति के श्रम की तरह उपयोगी होता है, जो कथित तौर पर बड़े रूप में कार्य कर रहा है। किसी को कमतर करके आंकना श्रम के महत्त्व को उपेक्षित करने के बराबर है। महात्मा गांधी का भी मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिए। गांधी चरखा कातने को केवल स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक नहीं मानते थे, बल्कि इसे वे श्रम की प्रतिष्ठा को जोड़ते थे। उनका यही मानना था कि सभी कार्य समान रूप से सम्माननीय होते हैं, चाहे वह खेती करना हो, सफाई करना हो या फिर कपड़े बुनना। सभी विचारक यह मानते हैं कि श्रम करने में कोई बुराई नहीं है।

श्रम करना एक सम्माननीय कार्य है और इसी नाते हमें श्रमिकों का बहुत सम्मान करना चाहिए। श्रम व्यक्ति को मेहनती बनाता है और उसे अनुशासन की सीख देता है। वास्तविक जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है, जो कि अपने संघर्षों के दौरान श्रम करना सीखता है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक, नेताओं और कलाकारों की सफलता के पीछे उनका कठोर परिश्रम छिपा है। आज का युग थोड़ा अलग हो गया है। मशीनों ने श्रम का स्थान ले लिया है। श्रम के स्वरूप में भी बदलाव आया है। इन सब विकसित मशीनों के कारण यह अंतिम तौर पर नहीं माना जा सकता है कि श्रम का महत्त्व कम हो गया है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मनुष्य का स्थान लिया है या ले रही है, लेकिन मनुष्य जैसी सृजनात्मक सोच, काम से जुड़ाव और मानवीय मूल्यों को कार्य के साथ जोड़ना मशीन का कार्य नहीं है, बल्कि यह अंतिम तौर पर मनुष्य का ही कार्य हैं। आज बुद्धिमत्ता ने भले ही काम की गति को बढ़ा दिया है, लेकिन यह तकनीक मनुष्य के समान भाव में कार्य करना कभी भी नहीं सीख सकती, क्योंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है और उसकी संवेदनशीलता, कुशलता और सृजनात्मकता का अपना मूल्य है।

इसलिए हमें चाहिए कि हम श्रम और श्रमिक दोनों का सम्मान करें। मनुष्य मशीनों पर अपनी निर्भरता को कम करे, श्रम को मानव विकास का साधन समझे और परिश्रमी बने। श्रम ही मानव जीवन और मानव के कल्याण का एक रास्ता है, जिसे हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब हम श्रम और श्रमिकों के प्रति सच्ची भावना रखेंगे। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम परिश्रम करें और अपने बच्चों को भी परिश्रमी ही बनाना सिखाएं। जो देश परिश्रम करना जानते हैं, वही मानव सभ्यता में आगे बढ़ सके हैं और उन्होंने ही विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आए, तो हम सभी नागरिकों को परिश्रम करना सीखना होगा और श्रम की महिमा को जरूरी महत्त्व देना होगा।

दुनिया मेरे आगे

> **यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि श्रम को सिर्फ जीविका अर्जित करने का माध्यम समझना उसकी गरिमा को कम करना है। छोटे से छोटा कार्य करने वाले व्यक्ति का श्रम भी उसी व्यक्ति के श्रम की तरह उपयोगी होता है, जो कथित तौर पर बड़े रूप में कार्य कर रहा है। किसी को कमतर करके आंकना श्रम के महत्त्व को उपेक्षित करने के बराबर है।**

शुचिता पर सवाल

परीक्षाओं की गोपनीयता दम तोड़ रही है। इसकी शुचिता पर सवाल उठ रहे हैं। विद्यार्थी सफलता की उम्मीद लगा कर परीक्षाओं में शामिल होते हैं, लेकिन व्यवस्था की नाकामी और सुरक्षा में लापरवाही के कारण पेपर लीक होने की घटनाएं सुर्खियों में होती हैं। एनटीए ने पिछले दिनों नीट-यूजी 2026 के परचे लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी थी। नतीजा लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत पर पानी फिर गया। सवाल है कि यह व्यवस्था किस कदर लकवाग्रस्त है? अब दोबारा परीक्षा पर कई करोड़ खर्च होंगे। इसमें प्रश्नपत्रों की छपाई, सुरक्षित परिवहन, परीक्षा केंद्रों का किराया और कर्मियों का मानदेय इत्यादि शामिल होगा। मगर उन बच्चों का क्या, जो अपनी सफलता की राह देख रहे थे? अब धन और समय दोनों की फिर बर्बादी होगी। दोबारा परीक्षा से युवाओं पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। आवास और कोचिंग पर होने वाला खर्च भी दबाव बढ़ाता है। कुछ भी हो यह घोर लापरवाही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

– योगेश जोशी, बड़वाह

आत्मनिर्भरता का पैमाना

आज देश में महंगाई पिछले करीब साढ़े तीन साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि दुनिया भर में चल रहे युद्धों का असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हम खुद को आत्मनिर्भर और 'विश्वगुरु' कहते हैं, तो फिर मध्य पूर्व में हो रहे युद्ध का असर सीधे हमारे घरों के चूल्हे और थाली तक क्यों पहुंच रहा है? आत्मनिर्भरता का मतलब केवल बड़े-बड़े भाषण देना नहीं होता, बल्कि ऐसी मजबूत व्यवस्था बनाना होता है, जिससे वैश्विक संकट का असर आम जनता पर कम पड़े। चीन और जापान जैसे देशों पर भी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वहां इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है।

– मोहम्मद नैयर आजम, सीतामढ़ी

सामाजिक सहभागिता

देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर भ्रम एवं चिंता का वातावरण बन रहा है, जबकि ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह संयम और समझदारी का परिचय दे। वर्तमान परिस्थितियों में निजी वाहनों की अपेक्षा सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्राथमिकता देना समय की मांग है। बस, ट्रेन, मेट्रो और साझा आटो जैसे साधनों का अधिक उपयोग न केवल ईंधन की बचत करेगा, बल्कि यातायात और प्रदूषण की समस्या को भी कम करेगा। जिन लोगों के पास निजी वाहन हैं, वे अपने पड़ोसियों, सहकर्मियों या परिचितों के साथ वाहन साझा करने की पहल करें। कठिन समय में सामूहिक जिम्मेदारी और सामाजिक सहभागिता ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। अधिक ईंधन जमा करने की प्रवृत्ति स्थिति को और गंभीर बना सकती है। अगर हर नागरिक सहयोग करें, तो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है।

– वरुण कुमार, जमशेदपुर

उर्वरक का संकट

होर्मुज जलमार्ग बाधित होने से रसायनिक उर्वरक की कमी महसूस की जा रही है। इसलिए राज्य सरकारों को धान की फसल उगाने के लिए यूरिया के विकल्प के तौर पर अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है, जिसमें 21 फीसद नाइट्रोजन और 24 फीसद सल्फर होता है। जबकि धान की प्रति एकड़ अच्छी पैदावार के लिए लगभग साठ किलो शुद्ध नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जो 46 फीसद वाले 130 किलो यूरिया से पूरी होती है। जबकि साठ किलो शुद्ध नाइट्रोजन के लिए 300 किलो अमोनियम सल्फेट प्रति एकड़ की जरूरत होगी, जिससे नाइट्रोजन के साथ 72 किलो सल्फर प्रति एकड भूमि को मिलेगा। इसलिए केंद्र सरकार को धान में यूरिया के विकल्प के तौर पर अमोनियम सल्फेट को उपयोग करने की सलाह पर पुनर्विचार करना चाहिए।

– वीरेंद्र सिंह लाठर, नई दिल्ली

तथ्य

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की हालिया रिपोर्ट में देश में युवा बेरोजगारी को लेकर चिंता बढ़ी है। 15-29 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर बढ़कर करीब 15% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में बेरोजगारी दर पुरुषों की तुलना में अधिक दर्ज की गई। रिपोर्ट में शहरों में युवाओं की बेरोजगारी गांवों की तुलना में अधिक पाई गई। बताया गया कि स्नातक और डिप्लोमा धारक युवाओं को नौकरी पाने में ज्यादा कठिनाई हो रही है। महिलाओं की कामकाजी भागीदारी बढ़ी है, लेकिन स्थायी रोजगार अभी भी कम हैं। बड़ी संख्या में युवा अस्थायी और असंगठित क्षेत्र के कामों पर निर्भर हैं।

डीयू में पीजी दाखिले शुरू, सात जून तक करें आवेदन

दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय के करीब 82 पीजी पाठ्यक्रमों की 13 हजार से अधिक सीटों पर प्रवेश लिए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 7 जून रात 11:59 बजे तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दाखिले सीयूईटी पीजी-2026 के अंकों के आधार पर कामन सीट एलोकेशन सिस्टम (सीएसएएस) के जरिए होंगे। इस वर्ष नई शिक्षा नीति के तहत एक वर्षीय और दो वर्षीय दोनों पीजी कार्यक्रम संचालित होंगे, हालांकि फिलहाल दो वर्षीय कोर्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 250 रुपए तथा एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 100 रुपए तय किया गया है।

सूचनापट्ट

एबीवीएमयू जीएनएम

अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय (एबीवीएमयू), लखनऊ द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश सामान्य नर्सिंग एवं प्रसूति विद्या प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन 29 अप्रैल से 26 मई 2026 तक किए जाएंगे। इस परीक्षा के माध्यम से सरकारी और निजी नर्सिंग संस्थानों में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी की आयु 31 दिसंबर 2026 तक कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक भारतीय नागरिक तथा शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना आवश्यक है। सरकारी सीटों के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना या 10वीं और 12वीं की पढ़ाई राज्य से पूरी होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता में 10 2 उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें अंग्रेजी विषय शामिल हो तथा न्यूनतम 40 फीसद अंक आवश्यक हैं, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को 5 फीसद की छूट दी गई है। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे।

अंतिम तिथि : 26 मई, 2026

डीआरडीओ

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अंतिम वर्ष के यूजी और पीजी छात्रों के लिए पेड इंटर्नशिप की घोषणा की है। यह इंटर्नशिप बंगलुरु स्थित डिफेंस बायोइंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी में आयोजित होगी। इंजीनियरिंग और विज्ञान वर्ग के वे छात्र आवेदन कर सकते हैं, जो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अंतिम वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। प्रशिक्षण की अवधि छह महीने होगी और चयनित छात्रों को रक्षा अनुसंधान तथा बायोमेडिकल तकनीक से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा। यह पूरी तरह आफलाइन इंटर्नशिप होगी, जिसमें छात्रों की नियमित उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। संस्था के अनुसार बायोमेट्रिक उपस्थिति भी लागू होगी। इंटर्नशिप के दौरान कुल 30 हजार रुपए स्टाइपेंड दिया जाएगा। पहले तीन महीने पूरे होने पर 15 हजार रुपए और छह महीने पूरे करने पर अतिरिक्त 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। तीन महीने से पहले इंटर्नशिप छोड़ने पर कोई स्टाइपेंड या प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया 12 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है। संभावित रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूचना 18 जून को जारी होगी, जबकि इंटर्नशिप एक जुलाई 2026 से शुरू हो सकती है।

अंतिम तिथि : 31 मई, 2026

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा पीजीएटी 2026-27 के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 मई 2026 से शुरू हो चुकी है, जो 25 मई 2026 तक चलेगी। आवेदन शुल्क भी 25 मई 2026 तक आनलाइन जमा किया जा सकता है। पीजीएटी प्रथम पाठ्यक्रमों में एलएलबी, एमकाम और एलएलएम शामिल हैं, जिनकी कुल 4203 सीटें विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग हेतु आवेदन शुल्क 1000 रुपए तथा एससी/एसटी वर्ग हेतु 500 रुपए निर्धारित है। पीजीएटी द्वितीय में बीएड, एमएड, एमबीए (आरडी) सहित अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे एमसीए, एमएससी फूड टेक्नोलाजी, एमवाक मीडिया स्टडीज एवं पीजीडीसीए शामिल हैं, जिनकी कुल 5264 सीटें संबद्ध महाविद्यालयों में उपलब्ध हैं। इनके लिए सामान्य वर्ग हेतु 1600 रुपयेएतथा एससी/एसटी वर्ग हेतु 800 रुपए शुल्क निर्धारित है।

अंतिम तिथि : 25 मई, 2026

रेलवे

रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 14 जून 2026 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 11,127 रिक्त पद भरे जाएंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 जून तय की गई है, जबकि आवेदन में संशोधन के लिए 17 जून से 26 जून 2026 तक सुधार विंडो खुली रहेगी। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपए रखा गया है। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 250 रुपए शुल्क देना होगा। भर्ती प्रक्रिया में पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-1) होगी, इसके बाद सीबीटी-2 आयोजित की जाएगी। सफल अभ्यर्थियों को योग्यता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सीय परीक्षण से गुजरना होगा। रिक्तियों में 4860 पद अनारक्षित, 2598 ओबीसी, 1746 एससी, 919 एसटी और 1004 ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए निर्धारित हैं।

अंतिम तिथि : 14 जून, 2026

आपूर्ति शृंखला और माल परिवहन

बदलती अर्थव्यवस्था में अवसरों का नया केंद्र

विशेषज्ञ की कलम से

आज का दौर तेजी, सुविधा और तकनीक का दौर है। लोग घर बैठे सामान मंगाना चाहते हैं और कंपनियां चाहती हैं कि हर वस्तु सही समय पर ग्राहक तक पहुंचे। यही कारण है कि आपूर्ति शृंखला और माल परिवहन का क्षेत्र तेजी से देश की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। भारत जिस गति से विनिर्माण और व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा आधार बनने वाला है।

जब कोई वस्तु कारखाने में तैयार होती है, तब उसे ग्राहक तक पहुंचाने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। कच्चे माल की खरीद, भंडारण, पैकिंग, परिवहन और समय पर वितरण, इन सभी कार्यों को मिलाकर सप्लाई शृंखला कहा जाता है। वहीं माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित और समय पर पहुंचाने की व्यवस्था माल परिवहन कहलाती है। आज यह व्यवस्था केवल ट्रकों और गोदामों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें आधुनिक तकनीक, आंकड़ों का विश्लेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई व्यवस्थाएं भी जुड़ चुकी हैं।

> बारहवीं के बाद डिप्लोमा या प्रबंधन से जुड़े पाठ्यक्रम कर सकते हैं। स्नातक के बाद विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और उच्च अध्ययन के अवसर भी उपलब्ध हैं।

भारत सरकार की 'पीएम गति शक्ति' योजना और राष्ट्रीय माल परिवहन नीति ने इस क्षेत्र को नई दिशा दी है। देश में सड़क, रेल, जल और हवाई मार्गों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे व्यापार और परिवहन की गति तेज हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ वर्षों में भारत का माल परिवहन बाजार दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में शामिल हो सकता है। इसका सीधा लाभ युवाओं को रोजगार और बेहतर वेतन के रूप में मिलेगा।

इस क्षेत्र में काम के कई अलग-अलग हिस्से होते हैं। सही मूल्य पर सामान खरीदना, गोदाम में वस्तुओं का हिसाब रखना, समय पर वितरण सुनिश्चित करना और परिवहन व्यवस्था को नियंत्रित करना सभी जिम्मेदारियां अलग-अलग पदों पर निभाई जाती हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधकीय दोनों प्रकार के युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। बारहवीं के बाद विद्यार्थी इस क्षेत्र में डिप्लोमा या प्रबंधन से जुड़े पाठ्यक्रम कर सकते हैं।

स्नातक के बाद विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और उच्च अध्ययन के अवसर भी उपलब्ध हैं। देश के कई बड़े संस्थान अब सप्लाई शृंखला और माल परिवहन प्रबंधन से जुड़े विशेष पाठ्यक्रम चला रहे हैं। सरकार द्वारा स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

अविनाश चंद्रा, *करिअर परामर्शदाता*

विशेष कौशल भी जरूरी

सिर्फ डिग्री ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष कौशल भी इस क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं। आंकड़ों को समझने की क्षमता, कंप्यूटर आधारित प्रणालियों की जानकारी, समस्या आने पर तुरंत निर्णय लेने की योग्यता और बेहतर संवाद शैली आज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। आने वाले समय में ड्रोन, स्वचालित मशीनें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस क्षेत्र को और अधिक आधुनिक बनाने वाली हैं।

वेतन

वेतन की बात करें तो शुरुआती स्तर पर भी युवाओं को अच्छे अवसर मिल रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सप्लाई शृंखला विश्लेषक को शुरुआती दौर में सालाना साढ़े तीन लाख से छह लाख रुपये तक वेतन मिल सकता है, जो पांच से सात वर्ष के अनुभव के बाद 12 से 18 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। वहीं माल परिवहन प्रबंधक को शुरुआती स्तर पर चार से आठ लाख रुपये और अनुभव के बाद 15 से 25 लाख रुपए तक वार्षिक वेतन मिल रहा है।

जानें-सीखें

अब आधे घंटे पहले बदलें स्टेशन

भारतीय रेलवे को देश की जीवनरेखा कहा जाता है। हर दिन करोड़ों लोग रेल यात्रा के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। यात्रा के दौरान कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, जब यात्री को अचानक अपना चढ़ने वाला स्टेशन बदलने की जरूरत पड़ती है। पहले यह काम काफी मुश्किल माना जाता था, क्योंकि रेलवे के पुराने नियम के अनुसार यात्रियों को ट्रेन छूटने से चार घंटे पहले तक ही बोर्डिंग स्टेशन बदलने की अनुमति थी। लेकिन अब रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए इस नियम में अहम बदलाव किया है।

रेलवे द्वारा 1 अप्रैल 2026 से लागू किए गए नए नियम के तहत यात्री अब ट्रेन के निर्धारित समय से केवल 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग प्वाइंट बदल सकते हैं। नियम लागू हुए एक महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज भी अधिकांश यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं है। यही कारण है कि कई लोग अंतिम समय में स्टेशन बदलने की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते।

इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा, जिनकी यात्रा योजना अचानक बदल जाती है। कई बार जाम, कार्यालय के काम, पारिवारिक कारण या किसी अन्य परेशानी के कारण यात्री अपने मूल स्टेशन तक समय पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे में अब वे रास्ते में पड़ने वाले दूसरे स्टेशन को अपना नया बोर्डिंग प्वाइंट बना सकते हैं। इससे टिकट रद्द कराने या सीट छूटने की परेशानी नहीं होगी।

यात्री यह सुविधा रेलवे की आनलाइन सेवा के जरिए भी आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए आइआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल अनुप्रयोग पर जाकर 'बुक टिकट हिस्ट्री' में बदलाव करना होता है। काउंटर टिकट वाले यात्री नजदीकी आरक्षण केंद्र में लिखित आवेदन देकर भी स्टेशन बदलवा सकते हैं। रेलवे के अनुसार, बदलाव के बाद सीट सुरक्षित रहती है और टीटीई उसे किसी दूसरे यात्री को आवंटित नहीं कर सकता।

हालांकि इस सुविधा के साथ कुछ जरूरी शर्तें भी जुड़ी हैं। यात्री केवल एक बार ही बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इसके अलावा यदि नया स्टेशन मूल स्टेशन से आगे का है, तो किराए का अंतर वापस नहीं मिलेगा। एक बार बदलाव के बाद पुराने स्टेशन से यात्रा करना भी मान्य नहीं होगा।

यात्रियों के लिए जरूरी बातें

- ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बदल सकते हैं स्टेशन
- आनलाइन और आफलाइन दोनों माध्यमों से सुविधा उपलब्ध
- सीट पूरी तरह सुरक्षित रहेगी
- बोर्डिंग प्वाइंट केवल एक बार बदला जा सकता है
- बदलाव के बाद नया टिकट या संदेश सुरक्षित रखें

युवा शक्ति डेस्क

निगरानी

बीकानेर में एक केंद्र पर बुधवार को स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले सुरक्षा जांच कराते अभ्यर्थी।

गर्मी की छुट्टियां : सीखने, निखरने व आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर

परामर्श

गर्मी की छुट्टियां केवल आराम और मनोरंजन का समय नहीं होतीं, बल्कि यह स्वयं को बेहतर बनाने और नई क्षमताएं विकसित करने का सुनहरा अवसर भी होती हैं। अक्सर विद्यार्थी छुट्टियों में अपना अधिकांश समय मोबाइल, दूरदर्शन और बिना योजना के इधर-उधर बिताने में गंवा देते हैं। यदि यही समय सही दिशा में लगाया जाए, तो यह भविष्य को मजबूत बनाने में बहुत सहायक साबित हो सकता है।

छुट्टियों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस दौरान समय का दबाव कम होता है। विद्यार्थी अपनी रुचियों और शौकों को पूरा करने के लिए खुलकर समय निकाल सकते हैं। कोई संगीत सीख सकता है, चित्रकला में हाथ आजमा सकता है, नई भाषा सीख सकता है या लेखन की शुरुआत कर सकता है। नई चीजें सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्तित्व में निखार आता है। यही छोटी-छोटी सीख आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनती हैं। यात्राएं भी सीखने का महत्त्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों और स्मारकों की सैर करने से इतिहास और संस्कृति को करीब से समझने का अवसर मिलता है। नई जगहों के रहन-सहन, खान-पान और परंपराओं को जानकर युवाओं का दृष्टिकोण व्यापक होता है और उनमें विविधता के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। इसके साथ ही छुट्टियों में स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। खेलकूद, योग, तैराकी और साइकिल चलाने जैसी गतिविधियां शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखती हैं। रोज कुछ समय डायरी लिखने या पुस्तक पढ़ने में बिताना भी लाभकारी होता है। अच्छी किताबें ज्ञान बढ़ाने के साथ सोचने और समझने की क्षमता को मजबूत करती हैं।

सीबीएसई : असंतुष्ट विद्यार्थियों को दोबारा जांच का अवसर

जरूरी जानकारी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा 2026 का परिणाम जारी होने के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपने अंकों को लेकर असंतोष जताया है। विशेष रूप से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित जैसे विषयों में अपेक्षा से कम अंक मिलने की शिकायतें सामने आई हैं। इसे देखते हुए बोर्ड ने विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच और पुनर्मूल्यांकन का अवसर देने की घोषणा की है। बोर्ड ने बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए इस बार आन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की गई, जिससे गोपनीयता और सटीकता सुनिश्चित हो सके।

बोर्ड के अनुसार, जिन विद्यार्थियों को अपने अंकों पर संदेह है, वे पहले चरण में अपनी जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए आवेदन 19 मई से 22 मई 2026 तक किए जा सकेंगे। सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब किसी छात्र से उत्तर पुस्तिका देखने के लिए 100 रुपए शुल्क लिया जाएगा, उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन के लिए 100 रुपए और किसी विशेष प्रश्न के उत्तर की पुनः जांच के लिए 25 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच प्रक्रिया में छात्र के अंक बढ़ते हैं या संशोधित होते हैं, तो उससे लिया गया पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

> पुनर्मूल्यांकन के बाद जारी परिणाम ही अंतिम माना जाएगा। अंक बढ़ने या घटने दोनों स्थितियों में संशोधित अंकपत्र जारी होगा।

इस प्रक्रिया के पहले चरण में प्रति विषय उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई कापी प्राप्त करने के लिए 700 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में त्रुटि सत्यापन के लिए 500 रुपए प्रति उत्तर पुस्तिका और पुनर्मूल्यांकन के लिए 100 रुपए प्रति प्रश्न शुल्क निर्धारित किया गया था।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी आवेदन केवल आनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अधूरे अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद भेजे गए आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन के बाद जारी परिणाम ही अंतिम माना जाएगा। अंक बढ़ने या घटने दोनों स्थितियों में संशोधित अंकपत्र जारी होगा। बोर्ड ने कहा कि निष्पक्ष और त्रुटिरहित मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है।

डीटीयू में बीए, एमए व एमबीए के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बीए (आनर्स) अर्थशास्त्र, एमए अर्थशास्त्र और एमबीए एग्जीक्यूटिव कार्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीए (आनर्स) इकोनामिक्स कार्यक्रम में कुल 182 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें 85 फीसद सीटें दिल्ली के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 13 जुलाई तय की गई है।

पहले चरण की काउंसलिंग सूची 16 जुलाई को जारी होगी, जबकि काउंसलिंग प्रक्रिया 24 जुलाई से शुरू होगी। दूसरे चरण की घोषणा चार अगस्त को होगी और इसकी काउंसलिंग 11 अगस्त से शुरू होगी। स्पाट राउंड भी 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। स्पेशल स्पाट राउंड की घोषणा बाद में की जाएगी। इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए अभ्यर्थियों के पास सीयूईटी यूजी-2026 का वैध स्कोरकार्ड होना जरूरी है। एमए इकोनामिक्स कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून निर्धारित की गई है। पहले चरण की काउंसलिंग की घोषणा 30 जून को होगी और प्रक्रिया सात जुलाई से शुरू होगी। दूसरे चरण और स्पाट राउंड की घोषणा 17 जुलाई को होगी काउंसलिंग 28 जुलाई से शुरू होगी। विवि में एमबीए एग्जीक्यूटिव कार्यक्रम के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार 15 जून तक आवेदन कर सकेंगे।

Your Time Is Most Valuable Thing
I will not let you down 🙏

I GIVE YOU MY GUARANTEE, THIS CHANNEL IS WORTH IT.

📚Indian Newspapers:

1) Times of India
2) Hindustan Times
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) The Hindu
7) Live Mint
8) Financial Express
9) Business standard
+All Editorial PDFs

Upload Starts From 5AM

🎈Access to all this In Private channel [lifetime Access]

Click below to

Join

📚International Newspapers Channel

📚 Magazine Channel (National & International)